

## 2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति: एक वृहद दृष्टिकोण

பருவத்தோ டொட்ட வெழுக்கல் திருவினைத்  
தீராமையாக்குங் கயிறு

“सही समय पर सही काम करना ऐसी आदत है जिससे व्यक्ति  
जीवन में असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है।”

-तिरूकुरल, अध्याय-49, श्लोक 482

नोवल कोविड-19 वायरस ने वर्ष 2020 में दुनिया को अव्यवस्था में डालकर सभी के लिए भय का माहौल सृजित करके उनके आवागमन, सुरक्षा और सामान्य जीवन को प्रभावित किया। इसने, भारत और दुनिया के लिए एक सदी में सबसे विकट आर्थिक चुनौती पेश की। इलाज या वैक्सिन के बिना, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति इस व्यापक संकट से निपटने के लिए केंद्रीय बन गई। रोग के वक्र को समतल करने की अनिवार्यता को आसन्न मंदी की आजीविका लागत के साथ जोड़ा गया था, जो महामारी को रोकने के लिए आवश्यक लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंधों से निकला था। इस अंतर्निहित व्यापार-बंद ने 'जीवन बनाम आजीविका' की नीति दुविधा को जन्म दिया।

दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए नीतिगत उपकरणों की एक श्रृंखला तैनात की जैसे कि प्रमुख नीतिगत दरों को कम करना, मात्रात्मक सहजता के उपाय, ऋण की गारंटी, नकद हस्तांतरण और राजकोषीय प्रोत्साहन के उपाय। भारत ने महामारी के विघटनकारी प्रभाव को पहचान लिया और देश में प्रसार के कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अपनी विशाल पथ, उच्च जनसंख्या घनत्व और स्वास्थ्य अवसंरचना पर अत्यधिक भार को देखते हुए अपने स्वयं के अनूठे पथ के अनुमानों के चार्ट बनाए।

जैसा कि खंड 1 के अध्याय 1 में दिखाया गया है, महामारी की शुरुआत में लागू तीव्र लॉकडाउन-जब भारत में केवल 100 पुष्टि की गई मामले थे-कई मायनों में भारत की अनूठी प्रतिक्रिया की विशेषता। सबसे पहले, नीति प्रतिक्रिया महामारी विज्ञान और आर्थिक अनुसंधान दोनों के निष्कर्षों से प्रेरित थी। विशेष रूप से, महामारी के संभावित प्रसार के बारे में भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, नीति ने Hansen और Sargent (2001) के नोबेल-पुरस्कार विजेता अनुसंधान को लागू किया है जो सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने पर केंद्रित नीति की सिफारिश करता है। एक अभूतपूर्व महामारी के साथ सामना, सैकड़ों मानव जीवन की हानि ने इस सबसे खराब स्थिति को पकड़ लिया। इसके अलावा, महामारी विज्ञान अनुसंधान ने एक ऐसे देश में विशेष रूप से एक प्रारंभिक, कड़े लॉकडाउन के

महत्व पर प्रकाश डाला, जहां उच्च जनसंख्या घनत्व ने सामाजिक दूरी के संबंध में कठिनाइयों का सामना किया। इसलिए, भारत की नीति मानवीय प्रतिक्रिया जिसने मानव जीवन को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया, ने स्वीकार किया कि प्रारंभिक, कड़े लॉकडाउन के अल्पकालिक कठिनाई ने बचाये जीवन में और आर्थिक सुधार की गति में दीर्घकालिक लाभ होगा। सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी हैं और वी-आकार की आर्थिक रिकवरी देखी जा रही है-जो प्रारंभिक लॉकडाउन के प्रभाव के कारण है-दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक कठिनाई लेने में भारत के साहस की गवाही है।

दूसरा, भारत ने माना कि महामारी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित करती है। सुधारों का मोड़-सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच फिर से अद्वितीय-यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि लॉक-डाउन के दौरान आपूर्ति-संबंधी व्यवधान, जो अपरिहार्य थे, मध्यम से दीर्घावधि में कम से कम हो। मांग पक्ष की नीति ने इस समझ को प्रतिबिंबित किया कि समग्र मांग, विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए, बचत करने के लिए निवारक उद्देश्यों को दर्शाती है, जो समग्र अनिश्चितता अधिक होने पर अनिवार्य रूप से उच्च रहता है। इसलिए, महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान जब अनिश्चितता अधिक थी और लॉकडाउन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, भारत ने विवेकाधीन खपत को बढ़ाने की कोशिश में कीमती वित्तीय संसाधनों को बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय, नीति ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम शामिल है। भारत सरकार ने भी रोजगार को बनाए रखने और देनदारियों को पूरा करने में मदद करके तनावग्रस्त क्षेत्रों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की।

अनलॉक चरण के दौरान, जब अनिश्चितता में गिरावट आई और एक तरफ सब्सिडी बचत करने के लिए एहतियाती मकसद था, एक ओर आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, दूसरी ओर, भारत ने अपने राजकोषीय खर्च में वृद्धि की। एक अनुकूल मौद्रिक नीति ने मौद्रिक नीति संचरण को करते हुए अस्थायी नैतिकता के माध्यम से देनदारों को प्रचुर मात्रा में तरलता और तत्काल राहत सुनिश्चित की। इस प्रकार, भारत की मांग-पक्ष नीति इस विचार को रेखांकित करती है कि त्वरक पर दबाव डालते समय ब्रेक को दबाया जाता है, जिसमें केवल अपशिष्ट ईंधन होता है।

भारत सितंबर के मध्य में अपने मामले में, महामारी विज्ञान वक्र को समतल करने के लिए प्रबंधन किया दूसरी लहर से बचने में सक्षम रहा है। जैसा कि खंड 1 के अध्याय 1 में दिखाया गया है, प्रारंभिक कठोर लॉकडाउन जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण था और V के आकार की आर्थिक प्राप्ति हुई। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट और भाग्यवादियों ने भारत के आगे और पीछे की नीतिगत प्रतिक्रियाओं के सिंसिफस भाग्य से बच निकलने को जारी रखा, जिससे अर्थव्यवस्था का लगातार अनलॉक हो रहा है। जैसा कि अनुमान था, जबकि लॉकडाउन में Q1 में जीडीपी में 23 प्रतिशत का संकुचन हुआ, रिकवरी में V के आकार का है, जो कि क्यू 2 में 7.5: की गिरावट और सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के रूप में देखा गया है। जुलाई से, एक लचीली V के आकार

की रिकवरी शुरू हो रही है, जैसा कि Q1 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में रिकवरी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, Q1 में तेज गिरावट के बाद, उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे बिजली की मांग, ई-वे बिल, जीएसटी संग्रह, स्टील में निरंतर पुनरुत्थान, खपत, आदि का शासनकाल अंतर्राज्यीय आंदोलन और रिकॉर्ड-उच्च मासिक जीएसटी संग्रह ने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के अनलॉक होने को चिह्नित किया है। वाणिज्यिक पत्र जारी करने में तेज वृद्धि, पैदावार में आसानी, और MSMEs के लिए मजबूत ऋण वृद्धि ने उद्यमों के जीवित रहने और बढ़ने के लिए ऋण प्रवाह में सुधार किया। निर्यात की तुलना में आयात अधिक तेजी से हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार 18 महीने के आयात को कवर करता है। मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रेरित, वर्ष के अधिकांश के लिए 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रही; दिसंबर में नरमी से आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने में आसानी हुई।

वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की कमी का अनुमान है, पहली छमाही में 15.7 प्रतिशत की गिरावट और दूसरी छमाही में मामूली 0.1 प्रतिशत की गिरावट। सेक्टर-वार, कृषि चांदी के अस्तर के रूप में बनी हुई है, जबकि संपर्क-आधारित सेवाएं, विनिर्माण, निर्माण सबसे कठिन थे, और लगातार ठीक हो रहे हैं। सरकारी खपत और शुद्ध निर्यात ने विकास को नीचे गिरा दिया है।

V आकार के आर्थिक सुधार को एक मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ सेवा क्षेत्र में एक मजबूत वसूली की उम्मीद है। साथ में, उपभोग और निवेश में मजबूत वृद्धि की संभावनाओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास के साथ 11 प्रतिशत पर फिर से शुरू किया गया है। भारत की इस संकट के लिए “सदी में एक बार” परिपक्व नीति प्रतिक्रिया इस प्रकार मायोपिक नीति से बचने के लिए लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है और दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के महत्वपूर्ण लाभों को प्रदर्शित करती है।

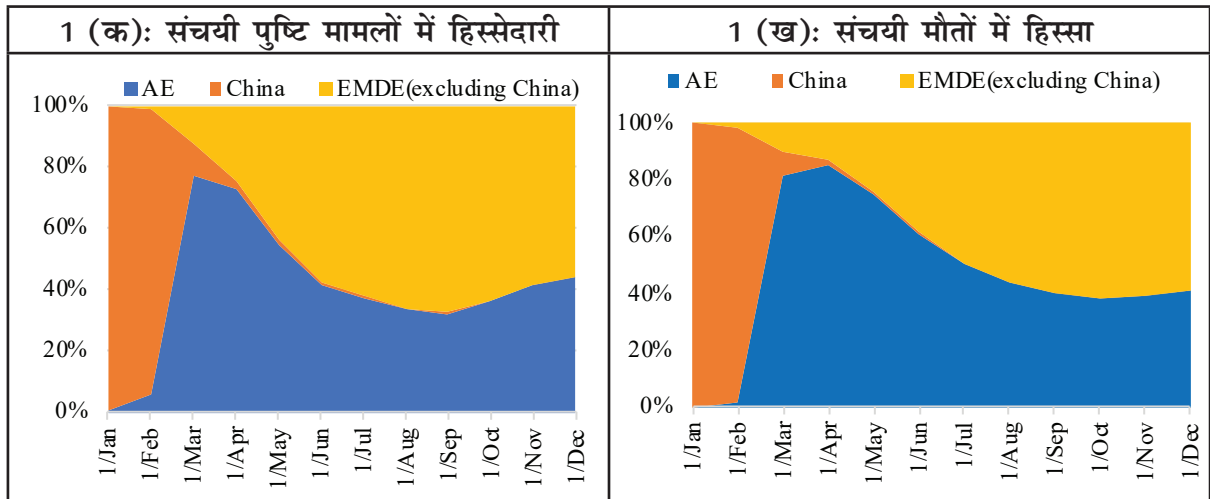
1.1 वर्ष 2020 में नए कोविड-19 वायरस और एक सदी में आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरती हुई महामारी के साथ बेजोड़ उथल-पुथल देखी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 30 जनवरी, 2020 को कोविड-19 को ‘अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल’ (PHEIC) घोषित किया और सलाह दी कि सभी देशों को नियंत्रण के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें सक्रिय निगरानी, शीघ्र पहचान, अलगाव और मामले प्रबंधन, संपर्क अनुरेखण और आगे की प्रसार की रोकथाम शामिल हैं। दैनिक मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि ने WHO को 11 मार्च, 2020 को इस प्रकोप को ‘सर्वव्यापी महामारी’ शीर्षक देने के लिए मजबूर किया - इसके उद्भव के तीन महीने की अवधि के भीतर दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक पुष्ट मामलों और 2 लाख से अधिक मौतों के साथ संसर्ग अभी भी फैल रहा है। आगामी झटके अपने आकार और अनिश्चितता के संदर्भ में बेहद अपरंपरागत रहे हैं, इसके प्रभाव से लॉकडाउन की तीव्रता, आपूर्ति श्रृंखला की सीमा और वित्तीय बाजार में बाधाएं जैसे संबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ अप्रत्याशित प्रभाव पर निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर वर्ग पर इसके व्यापक प्रभावों में महामारी अद्वितीय रही है।

## महामारी का प्रसार

### वैश्विक प्रसार

1.2 वुहान, चीन में इसके पहले प्रकोप के बाद से, कोविड-19 ने अंटार्कटिका (दिसंबर, 2020 में) और 220 से अधिक देशों सहित सभी महाद्वीपों को संक्रमित किया है। स्वास्थ्य का झटका, हालांकि वैश्विक है, कुल संक्रमण, मृत्यु दर और वसूलियों के मामले में देशों में विभिन्न प्रक्षेप पथ के माध्यम से प्रेषित किया गया है। महामारी के प्रारंभिक चरणों में, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (AE) कुल मामलों और कुल मौतों (चित्र 1) के 70 प्रतिशत से अधिक के साथ असंगत रूप से प्रभावित थीं। ब्राजील, भारत, मैक्सिको, रूस और तुर्की जैसे उभरते बाजार और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में भी महामारी तेजी से बढ़ी है, जो अब कुल मामलों और कुल मौतों का लगभग 50 प्रतिशत है। हाल के महीनों में, एक दोहराने की लहर के बीच AEs-विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरो क्षेत्र के देशों ने मामलों की बढ़ती हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है; EMDEs में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्रों में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। यह स्पष्ट है कि महामारी से AEs प्रभावित हुए हैं।

चित्र 1: कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रसार में रुझान

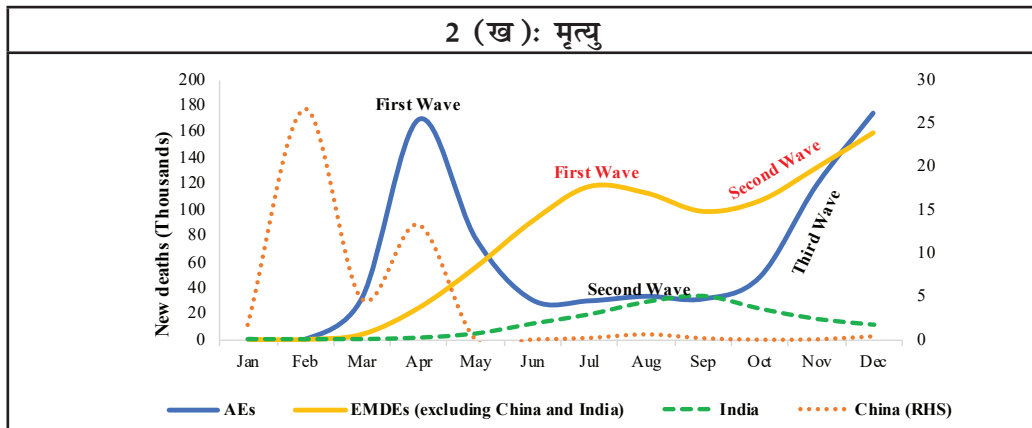
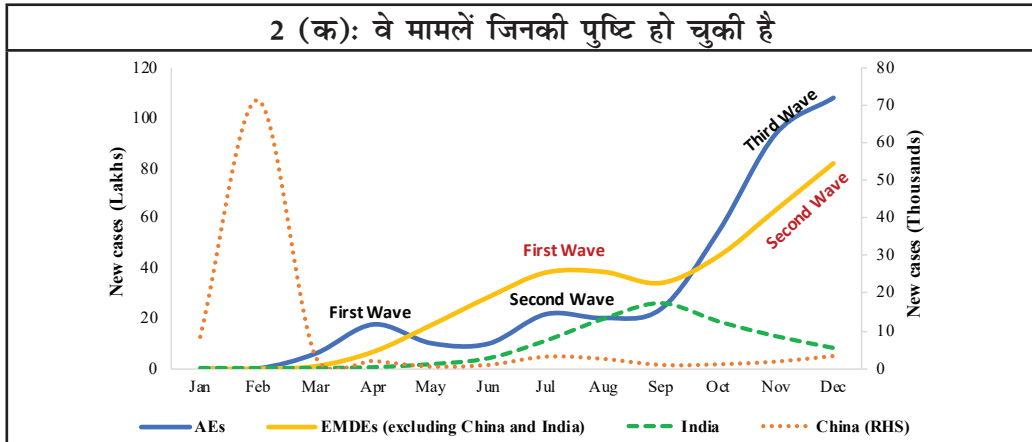


स्रोत: WHO, सर्वेक्षण गणना

1.3 महामारी का प्रसार तरंगों में हुआ है जैसा कि चित्र 2 में स्पष्ट है। AEs अपनी तीसरी तरंगों का अनुभव कर रहे थे, दोनों मामलों और मौतों के मामले में, वर्ष के अंत में जबकि EMDEs (चीन और भारत को छोड़कर) अपनी दूसरी लहरों का सामना कर रहे थे। चीन ने फरवरी, 2020 में मामलों की पहली लहर का अनुभव किया जिसके बाद वह प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ। भारत ने सितंबर, 2020 तक अपनी पहली लहर का अनुभव किया, जिसके बाद वह प्रभावी रूप से प्रसार का प्रबंधन करने में सक्षम हो गया-अब तक दूसरी लहर से बचा है।



चित्र 2: कोविड-19 संक्रमण तरंगें

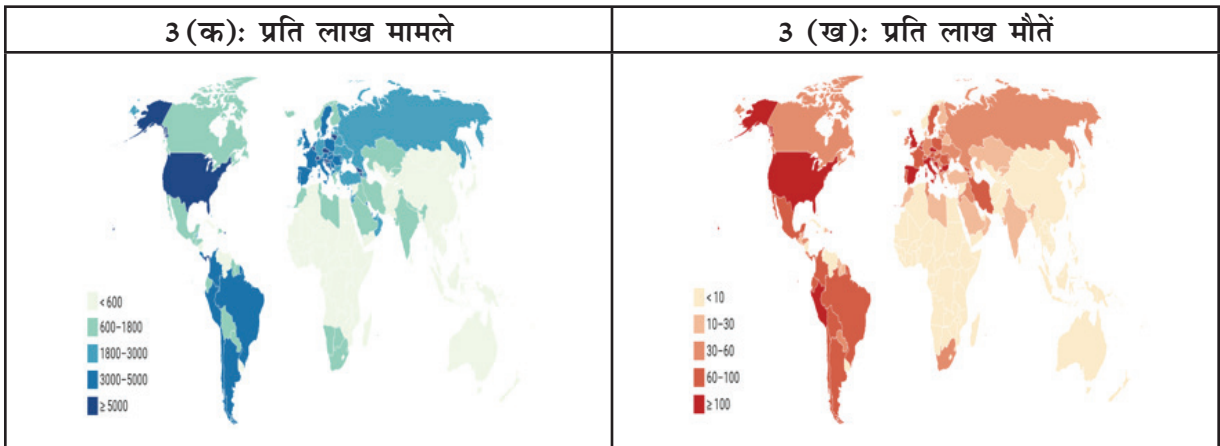


स्रोत: WHO से डेटा का उपयोग करके सर्वेक्षण गणना

नोट: डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक है।

1.4 EMDEs (चित्र 3) की तुलना में AEs प्रति व्यक्ति आधार पर उच्च पुष्टि वाले मामलों और मौतों का गवाह है। AEs में तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में 5.3 गुना से अधिक होने के साथ अधिक घातक साबित हुई है और दिसंबर में ही पहली लहर के दौरान के स्तर को पार कर गई है।

चित्र 3: देशों में प्रति व्यक्ति कोविड-19 केस लोड



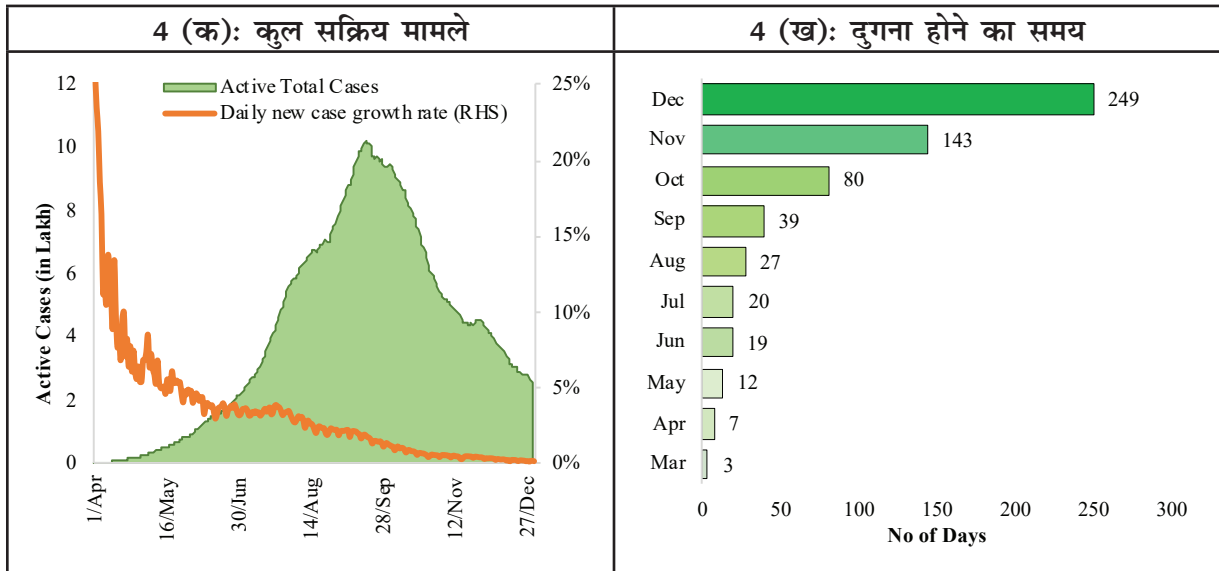
स्रोत: WHO से डेटा का उपयोग करके सर्वेक्षण गणना

नोट: डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक है।

## भारत में महामारी का प्रसार

1.5 भारत ने मार्च-अप्रैल-, 2020 में महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान एक कठोर राष्ट्रव्यापी तालाबंदी लागू की, जिसके बाद क्रमिक उपायों को शामिल किया गया और रोकथाम उपायों को चरणबद्ध किया गया। भारत ने 17 सितंबर, 2020 को 11.12 लाख सक्रिय मामलों के साथ सितंबर के मध्य में अपनी चोटी को पार किया और 16 सितंबर, 2020 (चित्र 4 (क)) पर 97,860 दैनिक नए मामले। इसके बाद, त्योहारी सीजन और सर्दियों के मौसम की शुरुआत के बावजूद जनवरी, 2021 में नए मामले घटकर 16,000 से भी कम हो गए हैं। भारत में पुष्टि किए गए मामलों ने 1.06 करोड़ से अधिक को छू लिया है, जो दुनिया के कुल मामले के लगभग 11 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व स्तर पर नए मामलों में भारत का हिस्सा सितंबर, 2020 में 31 प्रतिशत से घटकर दिसंबर, 2020 में 4 प्रतिशत हो गया है। मई, 2020 में 12 दिनों से दिसंबर, 2020 तक 249 दिनों तक बढ़ रहे मामलों के दोगुने समय के साथ प्रसार की गति को नियंत्रित किया गया है, (चित्र 4 बी)।

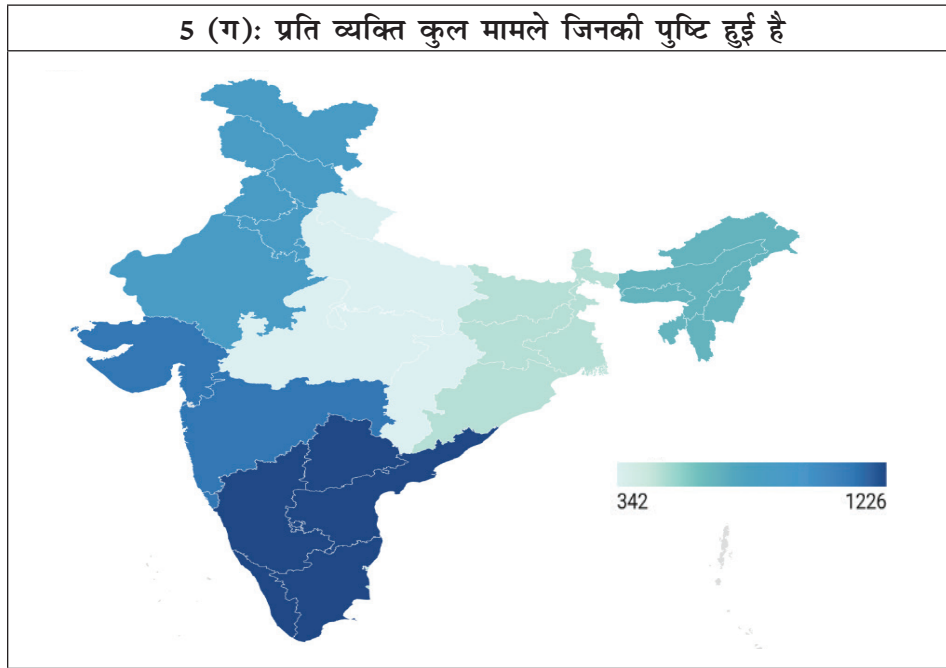
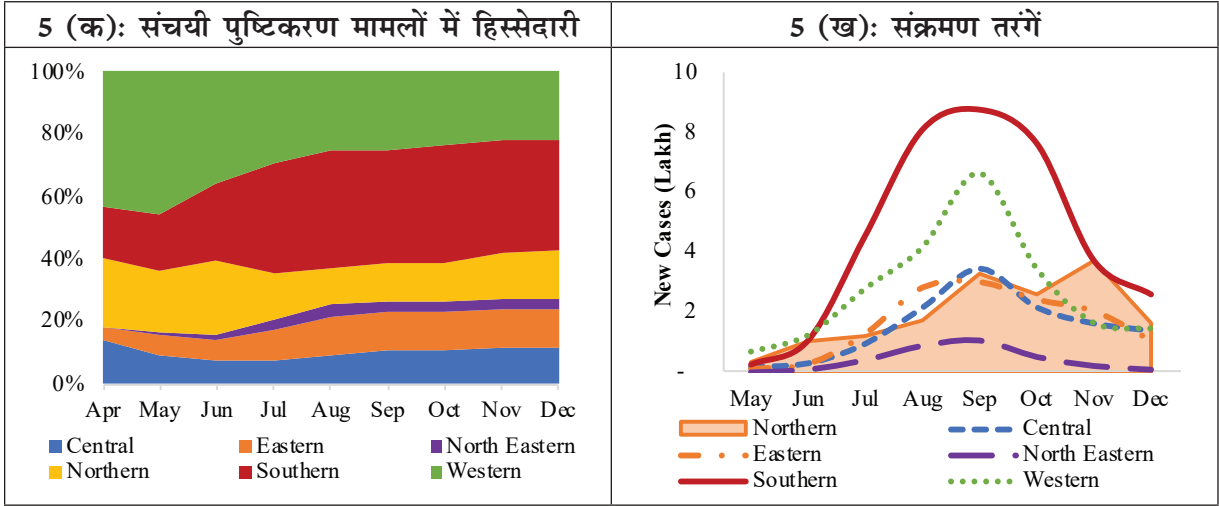
चित्र 4: भारत में कोविड-19 का प्रसार



स्रोत: <https://www.covid19india.org/> ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH & FW) से एक्सेस किया गया डेटा नोट: दुगने होने के दर को  $\ln 2 / \text{सद} (1 + r)$  के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां  $r$  संचयी मामलों में वृद्धि के पिछले सात दिनों का औसत है।

1.6 महामारी का प्रारंभिक प्रसार प्रमुख रूप से देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र तक सीमित था, जिसमें क्रमशः 42 और 22 प्रतिशत का योगदान था (चित्र 5)। दूसरी ओर, जुलाई, 2020 के बाद से दक्षिणी क्षेत्र की हिस्सेदारी में तेज वृद्धि देखी गई, इस क्षेत्र में औसतन प्रति माह नए मामलों का एक तिहाई से अधिक हिस्सा होता है। पूर्वी और मध्य क्षेत्र प्रत्येक वर्ष के दौरान क्रमशः कुल मामलों का 10 प्रतिशत का गठन किया। सभी क्षेत्रों, उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर, दिसंबर (चित्र 5 ख) तक संक्रमण की एक एकल लहर का अनुभव किया। अक्टूबर और नवंबर के दौरान त्योहारी सीजन के कारण उत्तरी क्षेत्र में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। प्रति व्यक्ति शर्तों के अनुसार, दक्षिणी क्षेत्र में प्रति लाख 1226 मामलों में अधिकतम केस लोड था, इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में 1124 मामले प्रति लाख थे; पूर्वी क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2020 (चित्र 5 सी) के अनुसार प्रति लाख 342 मामलों में सबसे कम केस लोड था।

चित्र 5: भारत में क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार में रुझान

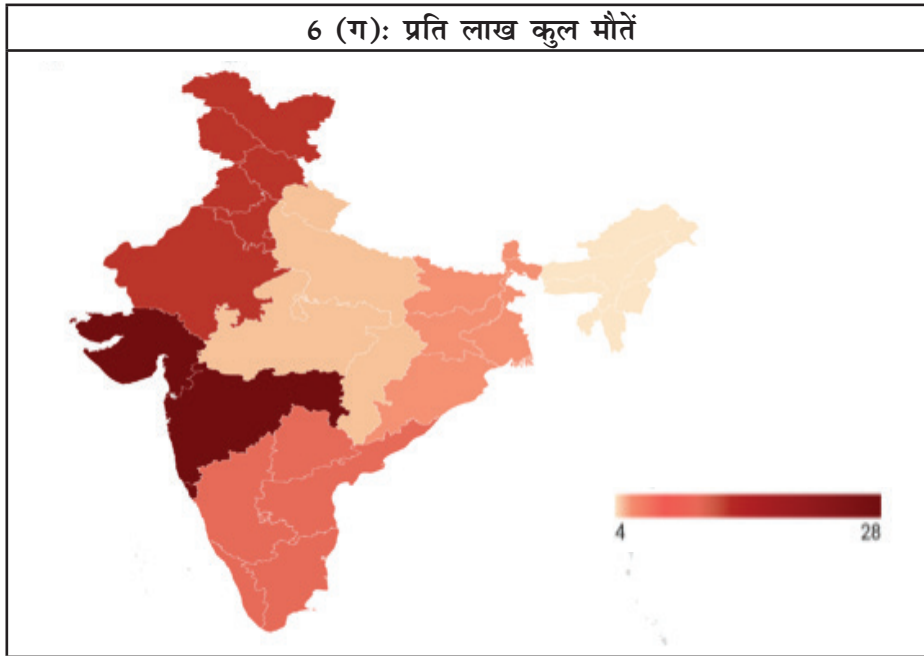
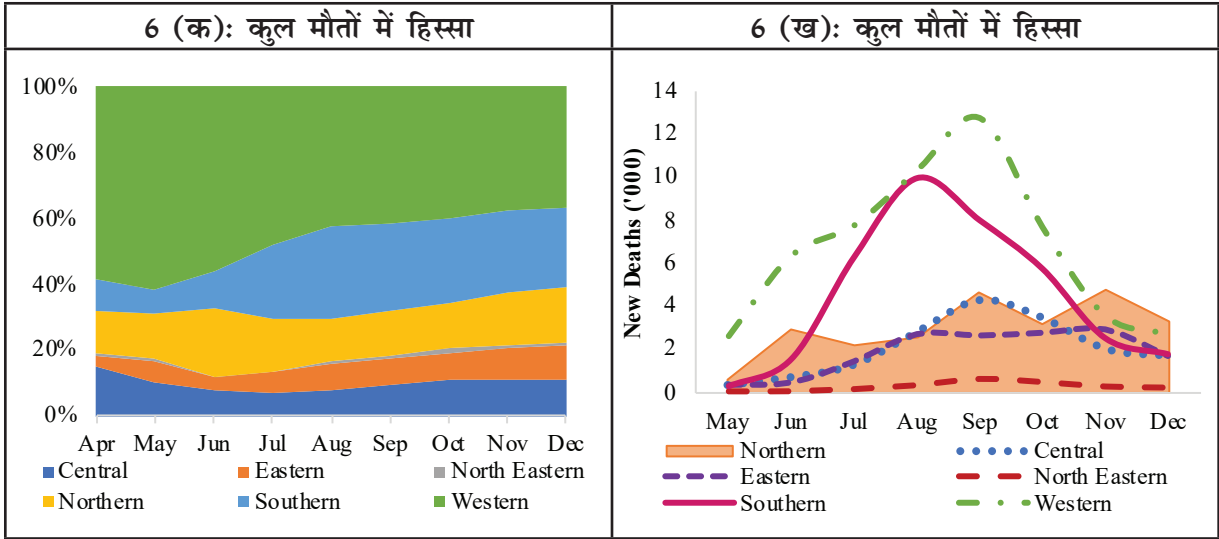


स्रोत: <https://www.Covid19india.org/>, MoH और FW से डेटा एक्सेस किया गया

नोट: डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक है। ज़ोन को ज़ोनल काउंसिल के अनुसार परिभाषित किया गया है।

1.7 भारत में 31 दिसंबर, 2020 तक कुल मृत्यु 1.48 लाख थी, जिसमें देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में होने वाले 50 प्रतिशत से अधिक घातक परिणाम थे। महामारी के दौरान, महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य रहा है (चित्र 6 ए)। उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में मृत्यु (चित्र 6 ब) के संदर्भ में एकल लहर का अनुभव हुआ। उत्तरी क्षेत्र में तीन मौत की लहरें देखी गईं, दूसरी लहर सबसे घातक साबित हुई क्योंकि पहली लहर के दौरान मौतें 1.7 गुना अधिक थीं। प्रति व्यक्ति की दृष्टि से, पश्चिमी क्षेत्र 27 लाख प्रति लाख मौतों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है, इसके बाद उत्तरी क्षेत्र में 13 मौतें प्रति लाख (चित्र 6ब) हैं। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जोन में प्रति व्यक्ति मृत्यु दर क्रमशः 6 और 4 प्रति लाख मौतों में कम रही है।

चित्र 6: भारत के क्षेत्रों में कोविड-19 की मौतों के रुझान



स्रोत: <https://www.Covid19india.org/>, MoH और FW से डेटा एक्सेस किया गया

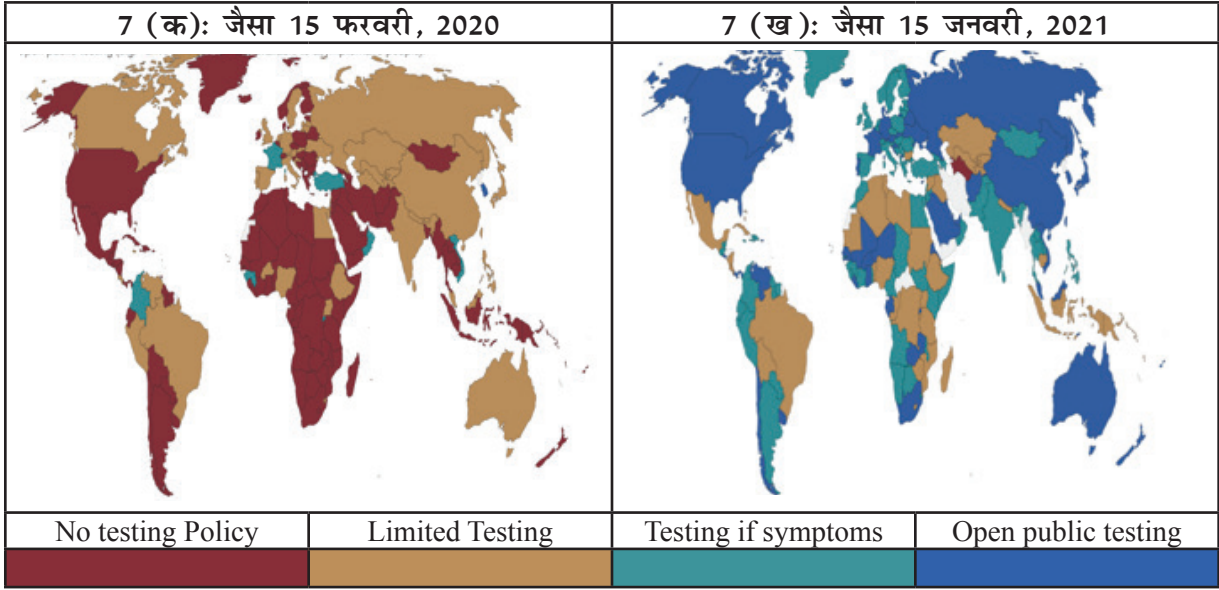
नोट: डेटा 31 दिसंबर, 2020 तक है

ज़ोन को ज़ोनल कार्डसिल के अनुसार परिभाषित किया गया है।

### परीक्षण में तेजी लाना

1.8 समय पर पहचान, शीघ्र अलगाव और प्रभावी उपचार की दिशा में पहले कदम के रूप में, प्रभावी परीक्षण को संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में पहचाना गया था। महामारी की एक विशेषता है, जो अपने डाह को बढ़ाती है, असिमटोमैटिक लोगों द्वारा इसका संभावित संचरण था। इसलिए, बड़े पैमाने पर परीक्षण मामलों की त्वरित पहचान के लिए जरूरी था, प्रसार और समय पर उपचार को रोकने के लिए तत्काल अलगाव। यह प्रभावी संपर्क अनुरेखण और भावी मामलों के समय पर अलगाव में भी मदद करेगा। परीक्षण नीति लगातार विकसित हो रही है क्योंकि देशों के साथ महामारी की शुरुआत तेजी से फैलने की गति (चित्र 7) को रोकने के लिए परीक्षण क्षमता बढ़ा रही है।

चित्र 7: पूरी दुनिया में परीक्षण की तीव्रता

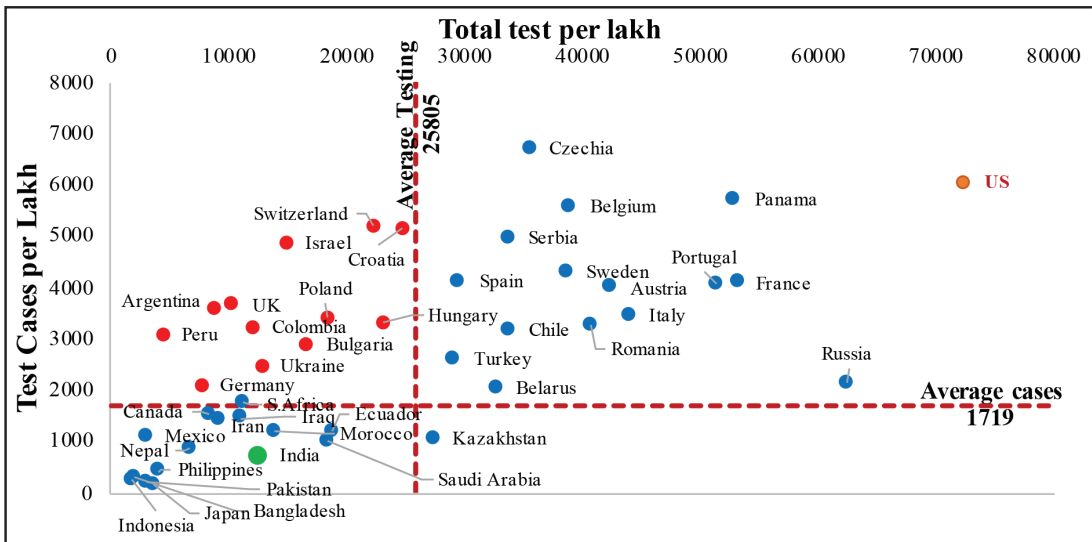


स्रोत: WHO

नोट: “सार्वजनिक परीक्षण खोलें” आक्रामक परीक्षण है; “परीक्षण यदि लक्षण” किसी को भी जो कोविड-19 लक्षण दिखाता है, परीक्षण करने के लिए संदर्भित करता है; “सीमित परीक्षण” तब होता है जब कोई व्यक्ति लक्षण दिखा रहा हो और चिकित्सा कार्यकर्ता, विदेश यात्रा आदि जैसे निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो।

1.9 प्रति लाख और कुल मामलों के प्रति परीक्षण के विश्लेषण से पता चलता है कि यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, जर्मनी, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और पेरू जैसे देशों को और अधिक परीक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रति लाख मामले परीक्षण किए गए परीक्षणों के सापेक्ष उच्चतर हैं। ( 8)। अमेरिका एक बहिर्मुखी है क्योंकि 31 दिसंबर, 2020 तक इसका प्रति लाख और उच्च केस लोड प्रति लाख, दोनों उच्च परीक्षण है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे खराब प्रभावित देश होने के बावजूद वैश्विक औसत मामलों में नीचे है।

चित्र 8: कुल टेस्ट बनाम पुष्टि मामले प्रति लाख

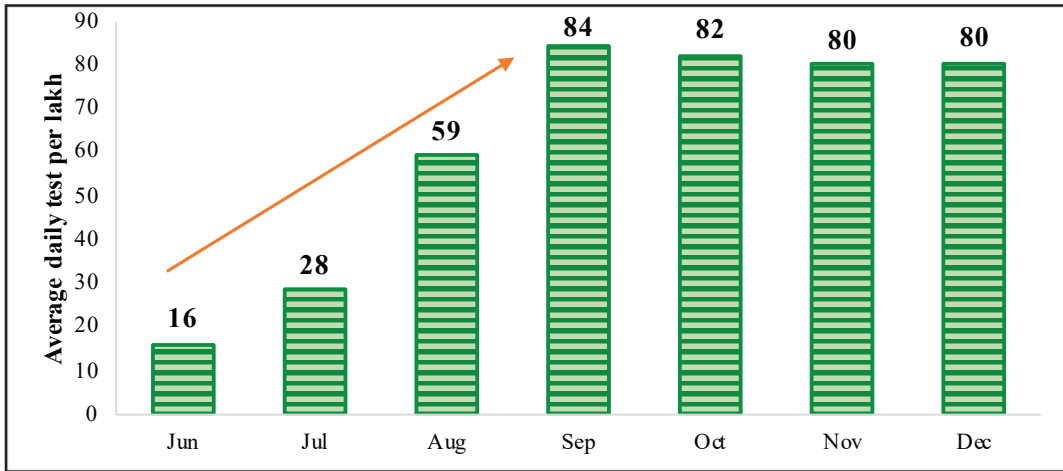


स्रोत: WHO

नोट: डेटा 31 दिसंबर 2020 तक है

1.10 भारत ने तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई। जनवरी 2020 में, भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 के लिए केवल एक प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था। आज देश भर में 2300 से अधिक प्रयोगशालाएँ हैं, जो इसके निदान के लिए आणविक परीक्षण करती हैं—भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। भारत ने परीक्षण आधारीक संरचना के विस्तार पर एक समर्पित जोर के साथ दैनिक परीक्षणों के संचालन में जबरदस्त प्रगति दिखाई है। “टेस्ट, ट्रेक एंड ट्रीट” रणनीति पर ध्यान देते हुए, भारत ने 31 दिसंबर, 2020 तक संचयी टैस्ट पॉजिटिव दर के साथ लगभग 18.5 करोड़ संचयी कोविड-19 नमूनों का परीक्षण किया है।

चित्र 9: भारत में परीक्षण की शुरूआत



स्रोत: MoH&FW

1.11 कोविड-19 के संचरण और घातकता की अभूतपूर्व गति ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया, जिसके कारण 10 करोड़ से अधिक पुष्ट मामलों और 21 लाख से अधिक मृत्यु दर के एक विशाल मानव हताहत का सामना करना पड़ा। शक्तिशाली इलाज और निवारक वैक्सिन की अनुपलब्धता को देखते हुए, यह जरूरी था कि विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करके प्रसार को समाहित किया जाए। हालाँकि, इसने दुनिया भर की सरकारों के समक्ष महत्वपूर्ण नीतिगत दुविधाएँ प्रस्तुत कीं।

## नीति दुविधा अंतर्निहित कोविड-19

### ‘जीवन बनाम आजीविका’

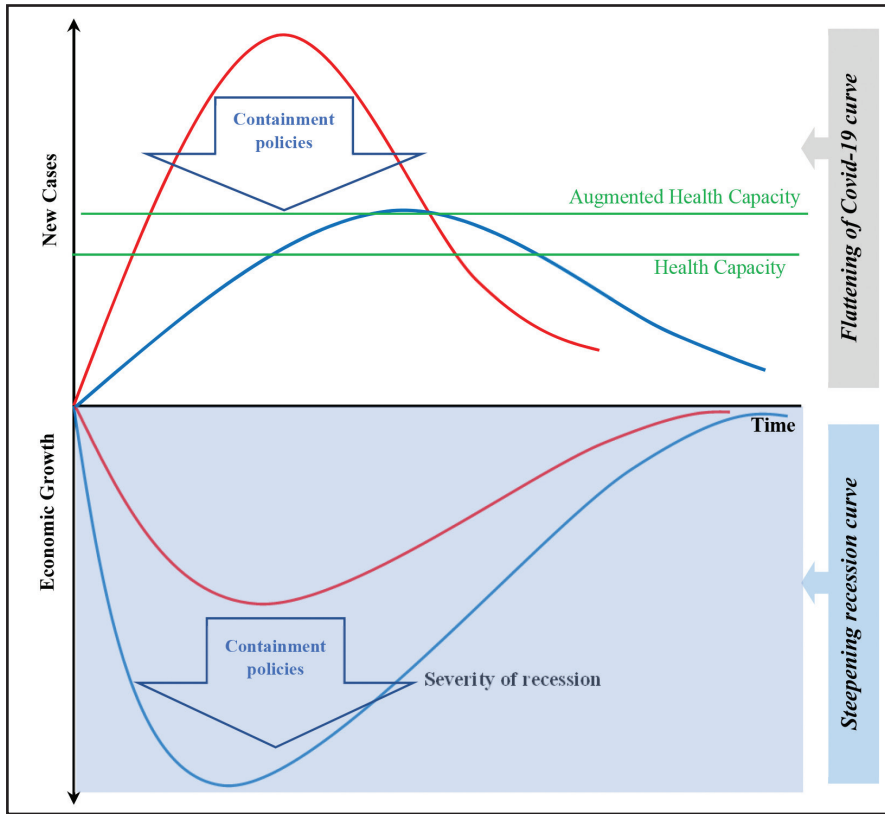
1.12 महामारी के तेजी से प्रसार को देखते हुए, तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की प्राथमिकता थी, ‘महामारी विज्ञान वक्र को फैलाने’ के प्रभाव को कम करने के लिए (अध्याय 1, खंड -1, आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 में बॉक्स 1 का संदर्भ लें)। “वक्र को समतल करने” के उद्देश्य वायरस के संचरण को धीमा करना, वक्र के शिखर को धक्का देना और समय के साथ मामलों के वितरण को फैलाना। देशों ने, तदनुसार, दुनिया भर में विभिन्न गैर-फार्मास्युटिकल हस्तक्षेप (NPIs) को अपनाया, जैसे कार्य और स्कूल बंद होने, यात्रा पर प्रतिबंध, सार्वजनिक घटनाओं को रद्द करना और आंतरिक आंदोलन के प्रतिबंधों के माध्यम से सामाजिक अलगाव के उपायों जैसे कि संक्रमित लोगों को बाहर निकालना, आबादी, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क और उन्नत परीक्षण का पता लगाना। रोकथाम के उपायों ने स्वास्थ्य और परीक्षण के बुनियादी ढांचे में गड़बड़ी की अनुमति दी, वायरस के प्रसार को गिरफ्तार किया और ‘लोगों की जान’ बचाई। अध्याय 1, सर्वेक्षण का आयतन बताता है कि जिन देशों ने प्रभावी रूप से महामारी की शुरुआत में प्रभावी NPIs लगाए हैं, वे अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से



महामारी के प्रसार का प्रबंधन कर सकते हैं।

1.13 भले ही कोई रोकथाम के उपाय लागू नहीं किए गए थे, तो महामारी से निपटने के लिए अनिश्चितता का सामना करने वाले परिवारों और फर्मों के एहतियाती और/या आतंक व्यवहार से मंदी का सामना करना पड़ता जिसका कोई इलाज नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवारों ने स्वेच्छा से सावधानी बरती, जिससे मांग प्रभावित हुई, विशेषकर गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए। लॉकडाउन ने महामारी के लिए इस प्रतिक्रिया को मजबूत किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, प्रसार को शामिल करने के लिए अपनाया, बड़े पैमाने पर तत्काल आर्थिक लागतों का अनुमान लगाया क्योंकि उन्होंने आर्थिक गतिविधि, घुमावदार खपत और निवेश के लगभग पूर्ण निलंबन का नेतृत्व किया, साथ ही साथ प्रतिबंधित श्रम आपूर्ति और उत्पादन भी। कोविड-19, इसलिए दुनिया को 'वक्र' या 'आजीविका' बचाने की भविष्यवाणी करने के लिए ले गया क्योंकि संक्रमण वक्र को समतल करने के लिए उठाए गए कदमों ने वृहद आर्थिक मंदी की अवस्था (चित्र 10) को बढ़ा दिया।

चित्र 10: समतल कोविड-19 संक्रमण वक्र के बीच व्यापार-बंद और मंदी की अवस्था का सामना



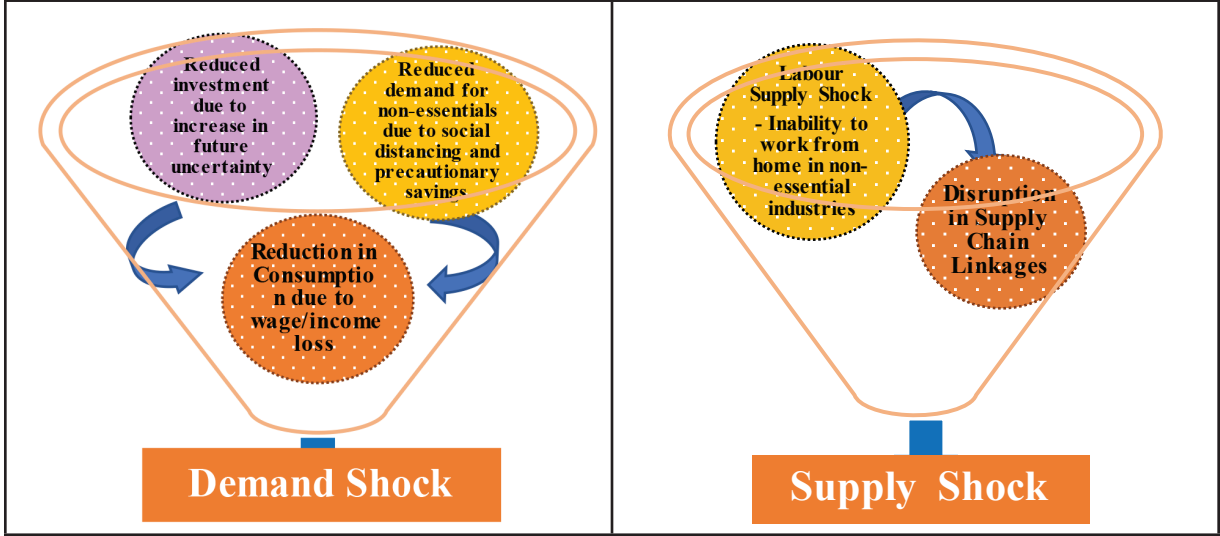
स्रोत: Gourinchas, P-O (2020) से अनुकूलित

### मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष की चुनौतियाँ

1.14 महामारी को एक अनोखा आर्थिक झटका लगा है जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं (चित्र 11) में एक साथ आपूर्ति और मांग के दोनों झटके शुरू कर दिए हैं। अनिश्चितता, कम आत्मविश्वास, आय में कमी, कमजोर विकास की संभावना, संसर्ग की आशंका, सभी संपर्क-संवेदनशील गतिविधियों को बंद करने के कारण खर्च करने के विकल्प को कम करना और वित्तीय और तंग वित्तीय और ऋण की स्थिति एहतियाती बचत को ट्रिगर करती है, व्यवसायों और परिणामी गिरावट के बीच जोखिम का बढ़ना। खपत और निवेश में-पहले

ऑर्डर की मांग को झटका। आर्थिक गतिविधि को बंद करने और पहले के आदेश की आपूर्ति के झटके के लिए श्रम नेतृत्व के प्रतिबंधित आंदोलन के कारण आपूर्ति श्रृंखला का व्यवधान।

चित्र 11: वैश्विक महामारी से दुगुने आर्थिक झटके



स्रोत: Estupinan, Xavier and Sharma, Mohit and Gupta, Sargam and Birla, Bharti (2020) से अनुकूलित

1.15 पहले आदेश की आपूर्ति के पक्ष में व्यवधान अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति पक्ष दोनों पर अनुक्रमिक दूसरे दौर का प्रभाव हो सकता है। प्रारंभिक आपूर्ति के झटके, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी और आय में कमी हुई, कुल मांग में दूसरी गिरावट आ सकती है और उत्पादक क्षमता की हानि हो सकती है, जिससे दूसरे ऑर्डर की आपूर्ति को झटका लग सकता है। इन प्रभावों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, वैश्विक गतिविधि को कम करने और कमोडिटी की कीमतों को नीचे धकेलने के लिए मांग और आपूर्ति के फीडबैक लूप में हिस्टैरिसिस प्रभाव पैदा करने की क्षमता है—जब घर कम मांगते हैं, तो फर्मों को कम राजस्व मिलता है, जो फर्मों द्वारा कम गतिविधि में फीड होता है, और इस प्रकार घरेलू आय में कमी आती है।

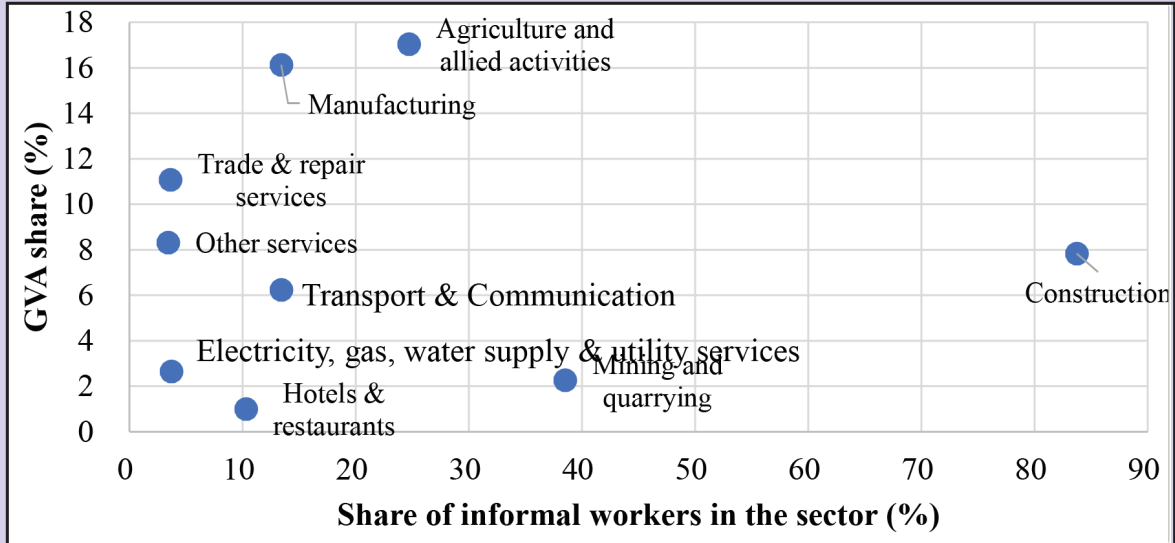
1.16 'महामारी विज्ञान वक्र' को 'समतल करने के लिए नीतियों, इसलिए, डिजाइन की गई आर्थिक नीतियों के साथ-साथ आर्थिक प्रणाली के परिणामस्वरूप होने वाले झटके को कम करने और मंदी की अवस्था को समतल करने के लिए लक्षित होना चाहिए। हालाँकि, महामारी के संभावित प्रसार के बारे में अभूतपूर्व अनिश्चितता थी। इसलिए महामारी में नीति निर्माताओं के आगे अभूतपूर्व दुविधाएं पैदा हुईं—आजीविका बनाम जीवन और महामारी के जुड़वां घटनों को समतल करना और परिणामी आर्थिक मंदी।

**बॉक्स 1: भारत में कोविड-19 का क्षेत्रीय प्रभाव: सर्वव्यापी मगर अनियमित**

कोविड-19 प्रेरित जुड़वां आर्थिक आघात के प्रसार और तीव्रता को आउटपुट/सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और रोजगार पर प्रभाव के माध्यम से मोटे तौर पर कब्जा किया जा सकता है। GVA सदमे के संदर्भ में, गैर-आवश्यक गतिविधियों को उनके संबंधित GVA योगदान के लिए आनुपातिक रूप से एक संयुक्त झटका सहन करने की संभावना है, यह देखते हुए कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान संचालित करने की अनुमति नहीं थी। आवश्यक गतिविधियां मुख्यतः गैर-आवश्यक क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों के अप्रत्यक्ष प्रभाव से उत्पन्न होने वाले झटके से गुजरने की संभावना है। रोजगार के झटके के संदर्भ में, व्यापार, होटल, परिवहन, पर्यटन आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संपर्क

से संबंधित व्यवसायों को संबंधित रोजगार हिस्सेदारी के लिए आनुपातिक से गुजरना पड़ता है, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए बड़ा खामियाजा उठाने की संभावना होती है (चित्र बी 1)। निर्माण और खनन क्षेत्र, जो अनौपचारिक श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा नियोजित करते हैं, महामारी से प्रभावित ताले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

**Figure B1: Sectoral Distribution by GVA Share and Share of Casual Workers**

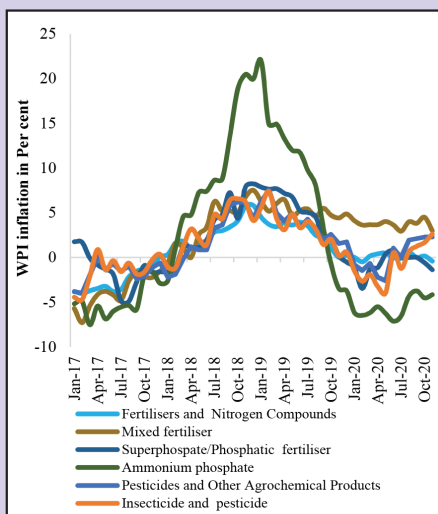


स्रोत: MoSPI, PLFS 2018-19

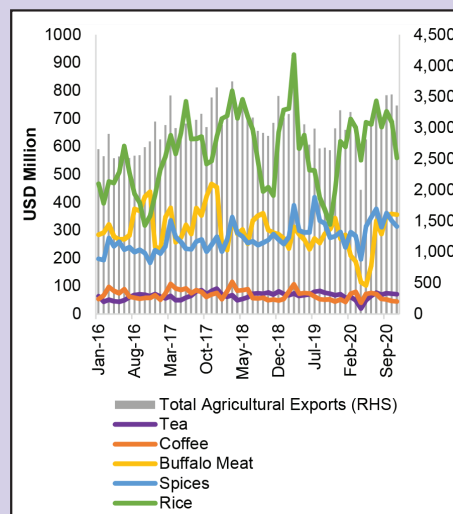
महामारी और संबद्ध स्वास्थ्य उपायों का प्रभाव अद्वितीय रहा है क्योंकि इसने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। भारत में कृषि को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन से रोधित किया गया था क्योंकि कोविड-प्रेरित लॉकडाउन से सेक्टर में समय पर और सक्रिय छूट के कारण रबी फसलों की निर्बाध कटाई और खरीफ फसलों की बुवाई की सुविधा थी। हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और कुछ प्रमुख कृषि निर्यातों पर प्रतिफल प्रारंभिक प्रभाव के कारण कृषि वस्तुओं के प्रवाह को प्रभावित किया। विनिर्माण क्षेत्र को पहली तिमाही में कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन तब से उठा है, हालांकि खनन अभी भी पिछड़ा हुआ है। निर्माण और सेवा क्षेत्र पर सामाजिक अंतर और व्यक्तिगत परस्पर क्रिया को कम करने की महामारी से प्रेरित आवश्यकताओं के कारण सबसे कठिन आघात हुआ था।

**चित्र B2: भारत में कोविड-19 का क्षेत्रीय प्रभाव कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ**

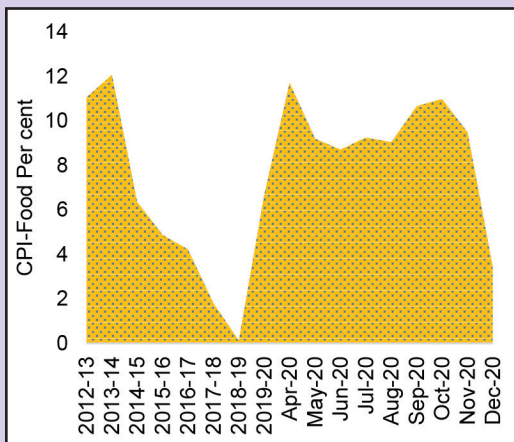
**कृषि आयात**



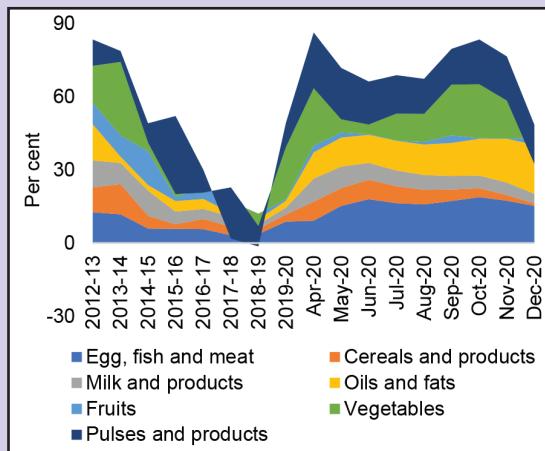
**कृषि निर्यात**



### सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति

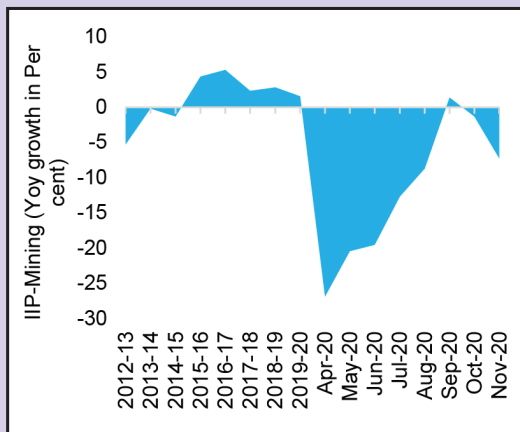


### CPI के घटक- खाद्य मुद्रास्फीति

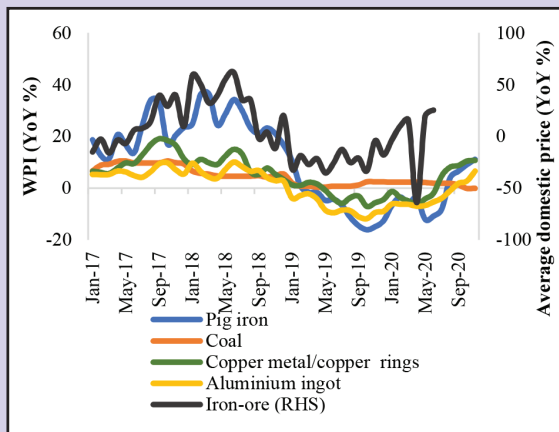


### खनन एवं उत्खनन

खनन अभी भी पूर्व-महामारी स्तरों के नीचे

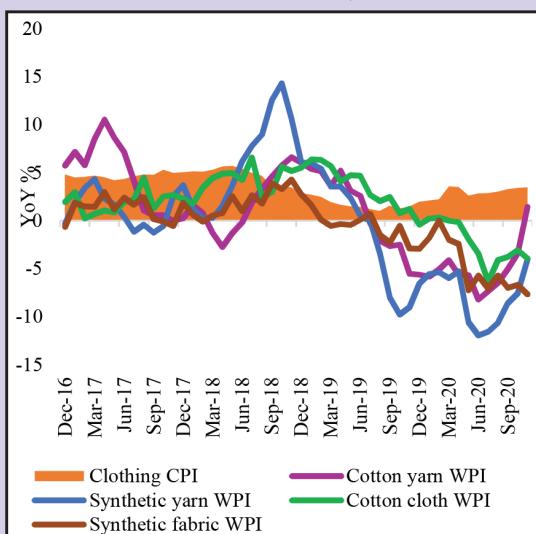


खनिज मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई है

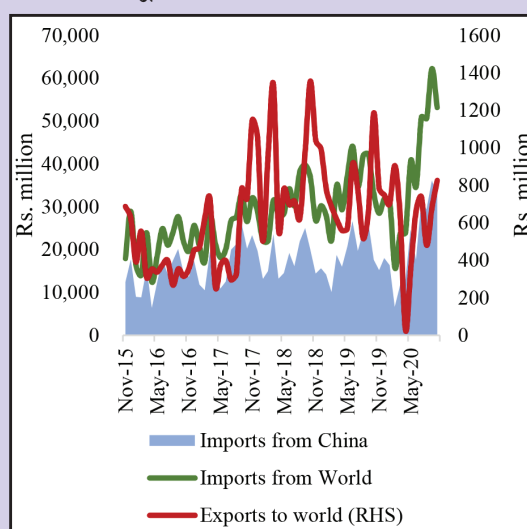


### विनिर्माण

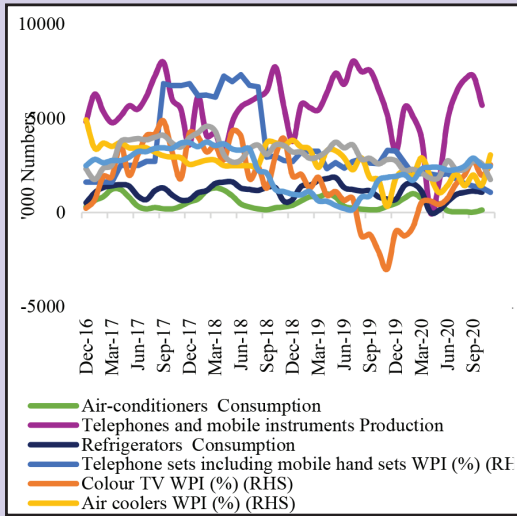
वस्त्र और कपड़ा



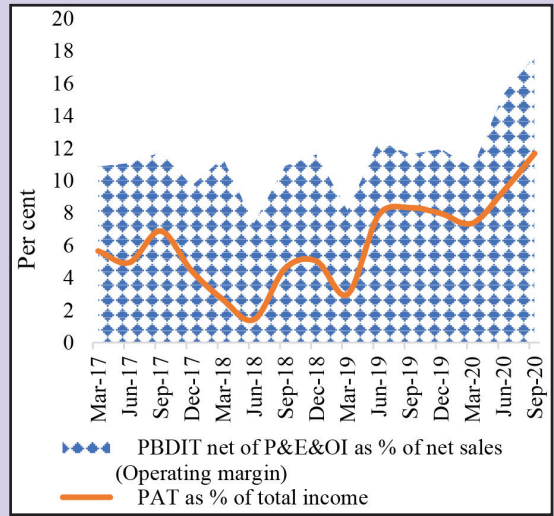
कंप्यूटर हार्डवेयर और परिधीय



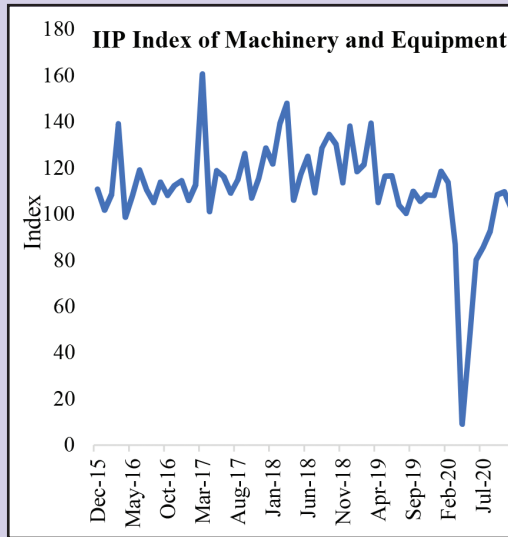
### उपभोक्ता वस्तुएं



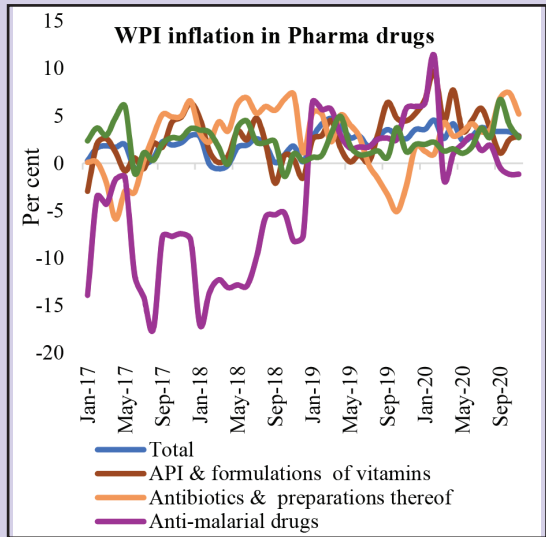
### उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की लाभप्रदता अनुपात



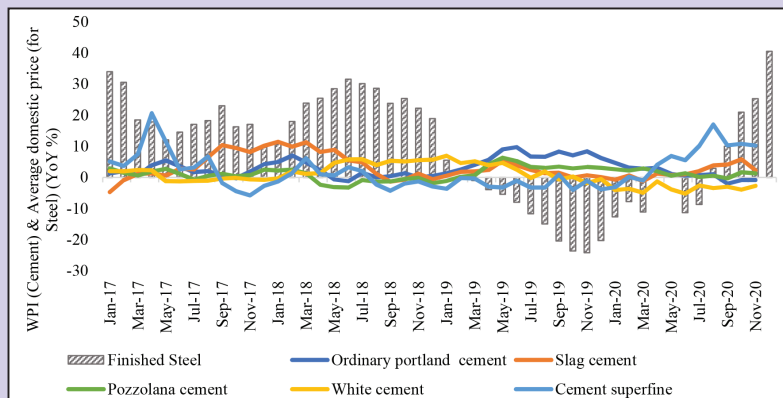
### मशीनरी क्षेत्र



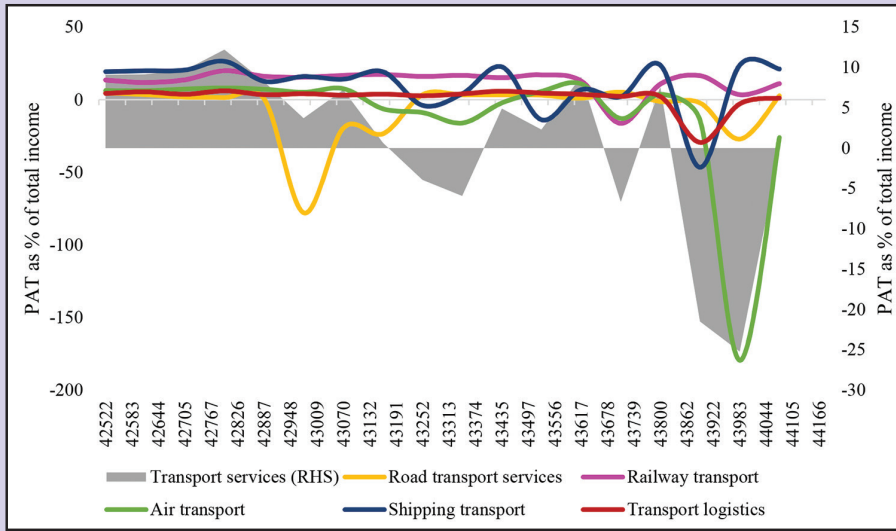
### फार्मास्यूटिकल्स



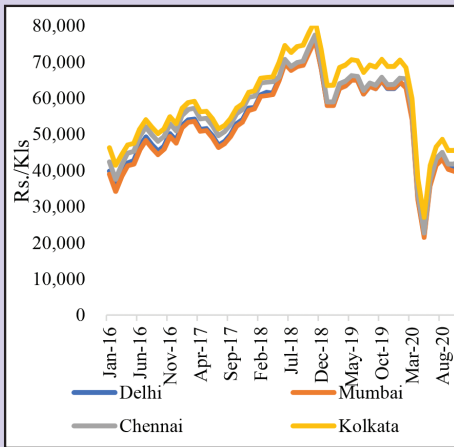
### निर्माण



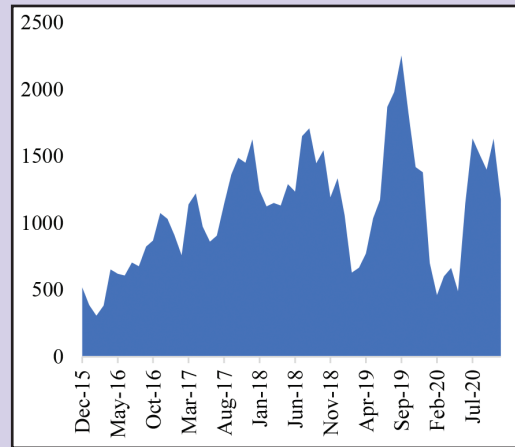
### सेवाएं



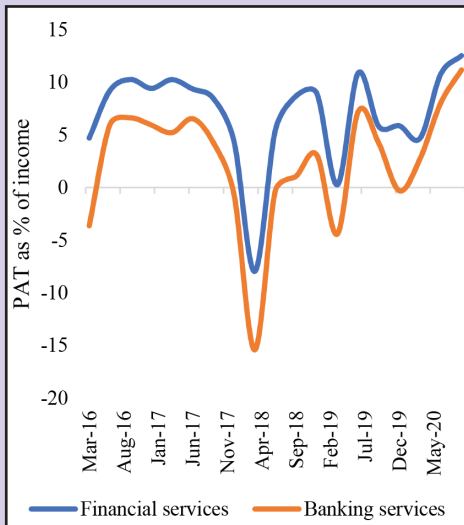
### वायु टरबाइन ईंधन की कीमतें: भारत



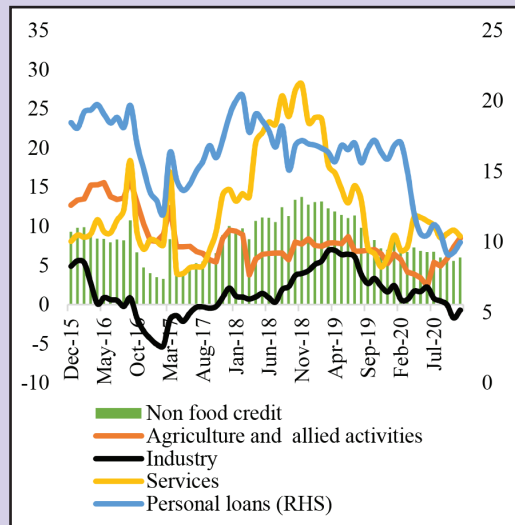
### शिपिंग भाड़ा दर (बाल्टिक सूखा सूचकांक)



### वित्तीय सेवाएं

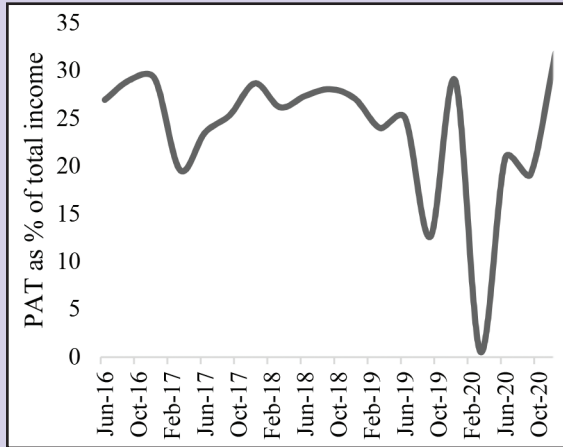


### बैंक ऋण वृद्धि (YoY)

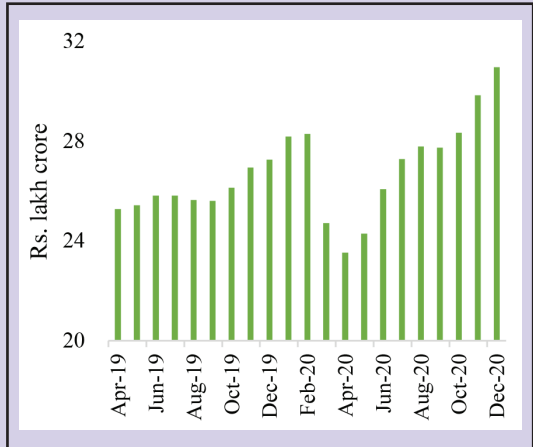




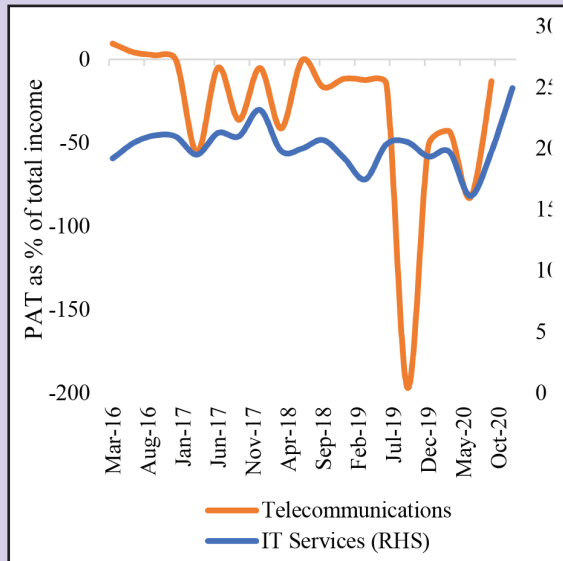
### एसेट फाइनेंसिंग सर्विसेज



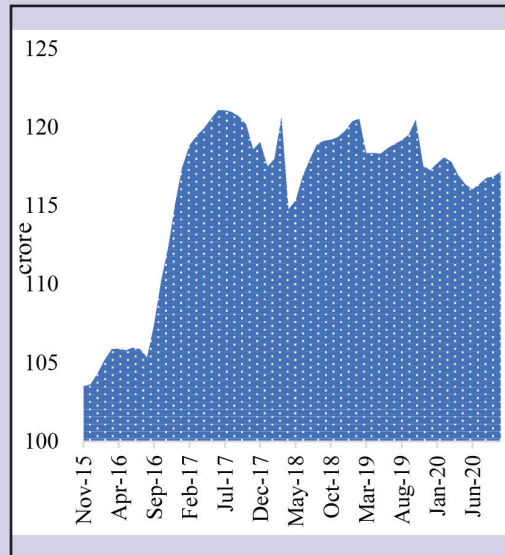
### प्रबंधन के तहत औसत शुद्ध संपत्ति (म्यूचुअल फंड)



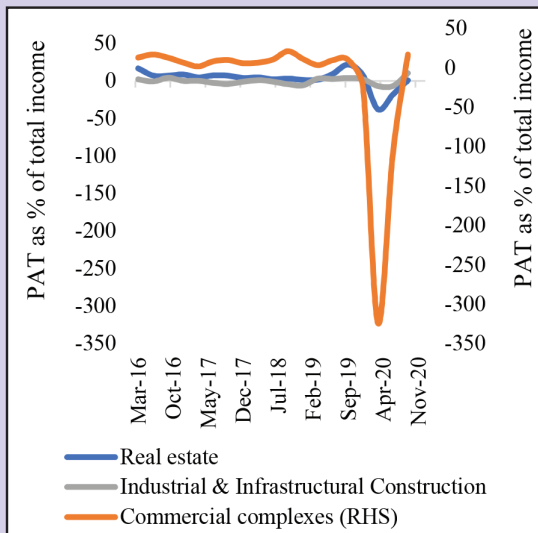
### संचार सेवाएं



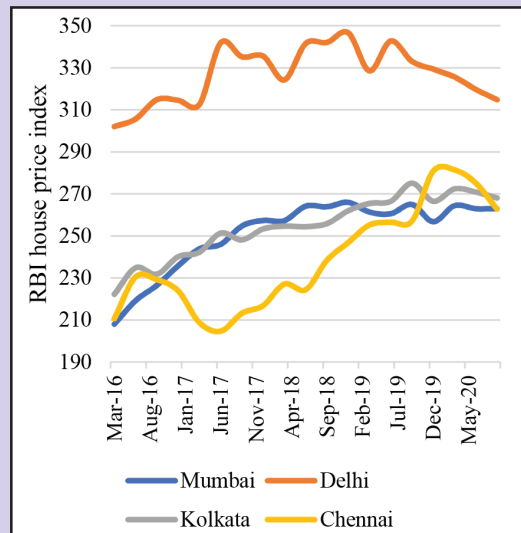
### दूरसंचार ग्राहक आधार



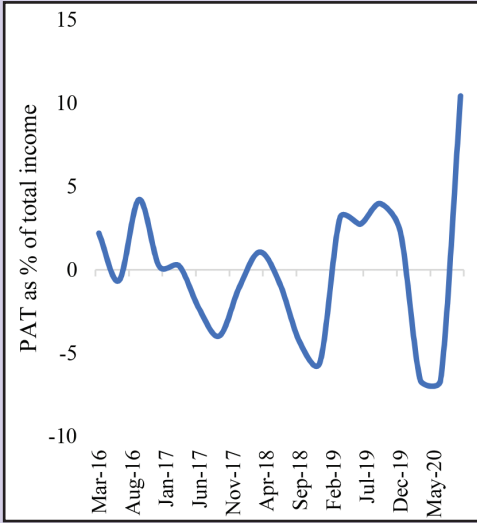
### रियल एस्टेट सेवाएं



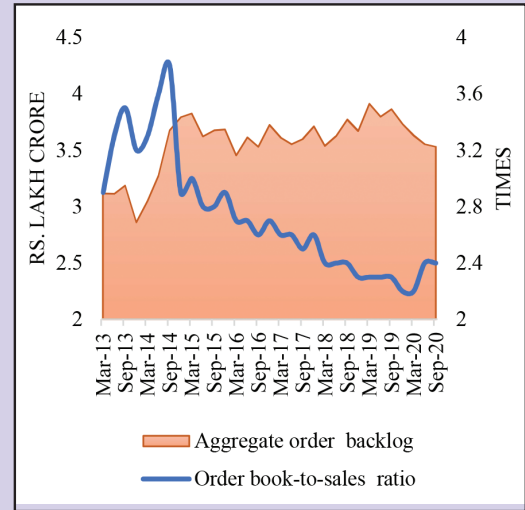
### आवास की कीमतें



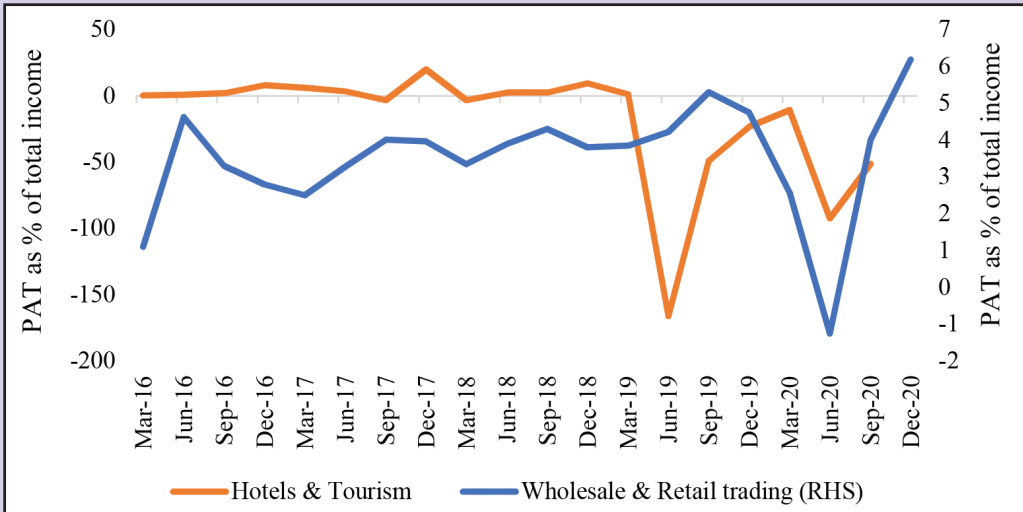
### औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कंपनियां



### औद्योगिक और ढांचागत निर्माण कंपनियों के सकल आदेश बैकलॉग



### होटल और पर्यटन, थोक और खुदरा व्यापार



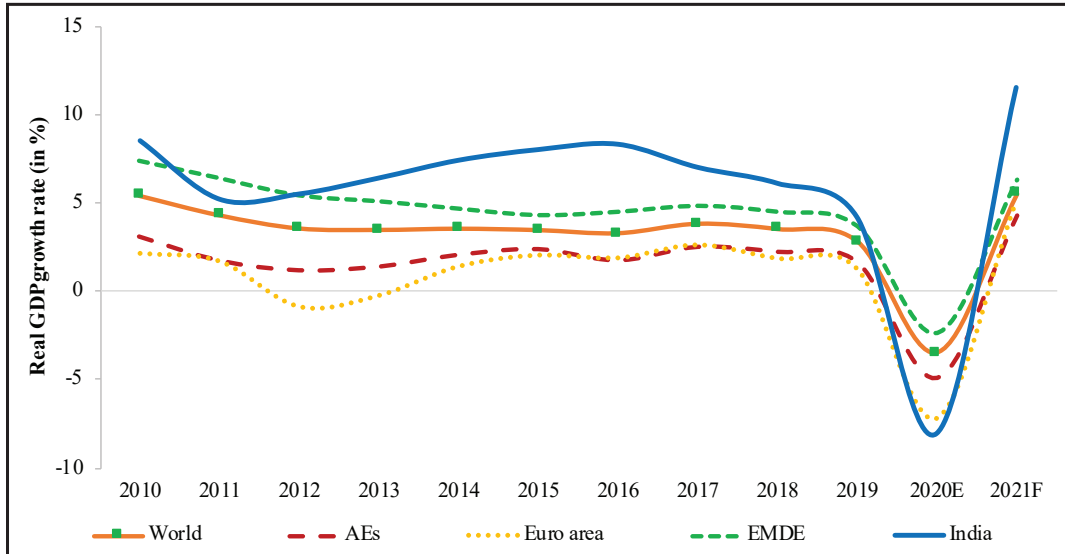
स्रोत: विभिन्न स्रोतों से संकलित

### महामारी द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था का विघटन

1.17 जैसा कि पहले खंड से स्पष्ट था, महामारी ने वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व स्वास्थ्य चुनौतियों को उठाया और अद्वितीय नीतिगत दुविधाएं पैदा कीं। 2018 के बाद से, वैश्विक उत्पादन में वृद्धि की गति कमजोर पड़ने के कारण व्यापार तनाव, राजनीतिक अस्थिरता, धीमी मांग और औद्योगिक गतिविधि में कमी जैसे विभिन्न कारणों के कारण थी। कोविड-19 महामारी ने गंभीर मांग और आपूर्ति में विच्छेद पैदा करके मंदी को बढ़ा दिया है। आधिकारिक गतिविधियों और निजी निर्णयों दोनों के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है। महामारी के बाद की आर्थिक संभावनाओं और नीतियों के बारे में अनिश्चितता ने निवेश की गति को रोक दिया है; शिक्षा में व्यवधानों ने मानव पूंजी संचय को कम कर दिया है; और वैश्विक मूल्य श्रृंखला और महामारी के मार्ग की व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन पर तौला है।

1.18 अप्रैल 2020 का महीना “ग्लोबल लॉकडाउन” का महीना बन गया, जिसमें विश्व आर्थिक गतिविधि एक ठहराव पर आ गई—2020 की दूसरी तिमाही के दौरान उत्पादन में भारी गिरावट आई। वैश्विक उत्पादन में एक सदी में सबसे तेज संकुचन देखने की उम्मीद है, जिसमें अनुबंध किया जा रहा है। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा क्रमशः प्रदान किए गए अनुमानों (चित्र 12) के अनुसार 2020 में 3.5–4.3 प्रतिशत की श्रेणी में संकुचन देखा गया है। 2020 और 2021 में वैश्विक GDP का संचयी नुकसान लगभग 9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर आंका गया है—जापान और जर्मनी की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं से अधिक। चीन को छोड़कर, EMDEs की तुलना में 5.4 प्रतिशत पर आउटपुट का नुकसान AEs में अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020 (चित्र 12) के लिए 5.0 प्रतिशत पर था। यह EMDEs की तुलना में AEs में फैली महामारी के अधिक गंभीर प्रभाव के साथ संरेखित है जैसा कि अध्याय के शुरुआती भाग में देखा गया था। वर्ष के जुलाई–सितंबर तिमाही में लॉकडाउन को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधि में पुनरुत्थान के साथ वैश्विक विकास के अनुमानों को वर्ष के माध्यम से ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। AEs में कोविड-19 संक्रमण दर में पुनरुत्थान के कारण वैश्विक गतिविधि में पलटाव, हालांकि, असमान और वश में किया गया है, जो वर्ष की दूसरी छमाही की शुरुआत से ही है।

चित्र 12: वैश्विक विकास में प्रवृत्ति



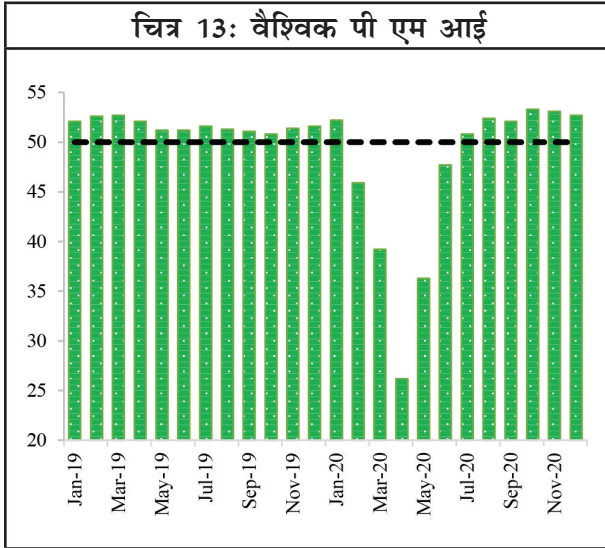
स्रोत: आईएमएफ

टिप्पणी: ई आकलन है, एफ पूर्वानुमान है।

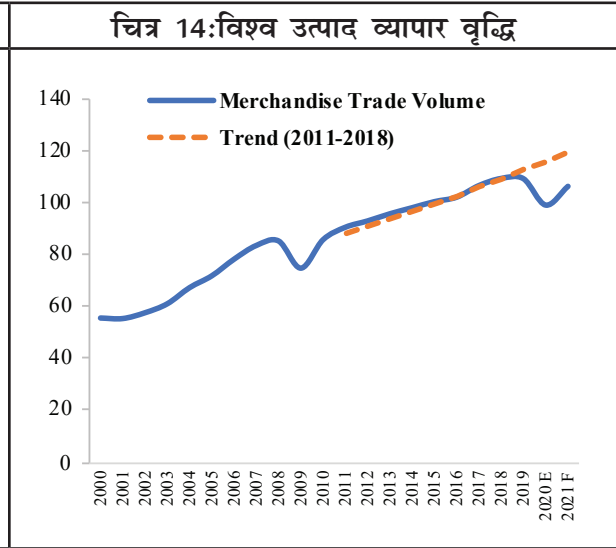
1.19 महामारी से प्रेरित सीमा बंद होने और आपूर्ति बाधित होने से वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान में बाधा उत्पन्न हुई। वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) जुलाई, 2020 (चित्र 13) से पहले पांच महीने के लिए संकुचन में था। वैश्विक व्यापार को 2020 में 9.2 प्रतिशत तक अनुबंधित करने का अनुमान है—2009 की वैश्विक मंदी के दौरान गिरावट के साथ तुलनात्मक रूप से लेकिन अर्थव्यवस्थाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी (चित्र 14) को प्रभावित किया है। व्यापार ने महामारी का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देशों को जीवनप्रद भोजन और चिकित्सा आपूर्ति तक सुरक्षित पहुंच मिल सकती है।

1.20 2020 के मध्य से अधिकांश कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि सख्त तालाबंदी को धीरे-धीरे हटा लिया गया और मांग दृढ़ हो गई विशेषकर चीन से (चित्र 15)। तेल की मांग पर महामारी के स्थायी प्रभाव पर चिंता के बीच तेल की कीमतों में वसूली अधिक मामूली थी। दिसंबर, 2019 की तुलना में नवंबर, 2020 में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ महामारी की कीमतों की पृष्ठभूमि में सोना एक सुरक्षित

ठिकाने के निवेश के रूप में उभरा। कमजोर मांग और कम ऊर्जा की कीमतों के परिणामस्वरूप, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मुद्रास्फीति में कमी आई है, प्रमुख AEs में अपस्फीति का दबाव उत्पन्न हुआ। EMDEs में मुद्रास्फीति में गिरावट AEs की तुलना में कम व्यापक थी, कुछ देशों में तेज मुद्रा मूल्यहास के प्रभाव के साथ-साथ घरेलू खाद्य कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है (चित्र 16)।

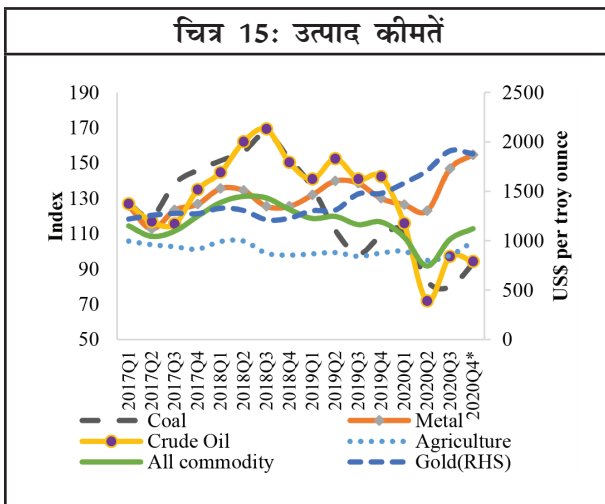


स्रोत: IHS



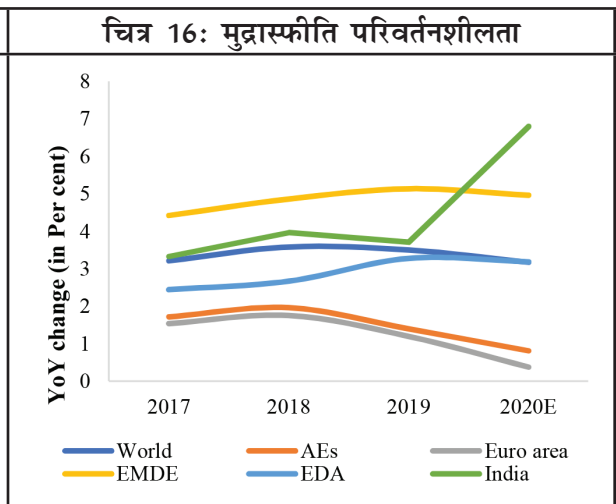
स्रोत: WTO

Note: World Trade in 2015 Indexed at 100



स्रोत: IMF

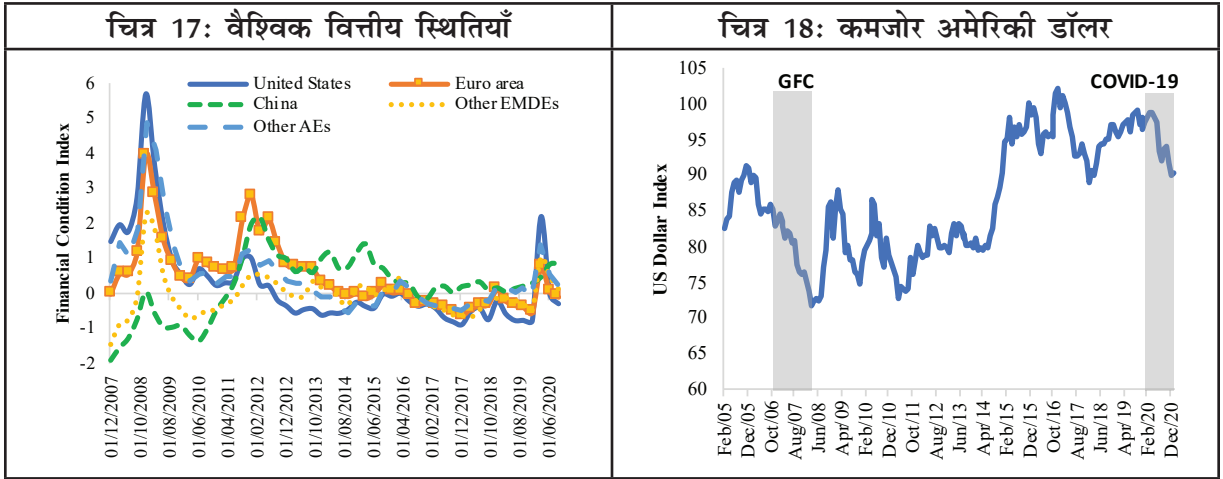
नोट: \*नवंबर 2020 तक का डाटा



स्रोत: WEO अक्टूबर 2020 डेटाबेस, IMF

1.21 वैश्विक वित्तीय स्थिति केंद्रीय बैंकों द्वारा अभूतपूर्व तेजी से हस्तक्षेप (चित्र 17) द्वारा निरंतर नीति समर्थन के पीछे बनी हुई है। मातहत गतिविधि और अत्यधिक अनिश्चित दृष्टिकोण के बावजूद, वैश्विक इक्विटी बाजारों ने मार्च कम से तेज गति से पलटाव किया है, हालांकि वायरस के प्रसार, नीति समर्थन और क्षेत्रीय संरचना के आधार पर, देशों में उल्लेखनीय भेदभाव के साथ। जोखिम परिसंपत्तियों की कीमतों में व्यापक प्रतिक्षेप के पीछे क्षेत्रों में भेदभाव के स्पष्ट संकेत हैं। कुछ क्षेत्र (जैसे एयरलाइंस, होटल, ऊर्जा और वित्तीय) लॉकडाउन और सामाजिक गड़बड़ी से अधिक प्रभावित हुए हैं, जबकि वे जो कम संपर्क-गहन (सूचना प्रौद्योगिकी, संचार)

बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स सबसे अधिक जी-10 मुद्राओं की तुलना में साल दर साल आधार पर 7.4 प्रतिशत तक कमजोर हो गया है, जिसमें विभिन्न देशों ने अपनी विनिमय दरों पर दबाव कम करने के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाया है। (चित्र 18)।



स्रोत: IMF

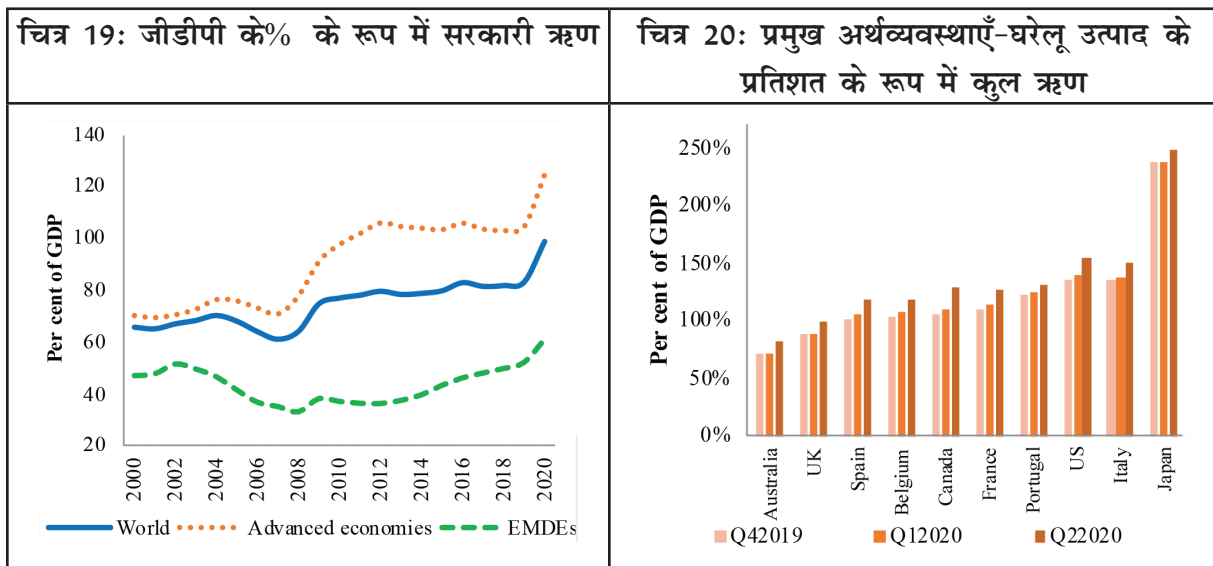
स्रोत: Thomson Reuters

नोट: ग्राफ इंडेक्स के माध्य से मानक विचलन को दर्शाता है—एक कम मूल्य समायोजन रुख को दर्शाता

नोट: यूएस डॉलर इंडेक्स यूएस ट्रेड पार्टनर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्राओं की भारत टोकरी के मुकाबले

1.22 महामारी ने वैश्विक ऋण संचय की एक दशक लंबी लहर के साथ जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है। बड़े पैमाने पर विवेकाधीन समर्थन, आउटपुट में तेज संकुचन और राजस्व में भारी गिरावट के कारण सरकारी ऋण और घाटे में वृद्धि हुई है। ऋण बोझ बढ़ गया है क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने तेजी से कम बिक्री की अवधि का सामना किया है और संप्रभु लोगों ने बड़े प्रोत्साहन पैकेजों को वित्तपोषित किया है। ऋण का स्तर ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से वित्तीय बाजार तनाव (चित्र 19) के प्रति कमजोर हो गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सरकारी ऋण 2020 की दूसरी तिमाही (चित्र 20) के दौरान बढ़ा। ऋण में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सरकारें और वित्तीय प्रणालियां पूंजी, श्रम, कौशल और नवाचार के बाद के आर्थिक माहौल में बदलाव की सुविधा देकर वसूली को वित्त प्रदान करती हैं।

1.22 महामारी ने वैश्विक ऋण संचय की एक दशक लंबी लहर के साथ जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है। बड़े पैमाने पर विवेकाधीन समर्थन, आउटपुट में तेज संकुचन और राजस्व में भारी गिरावट के कारण सरकारी ऋण और घाटे में वृद्धि हुई है। ऋण बोझ बढ़ गया है क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने तेजी से कम बिक्री की अवधि का सामना किया है और संप्रभु लोगों ने बड़े प्रोत्साहन पैकेजों को वित्तपोषित किया है। ऋण का स्तर ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से वित्तीय बाजार तनाव (चित्र 19) के प्रति कमजोर हो गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सरकारी ऋण 2020 की दूसरी तिमाही (चित्र 20) के दौरान बढ़ा। ऋण में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सरकारें और वित्तीय प्रणालियां पूंजी, श्रम, कौशल और नवाचार के बाद के आर्थिक माहौल में बदलाव की सुविधा देकर वसूली को वित्त प्रदान करती हैं।



स्रोत: विश्व बैंक, 2020 का डेटा अनुमान है

स्रोत: OECD

1.23 आगे बढ़ते हुए, प्रभावी टीकाकरण अभियान, उपभोक्ता और व्यवसाय के विश्वास की बहाली के साथ-साथ निरंतर मौद्रिक और राजकोषीय समर्थन से 2021 में वैश्विक उत्पादन 4.5 से 5.5 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। इस पूर्वानुमान में नकारात्मक जोखिमों में उत्परिवर्ती उपभेदों की संभावना, देरी शामिल हैं। टीके की खरीद और वितरण, महामारी से संभावित उत्पादन पर विघटनकारी प्रभाव, और उच्च ऋण स्तर और कमजोर विकास के कारण वित्तीय तनाव।

### एक वी आकार के सुदृढ़ प्रक्षेपवक्र पर भारतीय अर्थव्यवस्था

1.24 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019 में मातहत वृद्धि के बाद, जनवरी 2020 से फिर से गति प्राप्त करना शुरू कर दिया था, केवल एक बार की सदी के काले हंस कोविड-19 के प्रकोप से रुकी हुई थी। मार्च-अप्रैल, 2020 के दौरान लगाए गए कड़े लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही -21 और 7.5 प्रतिशत 7.5 Q2% FY 2020 में तेज संकुचन देखा गया था। तब से, कई उच्च आवृत्ति संकेतक ने क्षेत्रों में एक वी-आकार की वसूली का प्रदर्शन किया क्षेत्रों में एक असमानता, अंतर और प्रेरक शक्ति के साथ। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं, क्योंकि धीरे-धीरे लॉकडाउन की गति कम होती जा रही है और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन के रास्ते पर मजबूती से रखा है।

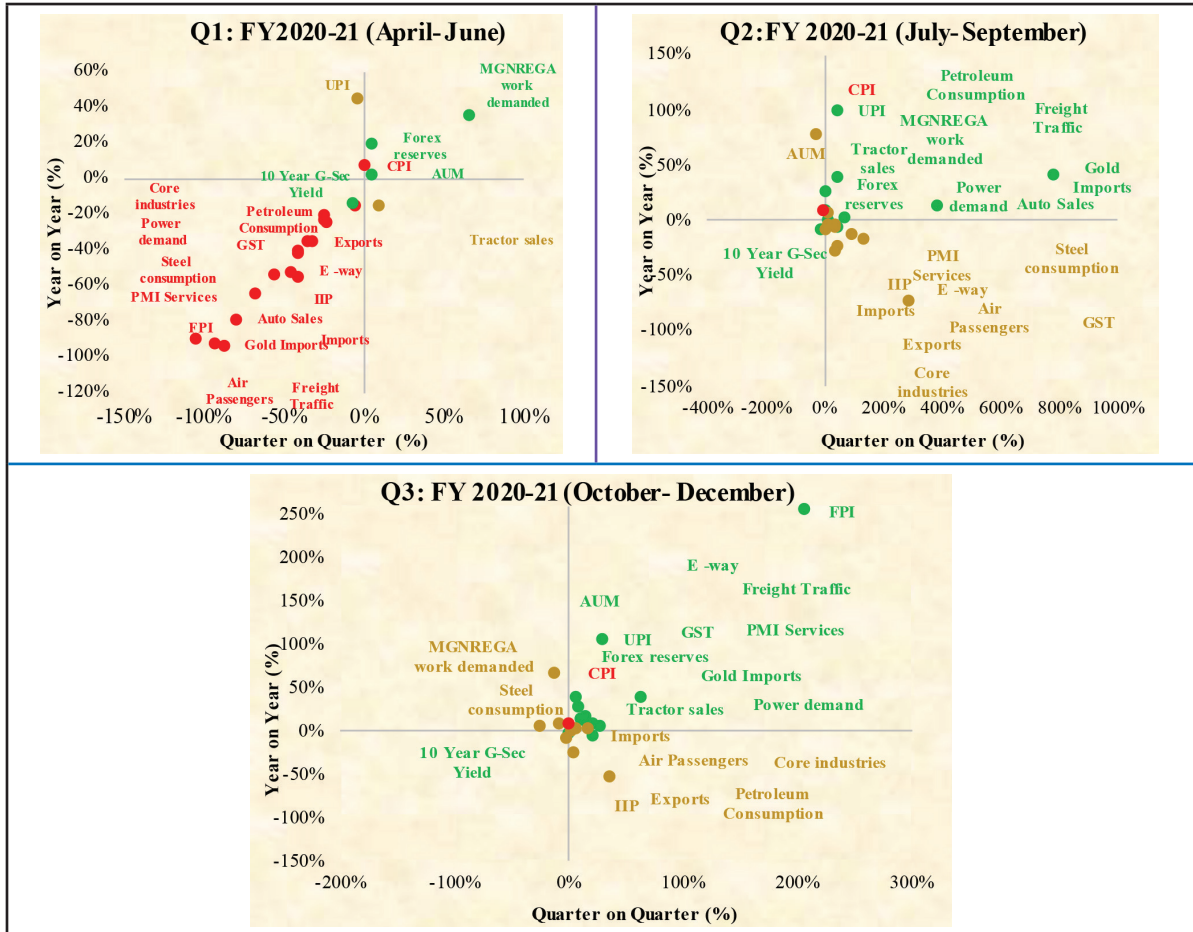
1.25 सरकार और RBI द्वारा प्रदान की गई असाधारण मौद्रिक और राजकोषीय सहायता के पीछे वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के कोविड-19 महामारी प्रेरित अभूतपूर्व चढ़ाव से भारत की आर्थिक गतिविधि में तेजी से सुधार हुआ है। क्यू 1, क्यू 2 और क्यू 3 से अधिक उच्च आवृत्ति संकेतकों के समग्र आंदोलन ने क्यू 2 में तेजी से पिकअप और क्यू 3 में पूर्व महामारी के स्तर तक बढ़ते अभिसरण का संकेत दिया। जैसे-जैसे भारत की गतिशीलता और महामारी के रुझान में सुधार हुआ है और, ई-वे बिल, रेल भाड़ा, जीएसटी संग्रह और बिजली की खपत जैसे संकेतक न केवल महामारी के स्तर तक पहुंच गए, बल्कि पिछले वर्ष के स्तरों से भी आगे निकल गए। इस साल विनिर्माण क्षेत्र में भी तेजी देखी गई, बढ़ती डिजिटल बिक्री में ग्रामीण मांग में उछाल और डिजिटल लेनदेन में संरचनात्मक खपत में बदलाव हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामारी का पूर्ण प्रभाव अभी भी अप्रभावित है और भविष्य



में विकास की संभावनाएं इस नीति की गति पर निर्भर होंगी जो आवश्यक नीतिगत धुरी की आवश्यकता को बढ़ाते हुए घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव के जोखिम के साथ है।

चित्र 21: उच्च आवृत्ति संकेतक का आंदोलन

Figure 21: Movement of High Frequency Indicators



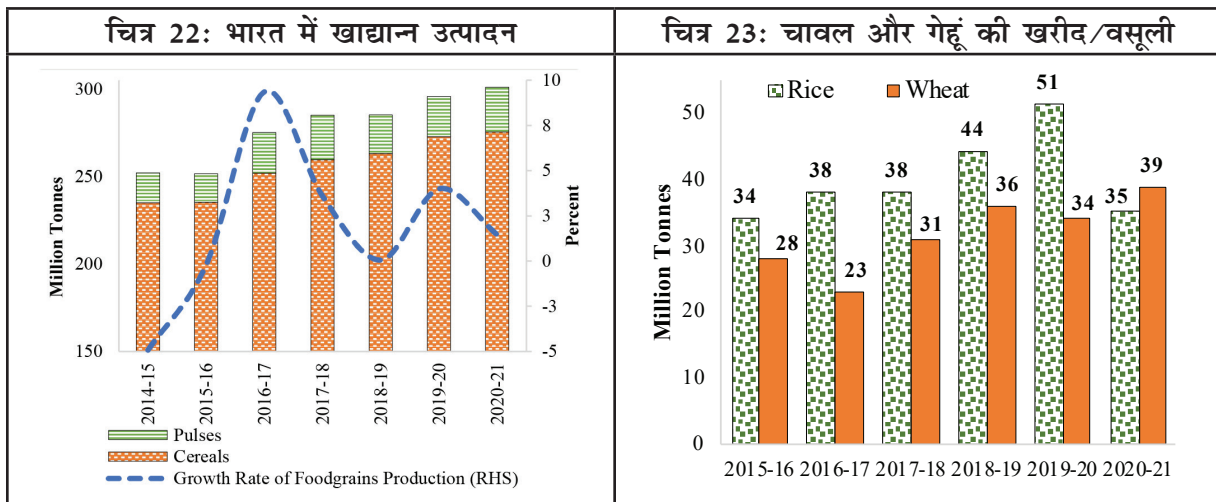
स्रोत: विभिन्न स्रोत से संकलित

नोट: लाल रंग नकारात्मक YoY और QoQ वृद्धि को इंगित करता है; भूरा रंग सकारात्मक YoY या QoQ विकास को इंगित करता है और हरा रंग सकारात्मक YoY और QoQ वृद्धि को इंगित करता है। सीपीआई और जी सेल जैसे सूचक के लिए उपज में ह्रास सकारात्मक रूप में माना जाता है अर्थात् हरा और इसके विपरीत।

### सेक्टरल ट्रेड

1.26 कृषि को 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के झटके को झेलने के लिए सेट किया गया है, Q1 और Q2 दोनों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ। यह एकमात्र क्षेत्र है जिसने 2020-21 के दोनों तिमाहियों में समग्र सकल मूल्य वर्धित (GVA) में सकारात्मक योगदान दिया है। यह इंगित करता है कि रबी की कटाई और खरीफ बुवाई के लिए कृषि गतिविधियां कोविड-प्रेरित तालाबंदी से अप्रभावित थीं। भरपूर खरीफ फसल की उम्मीद को देखते हुए, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2020-21 फसल वर्ष के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो 2019-20 (चित्र 22) में प्राप्त रिकॉर्ड उत्पादन से 1.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष भर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, बफर्स को मजबूती प्रदान करने और आपूर्ति को चैनलाइज

करने में निरंतर वृद्धि करते हुए बुआई स्वस्थ बनी रही (चित्र 23)।



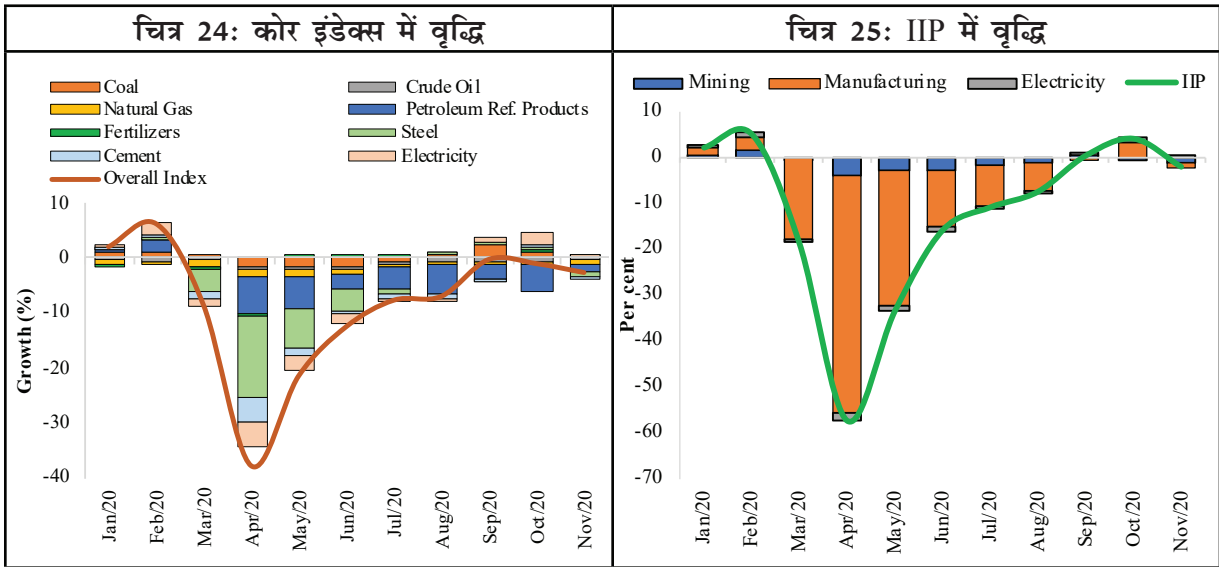
स्रोत: कृषि मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नोट: 2020-21 के लिए उत्पादन के आंकड़े अनुमान हैं।

2020-21 के लिए चावल की खरीद का लक्ष्य 495.37 लाख टन है

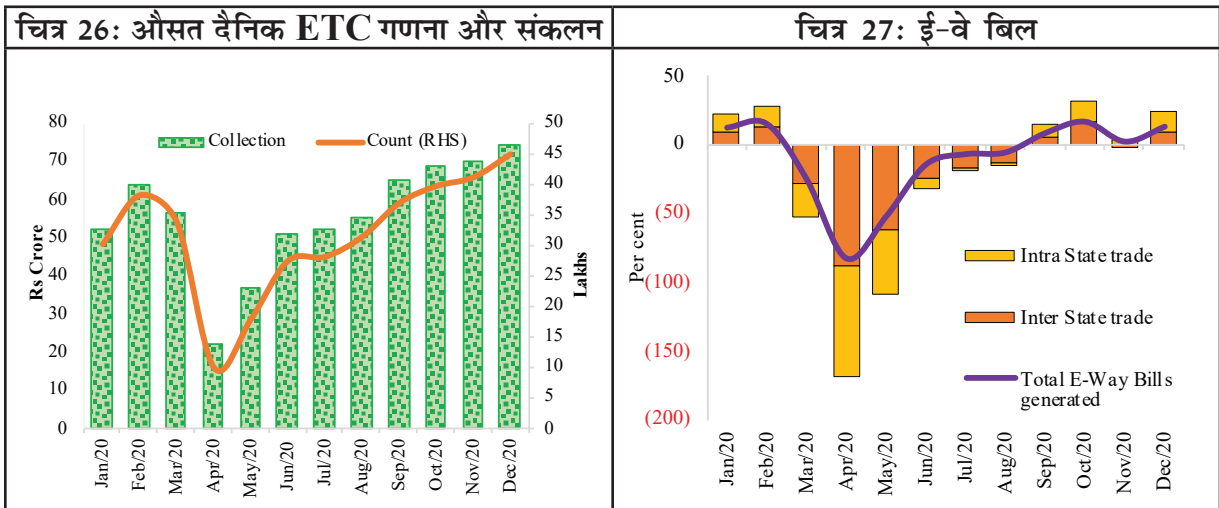
1.27 ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और आधारिक संरचना में सुधार के गुलदस्ते के माध्यम से पिछले वर्षों में ग्रामीण मांग सरकार के जोर से लचीली बनी हुई है। छोटे गांवों, ग्रामीण आवास और स्वच्छता, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आधारिक संरचना का प्रावधान और MGNREGS के माध्यम से टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण से ग्रामीण सड़कों पर पिछले छह वर्षों में फिर से सक्रिय ध्यान केंद्रित किया गया है। इन उपायों को ग्रामीण डिजिटाइजेशन और वित्तीय समावेशन ड्राइव द्वारा प्रबलित किया गया है, जो कोविड-19 के दौरान मांग धक्का उपायों के सुचारू कार्यान्वयन में सहायता करता है।

1.28 औद्योगिक उत्पादन में एक उल्लेखनीय वी-आकार की वसूली वर्ष में देखी गई थी। विनिर्माण प्रतिक्षेप और औद्योगिक मूल्य सामान्य करने के लिए शुरू कर दिया। हालांकि, हेडविंड पर टिका हुआ है। आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक, जो सूचकांक का लगभग 40 प्रतिशत बनाते हैं, ने नवंबर, 2020 में (-) 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि नवंबर, 2019 में 0.7 प्रतिशत और (-) 0.9 प्रतिशत की वृद्धि अक्टूबर, 2020 (चित्र 24)। नतीजतन, IIP, अक्टूबर 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद नवंबर, 2020 (चित्र 25) में संकुचन क्षेत्र में वापस फिसल गया। हालांकि, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2020 में विस्तार क्षेत्र में जारी रहा। निर्माण क्षेत्र में स्टील की खपत को फिर से तेज करने के लिए, अर्थव्यवस्था को खुला रखते हुए रोजगार को बढ़ावा दिया। इस्पात की खपत के लिए एक प्रमुख फॉरवर्ड लिंकेज सेक्टर हाउसिंग मार्केट ने अपने Q1: 2020-21 गत से क्रमिक पुनरुत्थान को देखा। सितंबर, 2020 से बिजली की खपत में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए विद्युत क्षेत्र ने अपनी गति बरकरार रखी।



स्रोत: MoSPI, DPIIT

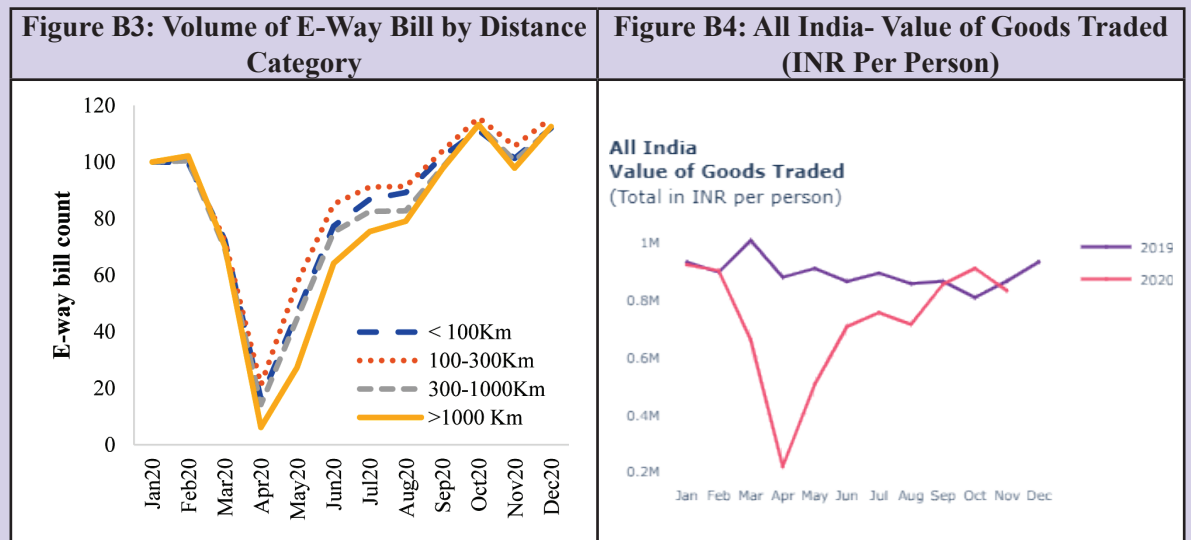
1.29 औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतर तेजी के साथ पुनर्जीवित अंतर और अंतर-राज्य आंदोलन ने अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति में लौटने की शुरुआत की। ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, रेल भाड़ा और पोर्ट कार्गो यातायात न केवल बरामद हुए बल्कि पिछले वर्ष के स्तर को तीसरी तिमाही: 2020-21 में पार कर गए, जबकि रेल यात्री आय और घरेलू विमानन में लगातार गिरावट देखी गई (आंकड़े 26 और 27)। भारतीय सेवा क्षेत्र ने दिसंबर में तीसरे सीधे महीने के लिए पीएमआई सेवा उत्पादन और नए कारोबार के बढ़ने के साथ महामारी से प्रेरित गिरावट से अपनी वसूली को बनाए रखा।



स्रोत: Ministry of Road, Transport and Highways; GSTN

बॉक्स 2: ई-वे बिल

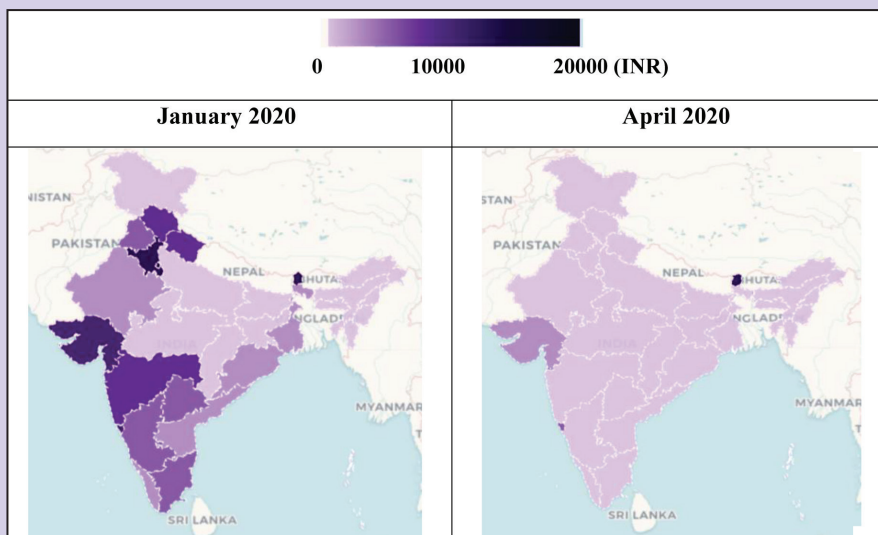
ई-वे बिल राजस्व संकलन, आपूर्ति श्रृंखला सुधार और रसद वृद्धि का एक मजबूत अग्रणी संकेतक है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के साथ, कुल ई-वे बिल ने अप्रैल 2020 में 74 प्रतिशत (YoY) का तीव्र संकुचन देखा। अंतर राज्य का परिमाण और अंतर राज्य व्यापार 89% तक गिर गया। पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में अप्रैल 2020 में क्रमशः 80 प्रतिशत। जबकि अप्रैल 2020 में सभी दूरी श्रेणियों के लिए ई-वे बिल तेजी से अनुबंधित हुए, 1000 किमी से अधिक की दूरी वाले ई-वे बिलों में अधिकतम गिरावट देखी गई (चित्र बी 3)। प्रति व्यक्ति ई-वे बिल के मूल्य में समान गिरावट (चित्र बी 4) देखी गई।

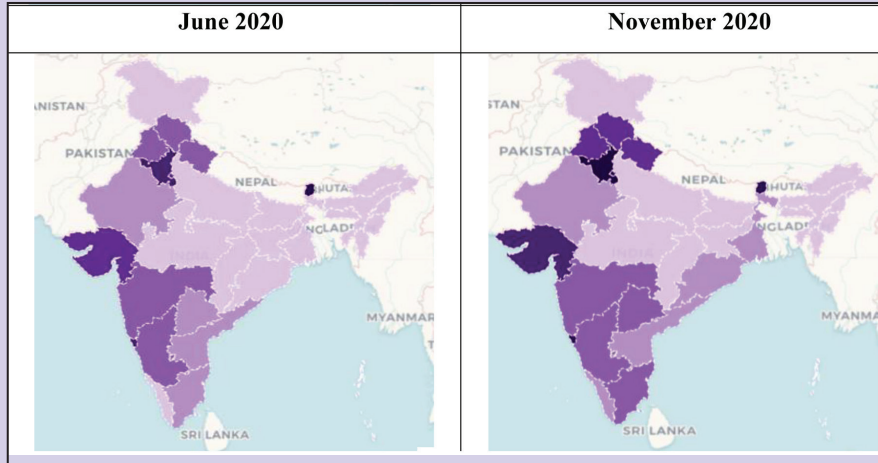


स्रोत: GSTN

नोट: सभी मूल्य जनवरी 2020 में 100 तक सामान्य हो गए।

प्रतिबंधों के क्रमिक रियायत के साथ, ई-वे बिल कुल मूल्यांकन योग्य मूल्य के संदर्भ में उत्पन्न हुए हैं और प्रति व्यक्ति प्राप्त होने वाले मूल्य में तेजी आई है और सितंबर 2020 (चित्र B5) में पिछले वर्ष के स्तर को पार करने में लगातार सुधार हुआ है। व्यापार की आयतन, दोनों इंटर और इंट्रा भी सितंबर 2020 तक पिछले वर्ष के स्तर पर वापस आ गए। उत्पन्न कुल ई-वे बिल के आयतन और मूल्य दोनों ने क्रमशः दिसंबर 2020 में 12.3 प्रतिशत और 17.5 प्रतिशत की दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ मजबूत गति प्राप्त की है।





युगल-वार राज्य व्यापार डेटा का उपयोग करके एक प्रतिगमन विश्लेषण का अनुमान है कि अंतर-राज्य व्यापार में लॉकडाउन के दौरान औसतन 36-39 प्रतिशत की गिरावट आई थी और सितंबर 2020 में पूरी तरह से ठीक हो गई। विश्लेषण से पता चलता है कि अंतर-राज्य की सीमाओं का व्यापार पर कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। अंतर-राज्य की सीमाएं लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण के दौरान एक बाधा हो सकती हैं, लेकिन बाद की अवधि में नहीं।

$$\log(\text{trade})_{ij,t} = a + b1 * \log(\text{distance}) + b2 * D(\text{Border}) + b3 * D(\text{COVID})_t + e_{ij,t}$$

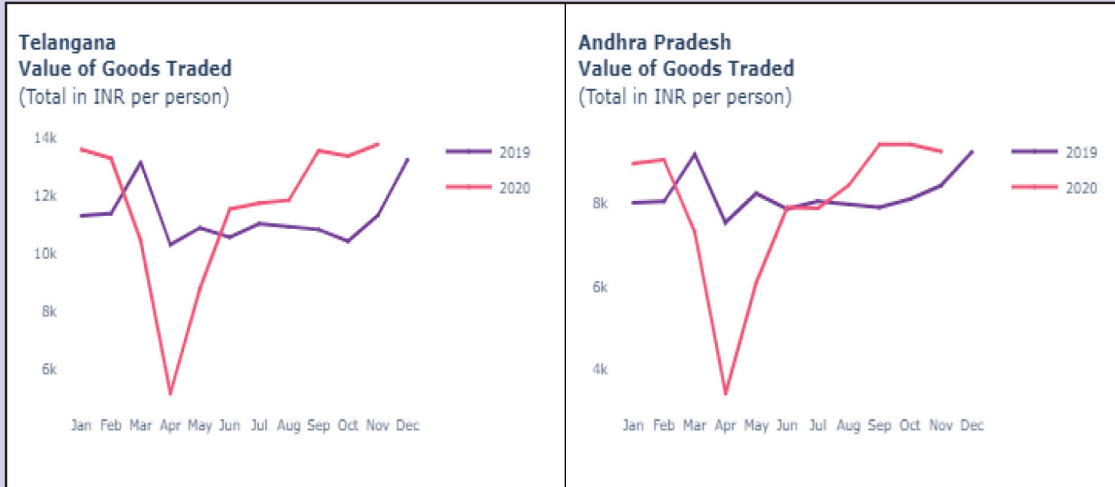
Log (Pairwise inter-state trade)			
	(1)	(2)	(3)
Log (distance)	-1.436*** (0.014)	-1.407*** (0.016)	-1.402*** (0.021)
D(Border)	0.333*** (0.026)	0.352*** (0.029)	0.361*** (0.038)
D(COVID)		-0.360*** (0.014)	-0.389*** (0.019)
Period	Jan 2019-Mar 2020	Nov 2019-Nov 2020	Dec 2019- Jun 2020
Observations	13020	12090	7440
R-Squared	0.929	0.916	0.908

D(COVID)=1 for March-August 2020 \*\*\*p<0.01

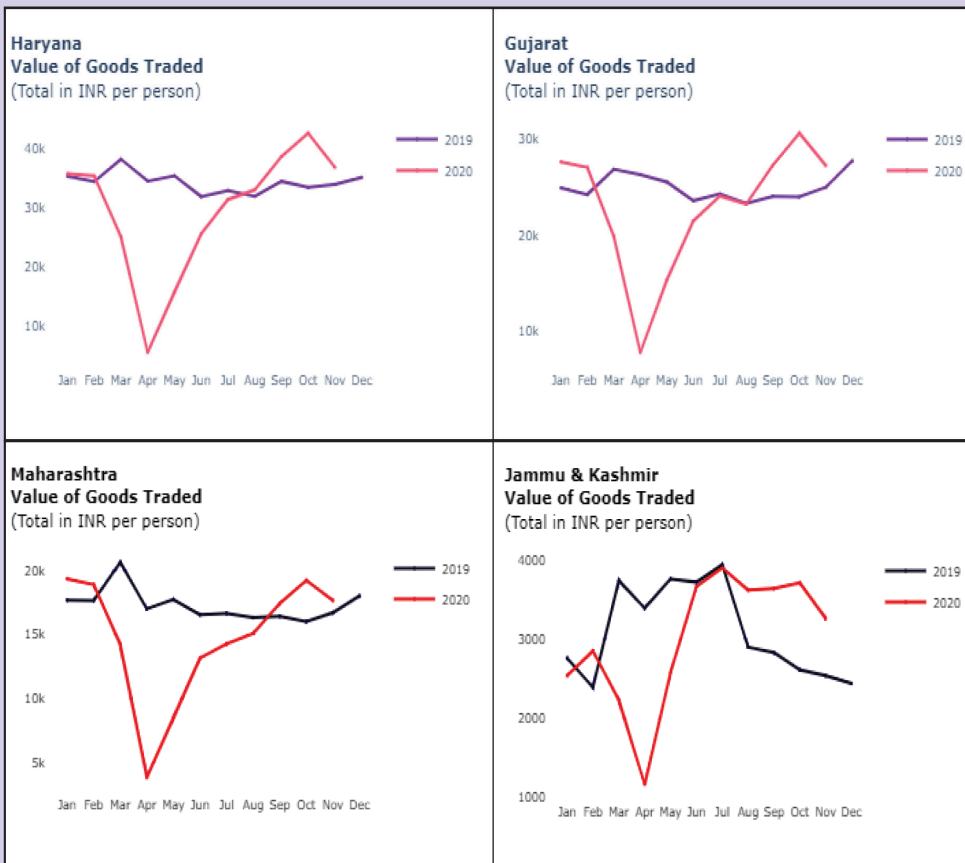
D(Border): Dummy variable which takes the value 1 if the pair of States shares borders

The V-shaped recovery in revenue collections was quite quick in states (Figure B6) such as Telangana and Andhra Pradesh with value of E-way bills per person reaching previous year levels in June. On the other hand, states like Haryana and Gujarat witnessed recovery a month later in July while Maharashtra, a key COVID-19 hotspot and the biggest contributor to India’s GDP witnessed a recovery August onwards.

**Figure B6: State-wise Value of Goods Traded Per Person**



Source: Data from GSTN curated from public platform Indiapulse@ISB

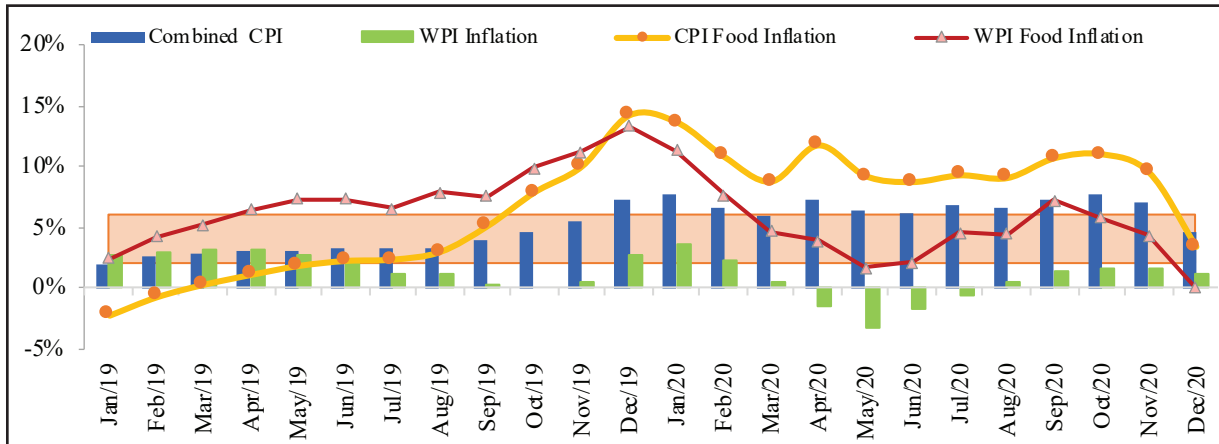


Source: Data from GSTN curated from public platform Indiapulse@ISB



1.30 उच्च खाद्य कीमतें 2020 में मुद्रास्फीति का एक प्रमुख चालक बनी रहीं। हालांकि, दिसंबर, 2020 में मुद्रास्फीति RBI की लक्ष्य सीमा में  $4\pm 2$  प्रतिशत तक गिरकर 6.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष पर 4.6 प्रतिशत तक पहुंच गई। नवंबर में (चित्र 28)। यह खाद्य कीमतों में भारी गिरावट से प्रेरित था, विशेष रूप से सब्जियों, अनाज और प्रोटीन उत्पादों और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण। Q1: 2020-21 के बाद से लगातार छह महीने तक बढ़त के बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर में क्रमिक रूप से कम हो गई। हालांकि, ईंधन की मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण चिपचिपी रही। मुख्य मुद्रास्फीति सालाना आधार पर बढ़ी लेकिन पिछले महीने की तुलना में कम रही।

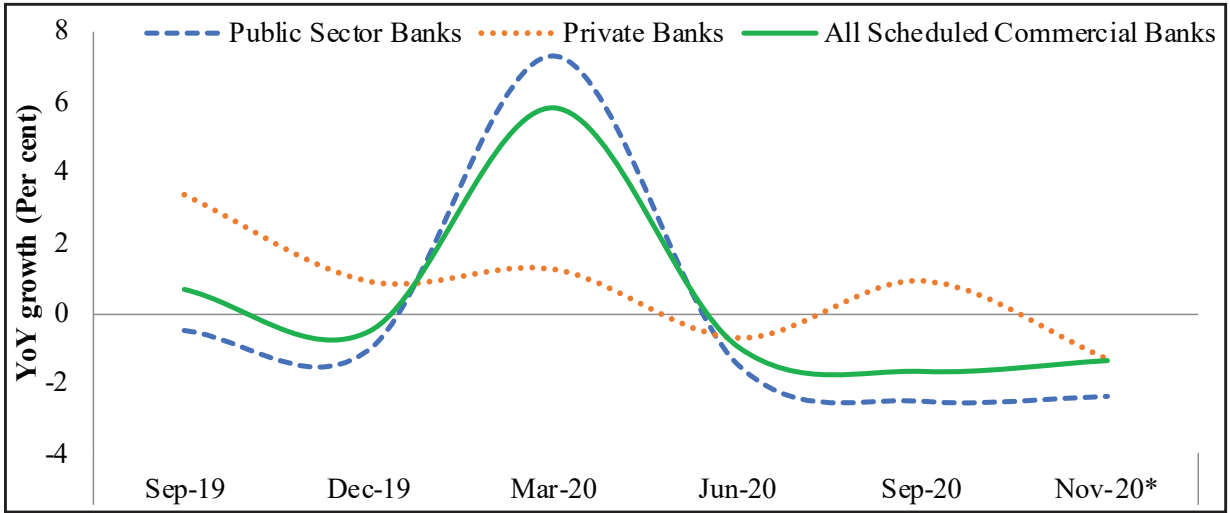
चित्र 28: मुद्रास्फीति



स्रोत: MOSPI

1.31 जोखिम से बचने और मौन ऋण जोखिम (चित्र 29) के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ऋण की स्थिति बनी रही। अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान थोक बैंक ऋण की रूपरेखा ने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों में इस प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। जबकि समग्र बैंक ऋण वृद्धि और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण धीरे-धीरे अपने अप्रैल के चढ़ाव से क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत तक पहुंच गया, क्रमशः 1 जनवरी को, यह पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में सुस्त बना रहा। अक्टूबर 2020 में कृषि के क्षेत्र में तैनाती, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वृद्धि में अक्टूबर 2019 में 7.1 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत की तेजी आई है। अक्टूबर 2020 में निर्माण, व्यापार और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में लचीला ऋण प्रवाह देखा गया, जबकि बैंक मौन रहे। विनिर्माण क्षेत्र के लिए। अक्टूबर 2019 में अक्टूबर 2019 में 5.5 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 6.5 फीसदी की रफ्तार से सर्विस सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ हुई। जबकि पर्सनल लोन में अक्टूबर 2020 में 9.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले 1 चमतण<sup>2</sup> फीसदी ग्रोथ के साथ वाहन लोन जारी रहा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अक्टूबर 2020 में 8.4 प्रतिशत की त्वरित वृद्धि दर्ज करते हुए अक्टूबर 2019 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र 29: शोक बैंक ऋण में वृद्धि



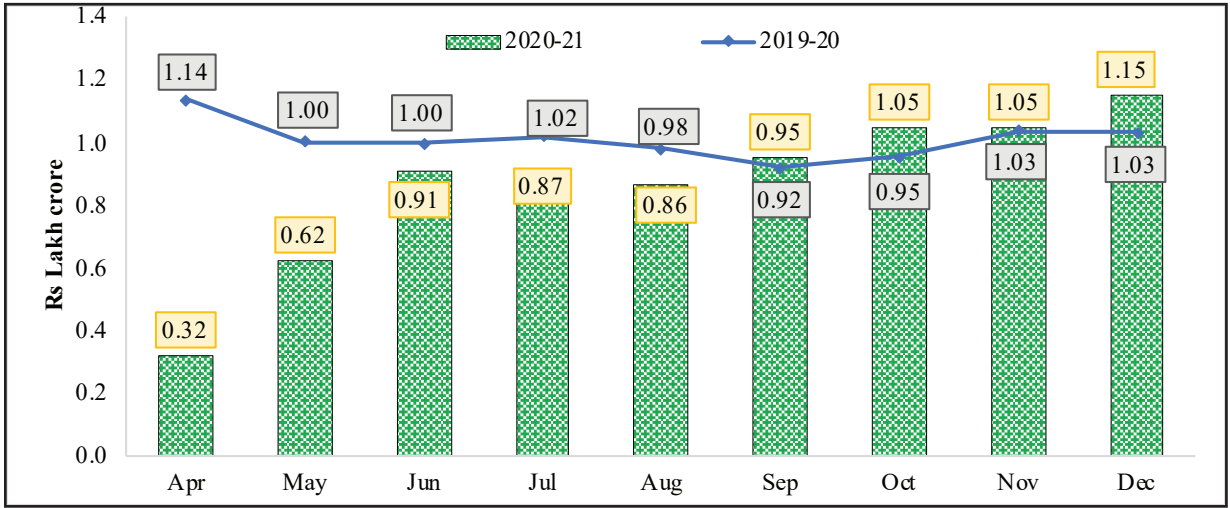
स्रोत: RBI

नोट: \* सितंबर 2020 तक विकास

1.32 गैर-बैंक वित्तपोषण पक्ष पर, म्यूचुअल फंडों के प्रबंधन (AUM) के तहत संपत्ति अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 17.73 प्रतिशत बढ़ी। इन फंडों ने ऋण बाजारों में तरलता की कमी के बीच वर्ष की पहली तिमाही के दौरान आक्रामक मोचन दबावों का सामना किया। हालांकि, म्यूचुअल फंड के लिए RBI की विशेष तरलता खिड़की ने उन्हें बनाए रखने में मदद की। RBI के तरलता बढ़ाने के उपायों ने वाणिज्यिक पत्र (CP) जारी करने और फैंले हुए ढील को बढ़ावा दिया। दिसंबर 2020 में, CP जारी करने में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो नवंबर 2020 में लाख 1.21 लाख करोड़ की तुलना में 1.88 लाख करोड़ तक पहुंच गई। CP के प्रभावी भारत औसत यील्ड दिसंबर 2020 में 3.6 प्रतिशत तक पहुंचने में आसानी रही। म्यूचुअल फंड NBFCs की हिस्सेदारी, IL & FS प्रकरण को काफी हद तक कम करने के बाद, नवंबर 2020 में मार्च 2020 से लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

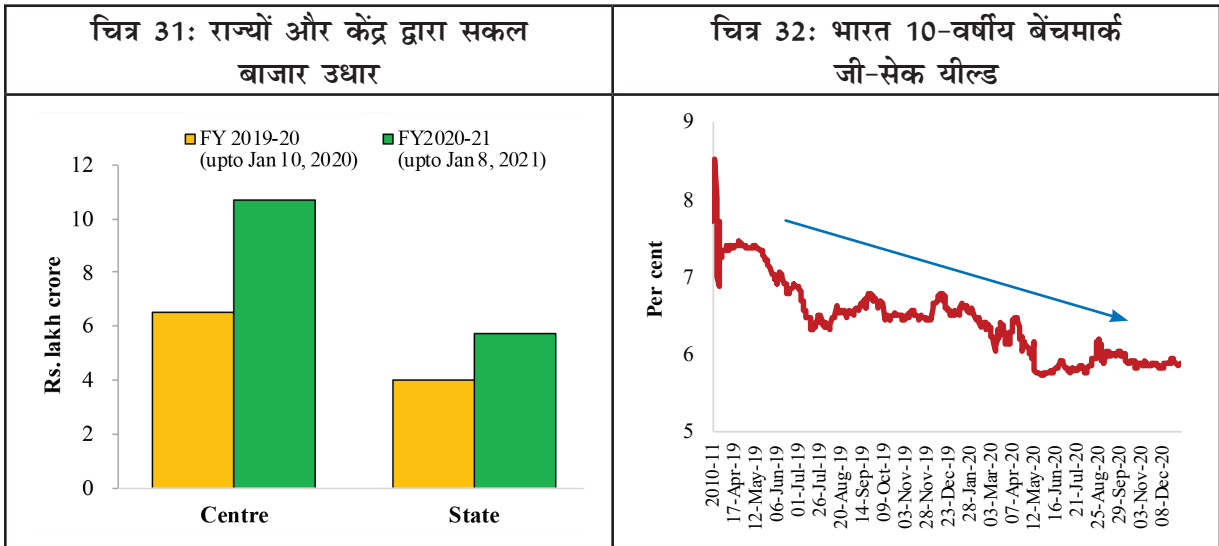
1.33 राजकोषीय अंकगणित सरकारी राजस्व और उच्च व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित हुआ, क्योंकि सरकार ने अनलॉक चरण के दौरान खर्च बढ़ाया। अप्रैल-दिसंबर 2020 (फ्लैश अनुमान) के दौरान, केंद्र सरकार की कुल गैर-ऋण प्राप्तियों में 4.7 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, सकल जीएसटी संकलन (केंद्र प्लस राज्यों) ने अक्टूबर के बाद से 3 महीने के लिए 1 लाख करोड़ का आंकड़ा लगातार पार किया, जिससे सरकार की राजस्व स्थिति (चित्र 30) के लिए बहुत आवश्यक सहायता मिली। हालांकि, राज्यों के अग्रभाग पर, अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां, 13.7 प्रतिशत से संकुचित हैं। केंद्र सरकार के कुल व्यय में अप्रैल-दिसंबर 2020 (फ्लैश अनुमान) के दौरान 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें पूंजीगत व्यय में 24.1 प्रतिशत और राजस्व व्यय में साल दर साल 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, राज्यों ने अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान साल-दर-साल 4.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल व्यय में कमी देखी। राज्यों के राजस्व व्यय में इस अवधि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई, लेकिन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय में अक्टूबर 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई लगातार गिरावट के आठ महीने बाद।

चित्र 30: 2020-21 के दौरान जीएसटी संकलन में रुझान



स्रोत: राजस्व विभाग

1.34 इस वर्ष में देखी गई महामारी के नेतृत्व वाली रसीद-व्यय कील को मुख्य रूप से अतिरिक्त बाजार उधार के माध्यम से दिया गया है, जैसा कि केंद्र द्वारा घोषित संशोधित उधार कैलेंडर में प्रदर्शित किया गया है और राज्यों को दी गई उच्च बाजार उधार सीमाएं हैं। 8 जनवरी 2021 को, केंद्र सरकार का सकल बाजार वित्त वर्ष 2015-21 के लिए उधार लेने से 10.72 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि राज्य सरकारों ने 5.71 लाख करोड़ जुटाए हैं। जबकि केंद्र का उधार पिछले वर्ष की इसी अवधि में जुटाई गई राशि से 65 प्रतिशत अधिक है, राज्य सरकारों ने 41 प्रतिशत (चित्र 31) का एक कदम देखा है। चूंकि कोविड-19 के प्रकोप ने विकास और राजस्व को प्रभावित किया है, उधार का एक महत्वपूर्ण पैमाना अर्थव्यवस्था में उच्च सार्वजनिक व्यय स्तर को बनाए रखने के माध्यम से निरंतर राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रदर्शन है।



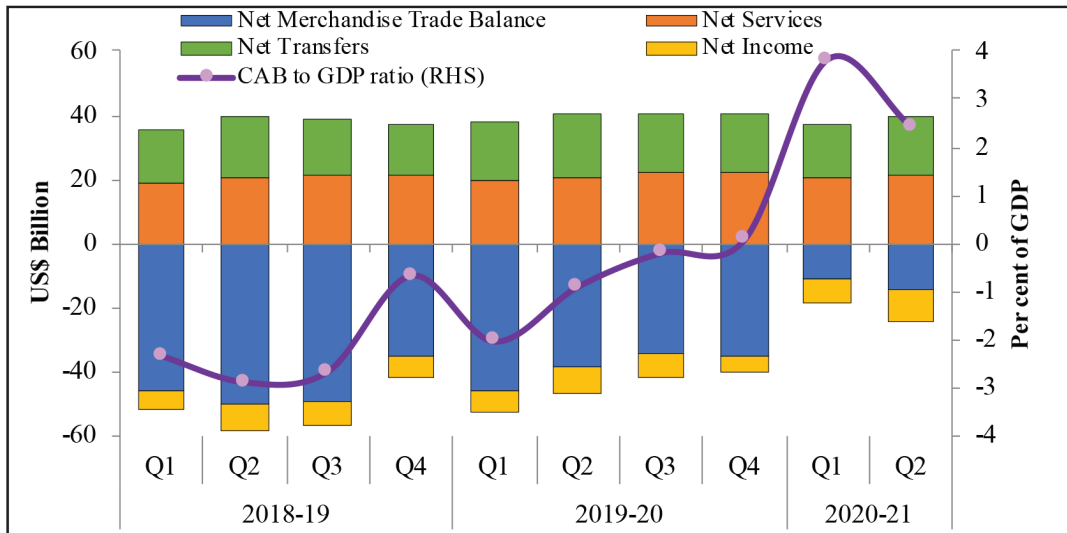
स्रोत: RBI

1.35 सरकार और आरबीआई ने तरलता समर्थन उपायों, तरीकों और साधनों की सीमा में वृद्धि और समेकित

सिंकिंग फंड (CSF) से निकासी को नियंत्रित करने वाले नियमों में ढील दी और बांड बाजारों को सरकारी उधारों के बढ़ते दबाव को अवशोषित करने में सक्षम बनाया और अपनी उछाल में जोड़ा। अधिशेष प्रणालीगत तरलता 10 साल के जी-सेक उपज में नरमी और AAA कॉर्पोरेट बांड पैदावार (चित्र 32) के साथ प्रसार को कम करना सुनिश्चित करती है। AAA के 3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड का औसत प्रसार मई 2020 में 171 बीपीएस से घटकर दिसंबर 2020 में 22 बीपीएस हो गया। एए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड पर फैलता है इसी अवधि के दौरान 131 बीपीएस (243 bps से 113 bps तक) के दौरान काफी मध्यम बीपीएस) और 60 बीपीएस (क्रमशः 177 bps से 117 bps तक) प्रत्येक 3-वर्ष और 5- वर्ष के बांड के लिए क्रमशः।

1.36 बाहरी क्षेत्र ने इन अनिश्चित समय में भारत को एक प्रभावी गुंजाइश प्रदान की। घरेलू और वैश्विक मांग और आपूर्ति में रुकावट के कारण, भारत का व्यापारिक निर्यात 2020-21 की पहली छमाही में 21.2 प्रतिशत घट गया, जबकि संकुचन 39.7 प्रतिशत आयात के लिए अधिक गंभीर था। हालांकि, निर्यात धीरे-धीरे पुनर्जीवित हो गई क्योंकि संकुचन की दर Q3: 2020-21 में 4.6 प्रतिशत तक घट गई, गैर-तेल निर्यात में तिमाही के दौरान 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था के क्रमिक अनलॉकिंग के साथ, आयात में गिरावट भी Q3: 2020-21 के दौरान 5.6 प्रतिशत हो गई है। जबकि व्यापार घाटा अप्रैल-सितंबर 2020-21 में 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित हो गया, जो एक साल पहले 88.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यह इस वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान यूएस \$ 34.3 बिलियन रहा, जो इसी तिमाही में यूएस \$ 37.1 बिलियन से कम था। पिछले साल भारत ने चालू वर्ष की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत का अधिशेष दर्ज किया जो मोटे तौर पर मजबूत सेवाओं के निर्यात (चित्र 33) द्वारा समर्थित है। जबकि बाहरी मांग के सामान्यीकरण की संभावनाएं चल रही हैं, इसकी गति वैश्विक कोविड-19 के दृष्टिकोण और दुनिया भर में टीकाकरण के सफल रोलआउट पर आकस्मिक है।

चित्र 33: भारत के चालू खाते की शेष राशि की संरचना



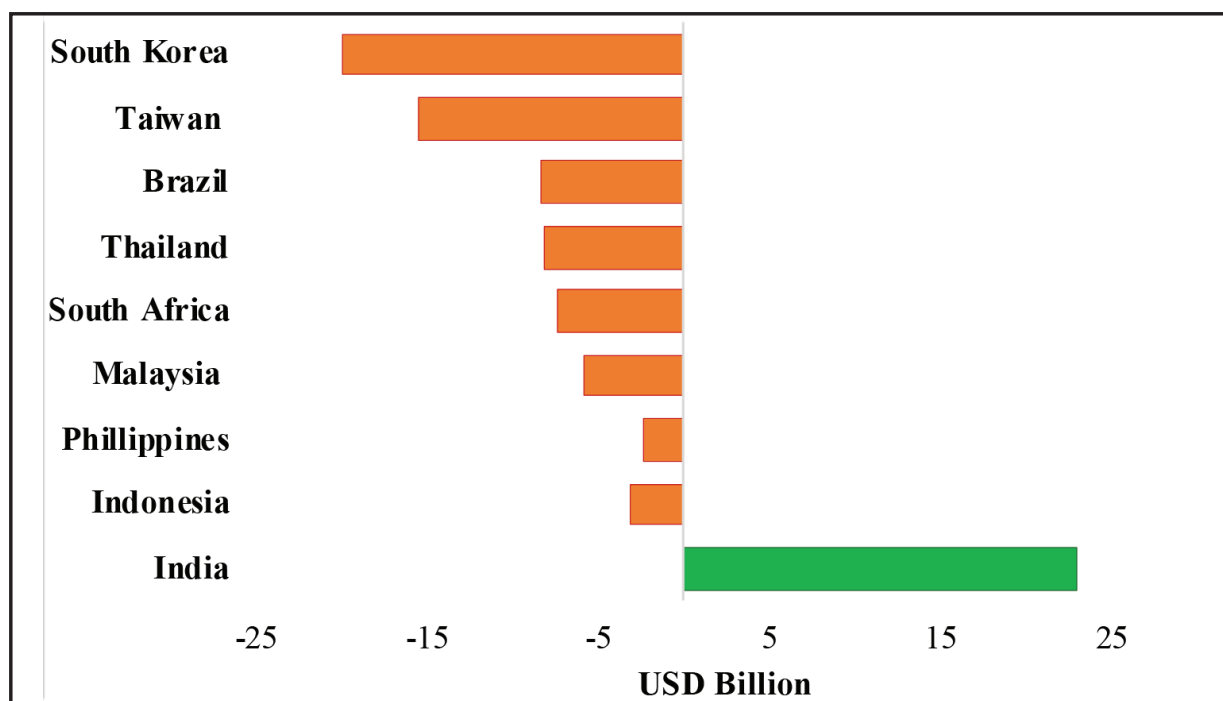
स्रोत: RBI

1.37 भारत वित्त वर्ष 2020-21 में पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी और तेजी से रिक्वरी की संभावनाओं के बीच वैश्विक परिसंपत्ति बदलावों के बीच FDI ने डाला। मार्च 2020 में एक बेजोड़ वैश्विक पोर्टफोलियो निवेशक सेलऑफ के बाद, FPI प्रवाह की वृद्धि दर जून में देखी गई थी, जिसमें वैश्विक मौद्रिक सहजता और राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों के बीच जोखिम भूख की वापसी, पैदावार के लिए

नए सिरे से खोज और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के संकेत थे। नेट FPI इनफ्लो ने नवंबर 2020 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मासिक उच्च स्तर दर्ज किया। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान इक्विटी में 30.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह देखा गया, जो पिछले वर्ष के मूल्य से पांच गुना था-भारत उभरते बाजारों में एकमात्र देश था। 2020 में इक्विटी FII प्रवाह प्राप्त करें (चित्र 34)। इन इनफ्लो के परिणामस्वरूप, बंबई सेंसेक्स और निफ्टी ने भारत के बाजार-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार 100 प्रतिशत के पार कर दिया। हालांकि, यह वित्तीय बाजारों और वास्तविक क्षेत्र के बीच के संबंध में चिंताओं को बढ़ाता है।

चित्र 34: भारत में FII से इक्विटी इनफ्लो

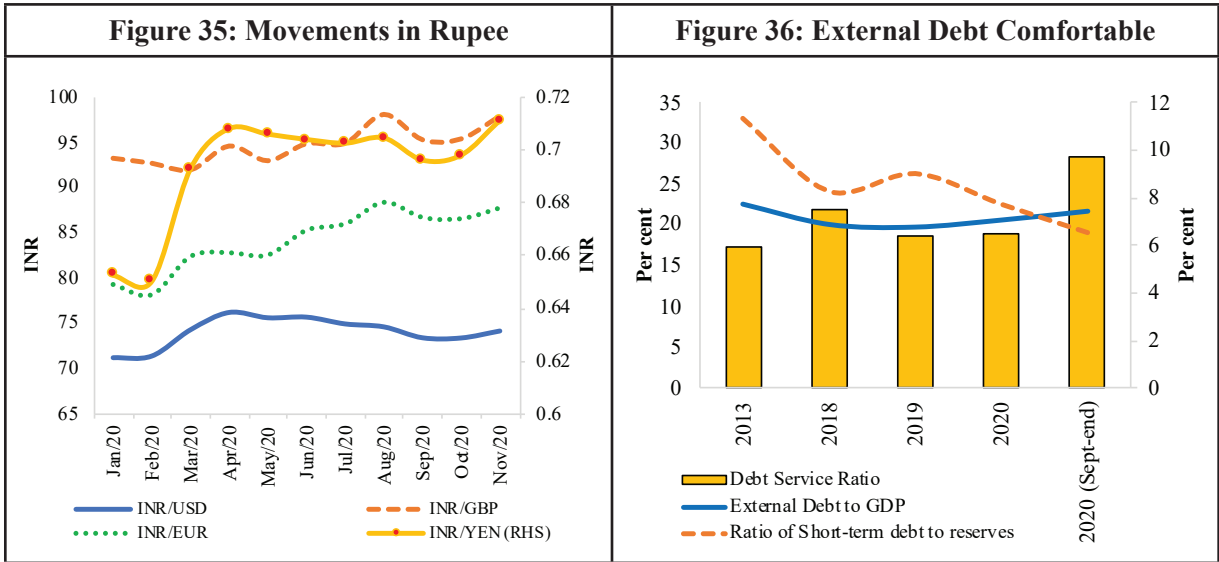
चित्र 34: भारत में थ्ये से इक्विटी इनफ्लो



स्रोत: Bloomberg

1.38 मजबूत पूंजी के साथ-साथ जून 2020 के अंत से भारतीय रुपये की सराहना करते हुए कमजोर डॉलर का प्रवाह बढ़ा। हालांकि, विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की सराहना सीमित है (चित्र 35) की तुलना में सराहना की प्रवृत्ति को सीमित कर दिया। सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि के साथ संयुक्त, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 18 जनवरी से अधिक आयात को कवर करते हुए 8 जनवरी, 2020 तक 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर चढ़ गया। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात, जिसमें मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बाहरी ऋण शामिल हैं, सितंबर -2020 के अंत में मार्च 2010 के अंत में 20.6 प्रतिशत की तुलना में 21.6 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कुल और अल्पकालिक ऋण (मूल और अवशिष्ट) में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात बेहतर हुआ भंडार (चित्र 36) में बड़े आकार के अभिवृद्धि के कारण। हालांकि, कम वर्तमान प्राप्तियों, ऋण सेवा अनुपात (मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान) को दर्शाते हुए, अंत में सितंबर 2020 तक 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ मार्च 2020 के अंत में 6.5 प्रतिशत तक बढ़ गया।

चित्र 35: रुपये में आंदोलन



Source: RBI

1.39 कुल मिलाकर, भारत पूर्व-महामारी स्तरों तक वी-आकार की वसूली के लिए रास्ते पर है। अर्थव्यवस्था को रणनीतिक रूप से विकसित मैक्रो-आर्थिक नीतियों और मजबूत बुनियादी बातों द्वारा समर्थित किया गया था। स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों मोर्चे पर समन्वित नीति प्रतिक्रिया ने भारत को लचीलापन के साथ झटके का सामना करने में मदद की।

**बॉक्स 3: GVA, श्रम बाजार और राजकोषीय स्थिति पर कोविड-19 का प्रभाव: एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य**

कोविड-19 स्वास्थ्य सदमे का भौगोलिक फैलाव राज्यों की पहले से मौजूद आर्थिक कमजोरियों के साथ जुड़ा हुआ है। इस भंगुरता की व्याख्या तीन मोर्चों पर की जा सकती है- जीविए की भंगुरता, श्रम बाजार की भंगुरता और राजकोषीय भंगुरता। उच्चतम उत्पादन में योगदान देने वाला राज्य और देश का कोविड-19 उपरिकेंद्र यानी महाराष्ट्र संपर्क-संवेदनशील सेवा क्षेत्र के झटके से जूझ रहा है (इसका 56% उत्पादन उस क्षेत्र से आ रहा है) और श्रम बाजार के तनाव ने देश के स्तर पर MSMEs के उच्च प्रतिशत में हिस्सेदारी दी। जबकि तमिलनाडु और केरल निर्माण क्षेत्र के झटके के लिए सबसे अधिक भंगुर हैं, एक विनिर्माण मंदी गुजरात और जम्मू और कश्मीर की आर्थिक वसूली के लिए जोखिम देती है। हालांकि, पंजाब अपेक्ष. कृत लचीले कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है, लेकिन सेवा क्षेत्र में गंभीर अनौपचारिक श्रम झटके महसूस होने की उम्मीद है। अनौपचारिक क्षेत्र के झटके वाली सेवाएं दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों को भी असुरक्षित बनाती हैं। हालांकि, दिल्ली की आरामदायक राजकोषीय स्थिति, जो प्रमुख कोविड-19 हॉटस्पॉट में से एक है, स्वास्थ्य को झटका देने के लिए कुशन प्रदान करती है। देश के एक अग्रणी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माण संबंधी अनौपचारिक क्षेत्र के झटकों की सर्वव्यापकता सबसे गंभीर है। जबकि बिहार की आर्थिक नाजुकता इसकी चुनौतीपूर्ण राजकोषीय स्थिति के कारण है, इस प्रमुख आउट-माइग्रेशन राज्य की पुनर्प्राप्ति संभावनाएं कोविड-19 से प्रेरित रिवर्स माइग्रेशन से उभरती हुई ग्रामीण मांग को धक्का देती हैं।



टेबल बी1: कोविड-19 के प्रभाव में अंतर-राज्य विविधता की तीव्रता

	GVA झटका तीव्रता (Measured as share in GSVA)					रोजगार झटका तीव्रता	MSMEs का प्रतिशत हिस्सा	Fiscal shock Intensity	कोविड-19	
	कृषि	खनन	विनिर्माण	निर्माण	सेवाओं	गैर-कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा		सकल राजकोषीय घाटा GDP के %	मामलों की पुष्टि (लाख)	मौतें ('000)
	FY 2019-20					FY 2018-19		FY 2015-16	FY 2019-20 (RE)	Jan
आंध्र प्रदेश	30.9	3.5	10.8	8.5	43.5	50.5	5.3	4.2	8.9	7.1
असम	16.6	14.0	16.3	9.7	41.1	31.1	1.9	3.1	2.2	1.1
बिहार	18.7	0.9	8.7	10.0	60.2	17.0	5.4	9.5	2.6	1.4
छत्तीसगढ़	16.8	11.7	15.3	10.1	37.0	38.3	1.3	6.4	2.9	3.5
गुजरात	12.6	4.5	38.0	5.6	35.9	42.4	5.2	2.1	2.5	4.4
हरियाणा	16.6	0.2	23.8	7.7	50.6	46.9	1.5	2.8	2.7	3.0
हिमाचल प्रदेश	12.6	0.4	30.9	8.5	40.5	29.7	0.6	6.4	0.6	1.0
जम्मू और कश्मीर	15.0	0.2	9.4	8.3	57.1	35.8	1.1		1.2	1.9
झारखंड	12.6	8.9	22.5	8.8	45.8	38.7	2.5	2.4	1.2	1.0
कर्नाटक	8.7	0.7	18.7	6.1	64.4	28.0	6.0	2.3	9.3	12.2
केरल	8.8	0.5	13.2	13.7	62.6	33.4	3.8	3.0	8.4	3.4
मध्य प्रदेश	31.8	3.1	11.7	8.6	41.0	45.2	4.2	3.6	2.5	3.7
महाराष्ट्र	9.4	3.7	23.0	5.7	55.9	29.7	7.5	2.1	19.8	50.3
ओडिशा	14.1	11.8	22.3	7.5	41.1	40.1	3.1	3.4	3.3	2.0
पंजाब	24.3	0.4	14.5	6.3	50.7	61.9	2.3	3.0	1.7	5.5
राजस्थान	25.2	9.0	12.2	7.7	44.1	53.7	4.2	3.2	3.1	2.7
तमिलनाडु	10.9	0.5	25.1	11.5	51.1	33.8	7.8	3.0	8.3	12.3
तेलंगाना	12.9	3.1	13.0	4.4	65.3	49.5	4.1	2.3	2.9	1.6
उत्तर प्रदेश	20.9	1.7	16.4	10.8	48.7	44.4	14.2	2.8	6.0	8.6
उत्तराखंड	7.9	1.9	40.3	7.9	38.4	31.1	0.7	2.2	0.9	1.6
पश्चिम बंगाल	19.9	1.2	14.6	8.9	53.3	39.6	14.0		5.6	10.0
अरुणाचल प्रदेश	27.7	3.3	4.1	11.5	44.3	14.3	0.0	4.1	0.2	0.1
चंडीगढ़	0.4	0.0	3.6	4.7	87.9	36.9	0.1		0.2	0.3
दिल्ली	0.4	1.6	5.5	4.6	84.5	52.0	1.5	-0.1	6.3	10.7
गोवा	4.5	2.8	50.8	3.2	31.4	16.2	0.1	5.6	0.5	0.8
मणिपुर	21.2	0.0	2.9	9.1	63.3	7.0	0.3	11.1	0.3	0.4
मेघालय	15.5	3.6	11.1	7.0	60.7	27.0	0.2	3.6	0.1	0.1

मिजोरम	22.8	0.3	0.7	10.3	51.3	2.4	0.1	8.7	0.0	0.0
नागालैंड	25.8	0.2	1.7	7.8	61.7	13.9	0.1	4.9	0.1	0.1
पुदुचेरी	4.1	2.3	28.0	16.9	47.2	27.2	0.2	0.8	0.4	0.6
सिक्किम	7.7	0.1	46.7	4.2	27.6	23.7	0.0	3.7	0.1	0.1
त्रिपुरा	22.1	11.6	4.0	7.6	50.0	14.2	0.3	6.5	0.3	0.4
अखिल भारत	14.6	2.7	17.4	7.8	55.2	39.2	100.0	3.2	105.4	152.1

स्रोत: MOSPI, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19, राज्य के बजट दस्तावेज, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 73 वें दौर 2015-16

नोट: \* गैर-कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिकों को नियमित मजदूरी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सामान्य नौकरी (पीएस + एस) में गैर-कृषि क्षेत्र में बिना लिखित नौकरी के अनुबंध के बिना, प्रत्येक राज्य के लिए किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के बिना, भुगतान छुट्टी के योग्य नहीं है। केन्द्र शासित प्रदेशों जहां वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है, वित्त वर्ष 2018-19 के आंकड़ों को निरूपित किया गया है।

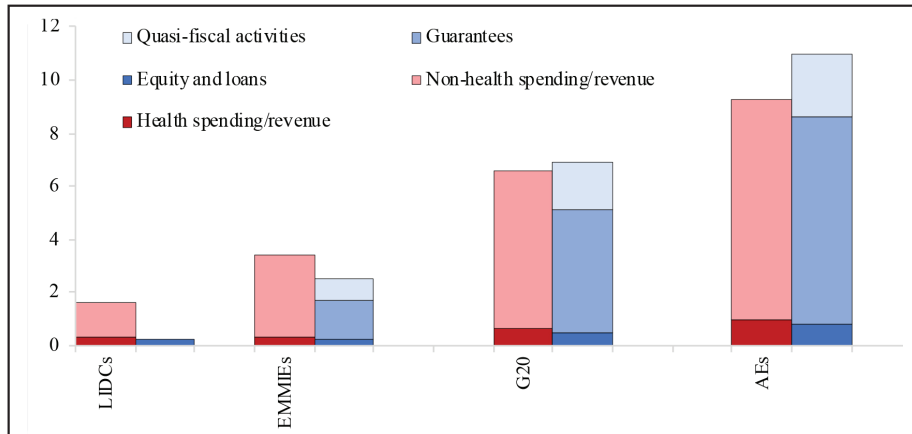
## कोविड -19 को नीति प्रतिक्रिया

### वैश्विक

1.40 वायरस के प्रसार को कम करने में मदद करने के लिए, कई देशों ने आवश्यक उपायों को लागू किया। इनमें स्कूल बंद करना, गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक परिवहन को निलंबित करना, आंदोलन पर प्रतिबंध, सीमा बंद करना और यात्रा प्रतिबंध शामिल हैं। कोविड-19 के घरेलू प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए, कई देशों ने सार्वजनिक सूचना अभियानों, व्यापक-आधारित परीक्षण और संभावित रूप से ज्ञात मामलों से अवगत कराए गए व्यक्तियों के संपर्क ट्रेसिंग के साथ इन सामाजिक गड़बड़ी के उपायों को पूरक बनाया है। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण आपूर्ति-पक्ष बाधाओं को लागू किया, जो कि आमतौर पर व्यापार चक्र में उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से गैर-व्यापार सेवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार को कम करते हैं।

1.41 अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र और समाज के हर पहलू पर महामारी के बेजोड़ प्रभाव ने अधि कारियों से समान अद्वितीय नीति प्रतिक्रिया व्यक्त की। दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने तरलता समर्थन और नियामक परिवर्तनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों को तैनात किया है। वैश्विक स्तर पर 11.7 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक जीडीपी के 12 प्रतिशत के करीब (11 सितंबर, 2020 तक) अभूतपूर्व वित्तीय प्रतिक्रिया ने कमजोर घरों और फर्मों को जीवनदान दिया है। इन उपायों में शामिल हैं, अस्थायी कर कटौती, नकदी और तरह-तरह के स्थानान्तरण, बेरोजगारी लाभ, मजदूरी सब्सिडी, और तरलता समर्थन शामिल हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र (चित्र 37) द्वारा ऋण, गारंटी और इक्विटी इंजेक्शन शामिल हैं।

चित्र 37: दुनिया भर में राजकोषीय सहायता के प्रकार

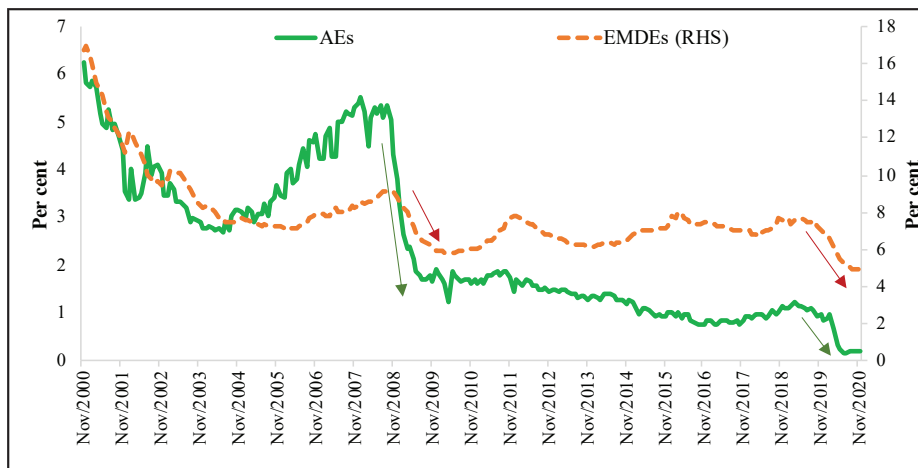


स्रोत: IMF

EMMIEs = उभरते बाजार और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं; जी 20 = बीस का समूह; LIDCs = कम आय वाले विकासशील देश

1.42 दुनिया भर में मौद्रिक अधिकारियों ने गतिविधि का समर्थन करने के लिए अल्पकालिक नीति दरों और आरक्षित आवश्यकताओं में व्यापक-आधारित कटौती के साथ मौद्रिक स्थितियों को आसान बनाया है और वित्तीय बाजारों (चित्र 38) को स्थिर करने के लिए आपातकालीन तरलता सहायता प्रदान की है। दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक दीर्घकालिक परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम (कई EMDEs में पहली बार) के रूप में अपरंपरागत मौद्रिक नीति हस्तक्षेपों में लगे हुए हैं, सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, परिसंपत्ति प्रावधान की आवश्यकताओं में छूट और उधारकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ऋण प्रावधान का समर्थन कर रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित धन के संबंधित इंजेक्शन बांड बाजारों को स्थिर करने, बांड की पैदावार को कम करने, विनिमय दरों पर दबाव डाले बिना इक्विटी की कीमतों को बढ़ाने में प्रभावी रहे हैं।

चित्र 38: वैश्विक नीति दर में रुझान



स्रोत: विश्व बैंक

1.43 कई देशों में गहरे आर्थिक संकुचन और महामारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में अनिश्चितताओं को बढ़ाते हुए, दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को वापस ला सकते हैं। इसलिए, महामारी ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए एक लंबा रास्ता तय किया है।

### भारत की सामरिक बहु-प्रचारित नीति प्रतिक्रिया

1.44 भारत ने महामारी के विघटनकारी प्रभाव को पहचान लिया और देश में प्रसार के निराशाजनक अनुमानों के बीच अपने स्वयं के अनूठे पथ का चार्ट बनाया। यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में मई, 2020 (Klein et al., 2020) के अंत तक 30 करोड़ मामले और कई हजार मौतें होंगी। तेजी से बदलाव और बढ़ती अनिश्चितता के समय, 'जान है तो जहान है' का स्पष्ट उद्देश्य और 'प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने' से सरकार को 'जीवन बनाम आजीविका' की दुविधा का सामना करने में मदद मिली, नीतिगत बदलावों के क्रम को गति दी गयी और विकसित स्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को अनुकूलित किया। भारत ने (i) रोकथाम उपायों से युक्त एक चार-तरफा रिक्तिपूर्व, और सक्रिय रणनीति को अपनाया, जिसमें शामिल हैं (i) रोकथाम के उपाय, (ii) लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता और अनलॉक चरण के दौरान मांग के धक्के पर कैलिब्रेटेड राजकोषीय समर्थन, (iii) वित्तीय उपाय और (iv) कोविड-19 (अध्याय 1, खंड I, आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 का संदर्भ लें) का मुकाबला करने के लिए संरचनात्मक सुधार। नीति की प्रतिक्रिया महामारी के विभिन्न चरणों के अनुरूप थी, लोगों को सफलता प्रदान करने, मांग का समर्थन करने, पूर्व-महामारी के स्तर को ठीक करने और वित्तीय और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विकासशील आवश्यकताओं को अपनाना। एक क्रमिक, सुचारु परिवर्तन को 'जान है तो जहान है' से 'जान भी और जहान भी' के लिए तैयार किया गया था।

1.45 24 मार्च, 2020 को 21 दिनों के लिए एक राष्ट्रव्यापी 'कड़े' लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और बाद में इसे 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया था। ऑक्सफोर्ड सरकार के प्रतिसाद ट्रैकर के अनुसार, भारत सबसे पहले एक सख्त लॉकडाउन (100 के साथ सूचकांक) लागू करने वालों में से था, लॉकडाउन लगाने के समय कुछ मामले होने के बावजूद। लॉकडाउन ने स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया को मजबूत करने, परीक्षण को रैंप करने और सामाजिक दूरी के अभ्यास के प्रति सार्वजनिक जुड़ाव/जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक समय प्रदान किया। महामारी की शुरुआत में, भारत लगभग पूरी तरह से आयातित वेंटिलेटर, पीपीई किट और एन-95 मास्क पर निर्भर था। केंद्र सरकार ने महामारी की प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न चुनौतियों को पहचान लिया और देश भर में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति से अधिक सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया। कोविड-19 मामलों के उचित प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी, (i) हल्के या पूर्व-लक्षण वाले मामलों के लिए अलगाव बेड के साथ कोविड केयर सेंटर; (ii) मध्यम मामलों के लिए ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बेड के साथ समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर (DCHC) और (iii) गंभीर मामलों के लिए ICU बेड के साथ समर्पित कोविड अस्पताल (DCH) को लागू किया गया है। 29 दिसंबर 2020 तक कुल 2,70,710 ऑक्सीजन समर्थित अलगाव बेड, 81,113 आईसीयू बेड (40,627 वेंटिलेटर बेड सहित) और 5,91,496 बेड वाले 12,669 संगरोध केंद्र बनाए गए थे। टेक्सटाइल उद्योग ने पीपीई किट और एन 95 मास्क के उत्पादन को बढ़ा-चढ़ा कर और महामारी को पीपीई किट के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरने और एन 95 मास्क के 32 लाख टुकड़ों के दैनिक उत्पादन तक पहुँचने की महामारी की चुनौती को जन्म दिया।

1.46 भारत सरकार और RBI ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और महामारी की वजह से उत्पन्न होने वाली माँग और आपूर्ति दोनों को कम करने के लिए आवश्यक नियामक सहायता प्रदान करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। प्रदान किए गए नीति समर्थन ने दोनों व्यक्तियों और फर्मों पर लॉकडाउन-प्रेरित संकट के कारण

अपेक्षित गिरावट को कम करने में मदद की। महामारी के लिए भारत सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अन्य देशों से अलग थी, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों और व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए एक तकिया प्रदान करने के उपायों पर पूर्व में ध्यान केंद्रित करने की मांग को चरणबद्ध तरीके से पेश किया गया था। (विशेषकर एमएसएमई)। इसमें दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम, 42 करोड़ व्यक्तियों को सीधे नकद हस्तांतरण, 20 करोड़ से अधिक महिला जन धन खातों, भवन निर्माण और निर्माण श्रमिकों को नकद सहायता, ARD 30,000 करोड़ अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए, अतिरिक्त शामिल थे। पेंशन भुगतान, मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए प्रावधान, MGNREGS के तहत अतिरिक्त आवंटन, साथ ही क्रेडिट के लिए सरकार की गारंटी, वित्तीय समय सीमा को स्थगित करना आदि। जिस गति से भारत महामारी के दौरान गरीब और निशक्त लोगों को वित्तीय सहायता के प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तांतरण पर हस्तक्षेप कर सकता है, वह जे.ए.एम. (जनधन, आधार और मोबाइल) के सावधानीपूर्वक निर्मित सामाजिक संस्थान से इसकी सफलता प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से, देश महामारी के समय बटन के एक क्लिक के माध्यम से करोड़ों खातों में धन हस्तांतरित कर सकता है। इसके अलावा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA) 20 जून, 2020 को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों की अवधि के लिए शुरू किया गया था, ताकि वे अपने गाँवों में लौट आए और मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दे सकें। कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार ने भी रोजगार को बनाए रखने और देनदारियों को पूरा करने में मदद करके तनावग्रस्त क्षेत्रों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS 1.0) की शुरुआत की। तनावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बैंकों और NBFC द्वारा ऋण के लिए आवश्यक क्रेडिट गारंटी की पेशकश करने के लिए योजना (ECLGS 2.0) का दूसरा संस्करण भी लॉन्च किया गया था।

1.47 RBI ने अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति के प्रबंधन के लिए कई पारंपरिक और अपरंपरागत तरलता बढ़ाने के उपाय किए। इन उपायों में, अन्य बातों के अलावा, 6 फरवरी से 4 दिसंबर, 2020 के बीच ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद के माध्यम से ₹2.7 लाख करोड़ से अधिक की टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में दो खरीद नीलामी ओएमओ के माध्यम से 20,000 करोड़।, 'तीन साल तक के टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (TLTROs) के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये, 'फरवरी-मार्च 2020 में लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (LTROs) के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपये, कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में कमी 28 मार्च, 2020 से निवल मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत से बैंकों की आवश्यकता, बैंकिंग प्रणाली में प्राथमिक तरलता में लगभग 1.37 लाख करोड़ की वृद्धि, सीमांत के तहत रातोंरात उधार लेने के लिए बैंकों की सीमा बढ़ा दी। स्थायी सुविधा (MSF), 'म्युचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा और सभी भारत के वित्तीय संस्थानों यानी नाबार्ड, NHB, SIDBI और EXIM बैंक के लिए 75,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा दी। RBI और भारत सरकार द्वारा H1: 2020-21 के दौरान NBFC द्वारा सामना की गई तरलता की बाधाओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय, योग्य NBFC/HFC से अल्पकालिक कागजात खरीदने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) की स्थापना करना था, जो फिर अपनी मौजूदा देनदारियों को बुझाने के लिए आय का उपयोग करें।

1.48 कॉर्पोरेट तनाव में सुधार लाने के लिए, सरकार ने 25 मार्च, 2020 से 25 मार्च 2021 तक या उसके बाद उत्पन्न होने वाली चूक के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 7, 9 और 10 के तहत नई इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने को निलंबित कर दिया। RBI ने भी 1 मार्च से लोन स्थगन की घोषणा की। 2020 से 31 अगस्त 2020 तक एक परिसंपत्ति वर्गीकरण वितरण और कोविड-19 संबंधित

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए विशेष संकल्प ढांचे के किये। उपरोक्त विंडो के तहत लागू की जा सकने वाली रिजॉल्यूशन योजनाओं के तहत, उधारदाताओं को दो साल तक की अतिरिक्त मोहलत देने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, MSME खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जहां 1 मार्च, 2020 तक बैंकों और NBFCs के कुल जोखिम ₹25 करोड़ या उससे कम थे, कुछ शर्तों के अधीन, परिसंपत्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना पुनर्गठन की अनुमति दी गई थी।

1.49 भारत की प्रतिक्रिया यह मानने में अद्वितीय रही है कि महामारी का उत्पादक क्षमता पर दीर्घकालिक विघटनकारी प्रभाव पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन, तदनुसार, व्यक्तियों और फर्मों के अल्पकालिक संकट को दूर करने के लिए कल्याणकारी उपायों के साथ घोषित एक समग्र पैकेज था; और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक संकट को कम करने के लिए संरचनात्मक सुधार। अर्थव्यवस्था के क्रमिक अनलॉकिंग के साथ, प्रोत्साहन उपायों का फोकस उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन, पूंजी व्यय और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में निवेश जैसे पुनरुद्धार उपायों की ओर बढ़ा। महामारी की आवश्यकताओं के अनुसार नीति में बारीक अनुकूलन केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय पर आधारित था। इसलिए, समग्र नीति प्रतिक्रिया का उद्देश्य कोविड के बाद की दुनिया के अवसरों और समस्याओं (तालिका 1) से निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक मुलायम और लचीला बनाना है।

तालिका 1: कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत में नीति पैकेज

उपाय	स्वरूप	नीति उपकरण
रोकथाम के उपाय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रोकथाम और बंद करने की नीति</li> <li>• संचरण की रोकथाम</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्कूल बंद करना</li> <li>• 21 दिनों के लिए पूरा राष्ट्र-व्यापी लॉक-डाउन</li> <li>• यात्रा प्रतिबंध/रोक</li> <li>• सार्वजनिक स्थानों को बंद करना/सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करना</li> <li>• गैर-जरूरी आर्थिक गतिविधियों की कटौती</li> <li>• रेड जोन (हॉट स्पॉट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों की जोखिम रूपरेखा</li> <li>• सामाजिक भेद मानदंड</li> <li>• मास्क का अनिवार्य उपयोग</li> </ul>
राजकोषीय नीति के उपाय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्वास्थ्य</li> <li>• कल्याण</li> <li>• कर उपाय</li> <li>• मांग धक्का</li> <li>• निवेश धक्का</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आपातकालीन स्वास्थ्य कोष (₹. 150 बिलियन)</li> <li>• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना - वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा</li> <li>• MGNREGS के तहत दैनिक वेतन में वृद्धि</li> <li>• गरीब कल्याण रोजगार अभियान - ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका निर्माण</li> <li>• कर और योगदान नीति में परिवर्तन</li> <li>• राज्यों को सहायता, उधार को सुधारों से जोड़ना</li> </ul> <p><b>आत्म निर्भर भारत पैकेज 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MSMEs के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)</li> <li>• MSMEs के लिए निधियों के माध्यम से स्ट्रेस्ड एमएसएमई और इक्विटी इन्फैक्शन के लिए अधीनस्थ ऋण</li> </ul>



उपाय	स्वरूप	नीति उपकरण
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• NBFCs और MFIs की सहायता के लिए आंशिक गारंटी योजना का विस्तार</li> <li>• स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष क्रेडिट सुविधा</li> <li>• DISCOMs के लिए तरलता इंजेक्शन</li> <li>• एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए विशेष तरलता योजना</li> <li>• MUDRA शिशु ऋण के लिए ब्याज सबमिशन</li> <li>• हाउसिंग क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना - MIG</li> <li>• नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी</li> <li>• KCC के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट</li> <li>• एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का निर्माण, पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड</li> <li>• हर्बल खेती को बढ़ावा</li> <li>• मधुमक्खी पालन की पहल</li> <li>• सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि योजना</li> </ul> <p><b>आत्म निर्भर भारत पैकेज 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना</li> <li>• LTC वाउचर योजना</li> <li>• त्यौहार अग्रिम</li> </ul> <p><b>आत्म निर्भर भारत पैकेज 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आत्म निर्भर विनिर्माण के लिए बूस्ट - उत्पादन जुड़े प्रोत्साहन</li> <li>• ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट</li> <li>• कोविड सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान - भारतीय टीका विकास</li> <li>• आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना</li> <li>• औद्योगिक बुनियादी ढांचा, औद्योगिक प्रोत्साहन और घरेलू रक्षा उपकरण</li> <li>• कृषि के लिए समर्थन - उर्वरक सब्सिडी</li> <li>• सभी के लिए आवास - PMAY-U</li> <li>• NIIF डेट PF में इन्फ्रास्ट्रक्चर-इक्विटी जलसेक के लिए बूस्ट</li> <li>• परियोजना निर्यात के लिए बूस्ट - EXIM बैंक के लिए सहायता</li> </ul>
मौद्रिक उपाय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पॉलिसी की दरें</li> <li>• लिक्विडिटी</li> <li>• संपत्ति खरीद</li> <li>• ऋण अधिस्थगन</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेपो और रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 115 और 155 बीपीएस से कम करना।</li> <li>• ओपन मार्केट ऑपरेशन (वडव) के माध्यम से टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन</li> <li>• तीन वर्षों तक के दीर्घकालिक रेपो परिचालन (जस्ज्ते) लक्षित</li> </ul>

उपाय	स्वरूप	नीति उपकरण
		<ul style="list-style-type: none"> <li>बैंकों की सीआरआर आवश्यकता में कमी</li> <li>बैंक की उधारी की सीमा को बढ़ाया</li> <li>कार्यशील पूंजी समर्थन-अवधि ऋण अधिस्थगन, ब्याज का आवर्तन और वित्तपोषण आवश्यकताओं में ढील</li> <li>संवर्धित WMA उधार सीमा और सीएसएफ निकासी नियमों में छूट</li> <li>तनावग्रस्त परिसंपत्ति के अनुपालन में आसानी</li> <li>विचलन, पूंजी बफर और तरलता कवरेज आवश्यकताओं में ढील</li> <li>स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (VRR) के तहत एफपीआई के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को जानें</li> </ul>
मौद्रिक उपाय	<ul style="list-style-type: none"> <li>पॉलिसी की दरें</li> <li>लिक्विडिटी</li> <li>संपत्ति खरीद</li> <li>ऋण अधिस्थगन</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रेपो और रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 115 और 155 बीपीएस से कम करना।</li> <li>ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के माध्यम से टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन</li> <li>तीन वर्षों तक के दीर्घकालिक रेपो परिचालन (TLTROs) लक्षित</li> <li>बैंकों की सीआरआर आवश्यकता में कमी</li> <li>बैंक की उधारी की सीमा को बढ़ाया</li> <li>कार्यशील पूंजी समर्थन-अवधि ऋण अधिस्थगन, ब्याज का आवर्तन और वित्तपोषण आवश्यकताओं में ढील</li> <li>संवर्धित WMA उधार सीमा और सीएसएफ निकासी नियमों में छूट</li> <li>तनावग्रस्त परिसंपत्ति के अनुपालन में आसानी</li> <li>विचलन, पूंजी बफर और तरलता कवरेज आवश्यकताओं में ढील</li> <li>स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (VRR) के तहत एफपीआई के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को जानें</li> </ul>
संरचनात्मक सुधार	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि</li> <li>एमएसएमई</li> <li>श्रम</li> <li>बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)</li> <li>बिजली</li> <li>सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण</li> <li>खनिज क्षेत्र</li> <li>उद्योग</li> <li>अंतरिक्ष</li> <li>रक्षा</li> </ul>	<p><b>कृषि</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020</li> <li>मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 का किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता</li> <li>आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020</li> </ul> <p><b>MSMEs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>नई MSME परिभाषा MSMEs को आकार में बढ़ने और रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाने वाली सभी कंपनियों के लगभग 99% को कवर करती है</li> </ul>

- निर्माण और सेवा डैडले के बीच कृत्रिम अलगाव को हटाना
- श्रम**
- चार श्रम कोडों का अधिनियमन, मजदूरी कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता
- 'एक श्रम रिटर्न, एक लाइसेंस और एक पंजीकरण'
- ओपन

### बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ( BPO )

- दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता (ऍच) दिशानिर्देशों का सरलीकरण। कई आवश्यकताएं, जिन्होंने कंपनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर' नीतियों को अपनाने से रोका।

### बिजली

- टैरिफ नीति सुधार: उपभोक्ताओं को बोझ न करने की अक्षमता, क्रॉस सब्सिडी में प्रगतिशील कमी, खुली पहुंच का समयबद्ध अनुदान आदि।
- संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण

### सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण

- केवल रणनीतिक क्षेत्रों में PSUs
- गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण

### खनिज क्षेत्र

- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन
- एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन शासन का परिचय।

### उद्योग

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (ऍप्) योजना

### अंतरिक्ष

- उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को प्रदान किया जाने वाला स्तरीय खेल का मैदान
- तकनीक-उद्यमियों को दूरस्थ-संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भू-स्थानिक डेटा नीति
- तकनीक

### रक्षा

- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- ऑटोमैटिक रूट के तहत डिफेंस मैनुफैक्चरिंग में एफडीआई की सीमा 49: से बढ़ाकर 7 की जाएगी 4%

		<ul style="list-style-type: none"> <li>निर्माण और सेवा डैडले के बीच कृत्रिम अलगाव को हटाना</li> </ul> <p><b>श्रम</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>चार श्रम कोडों का अधिनियमन, मजदूरी कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता</li> <li>‘एक श्रम रिटर्न, एक लाइसेंस और एक पंजीकरण’</li> <li>ओपन</li> </ul> <p><b>बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ( BPO )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता (ऍच) दिशानिर्देशों का सरलीकरण। कई आवश्यकताएं, जिन्होंने कंपनियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ‘वर्क फ्रॉम एनीवेयर’ नीतियों को अपनाने से रोका।</li> </ul> <p><b>बिजली</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>टैरिफ नीति सुधार: उपभोक्ताओं को बोझ न करने की अक्षमता, क्रॉस सब्सिडी में प्रगतिशील कमी, खुली पहुंच का समयबद्ध अनुदान आदि।</li> <li>संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण</li> </ul> <p><b>सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>केवल रणनीतिक क्षेत्रों में PSUs</li> <li>गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण</li> </ul> <p><b>खनिज क्षेत्र</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन</li> <li>एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन शासन का परिचय।</li> </ul> <p><b>उद्योग</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (ऍस्प) योजना</li> </ul> <p><b>अंतरिक्ष</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को प्रदान किया जाने वाला स्तरीय खेल का मैदान</li> <li>तकनीक-उद्यमियों को दूरस्थ-संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भू-स्थानिक डेटा नीति</li> <li>तकनीक</li> </ul> <p><b>रक्षा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण</li> <li>ऑटोमैटिक रूट के तहत डिफेंस मैनुफैक्चरिंग में एफडीआई की सीमा 49: से बढ़ाकर 7 की जाएगी 4%</li> </ul>
--	--	--

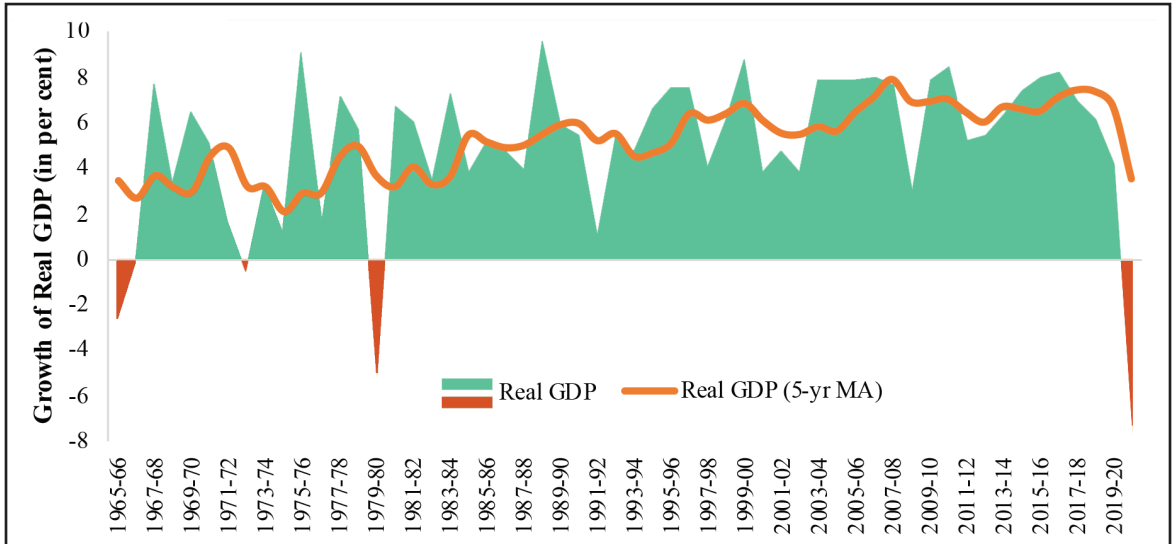
स्रोत: विभिन्न संसाधनों से संकलित और प्रमुख नीतिगत उपायों को शामिल किया गया।

## V आकार की अर्थिक पुनः प्राप्ति

1.50 भारत का GDP का Q1 में Q1 प्रतिशत: वित्त वर्ष 2020-21 और Q2 में 7.5 प्रतिशत: वित्त वर्ष 2020-21 तिमाही में कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव और महामारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए रोकथाम उपायों को दर्शाता है। संकुचन भारत के सबसे कड़े लॉकडाउन में से एक के प्रवर्तन के अनुरूप था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मापे गए सरकारी रिस्पांस स्ट्रिजेंसी इंडेक्स में परिलक्षित होता था। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने रहे क्योंकि धीरे-धीरे तालाबंदी का दौर जारी रहा, साथ ही आत्मानवीर भारत मिशन के आश्चर्यजनक समर्थन ने अर्थव्यवस्था को रिकवरी के रास्ते पर मजबूती से खड़ा कर दिया।

1.51 NSO ने 2019-20 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में वास्तविक GDP के 7.7 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है। यह पिछले चार दशकों में पहला वार्षिक संकुचन और स्वतंत्रता के बाद से सबसे कठिन (चित्र 39) को चिह्नित करता है। 1965-66 और 1971-72 में संकुचन युद्धों और सूखे के साथ हुआ, जबकि 1979-80 का वर्ष एक गंभीर सूखे और राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा था। इन सभी वर्षों में एक सामान्य कारक कृषि उत्पादन में गिरावट थी। वर्ष 2019-20, इसके विपरीत, प्रचुर मात्रा में मॉनसून के साथ कृषि क्षेत्र अग्रणी रहा है, जो अर्थव्यवस्था के चांदी के रूप में उभर रहा है। इस वर्ष में संकुचन 'एक बार एक सदी के संकट' के प्रभाव को इंगित करता है जो महामारी और संबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों द्वारा फैलाया गया है।

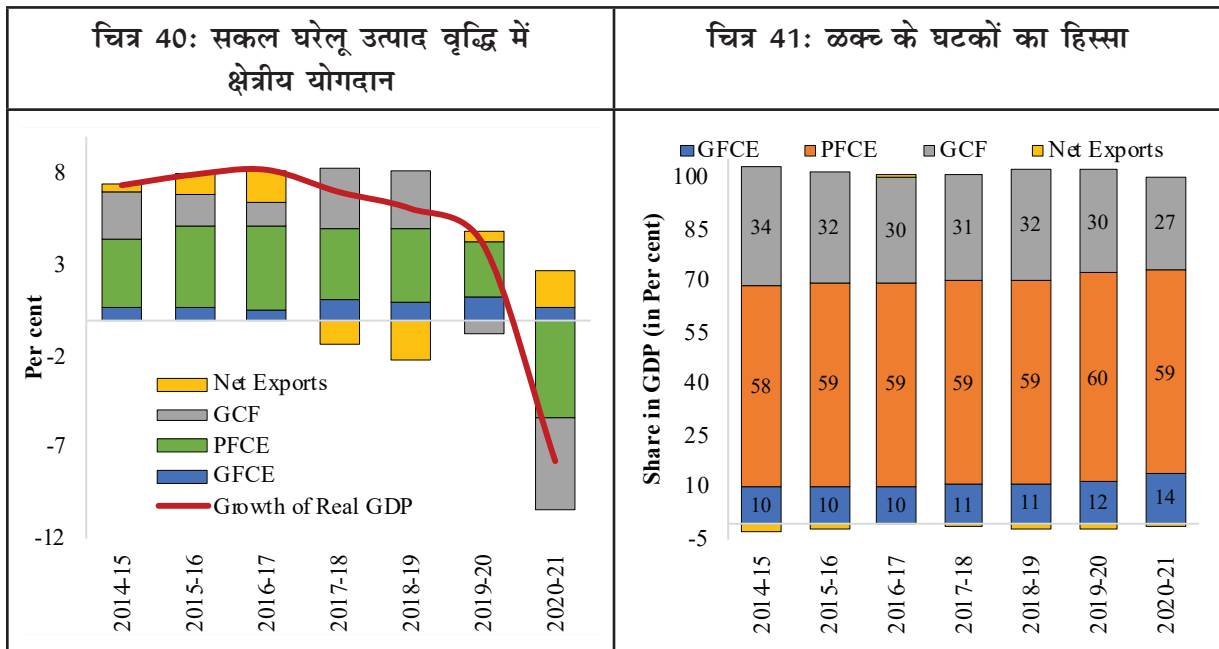
चित्र 39: भारत की वास्तविक GDP वृद्धि में रुझान



स्रोत: NSO

1.52 सरकारी उपभोग और शुद्ध निर्यात ने सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन को कम कर दिया है जबकि सकल पूंजी निर्माण (GCF) और निजी उपभोग ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन में योगदान दिया है (चित्र 40)। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बरकरार रखा है, जबकि 2019-20 (चित्र 41) में इसका हिस्सा 12.0 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 प्रतिशत हो गया है। निजी खपत का हिस्सा लगभग समान ही रहा है जो संपर्क-संवेदनशील क्षेत्रों में महामारी और संयमित व्यक्तिगत खपत के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। सकल निवेश ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन में सबसे अधिक योगदान दिया है, जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 26.7 प्रतिशत है, जो कि 2000 के दशक में सबसे कम

है। नेट एक्सपोर्ट्स ने 2020-21 में जीडीपी में गिरावट को मुख्य रूप से निर्यात के मुकाबले आयात में तेज संकुचन के कारण कुशन किया है।



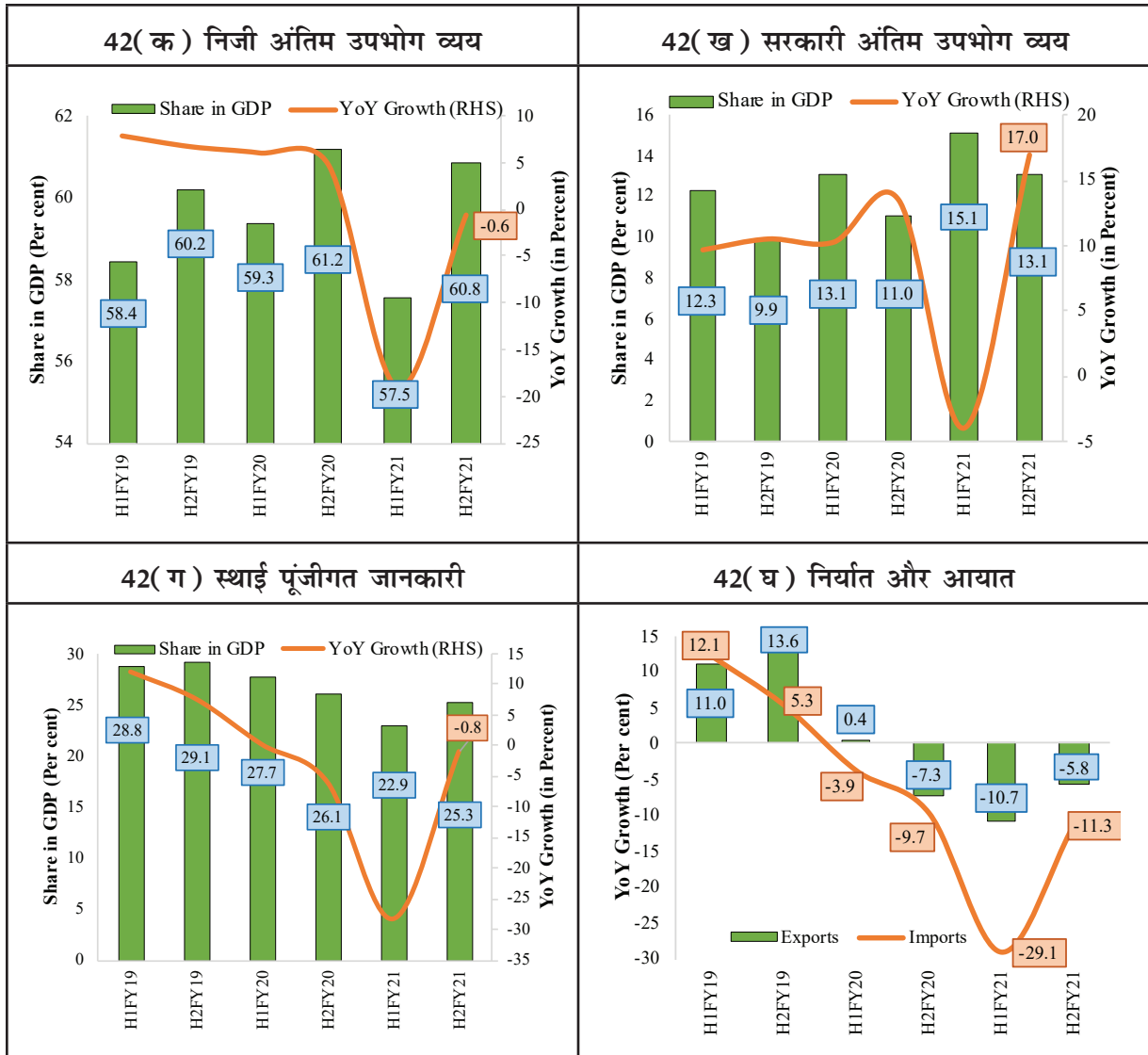
स्रोत: NSO

1.53 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम अनुमान: NSO द्वारा जारी किया गया है जिससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था को H 2: 2020-21 में एक लचीला V-आकार की वसूली के चरण की उम्मीद है। NSO द्वारा जारी तिमाही अनुमानों के अनुसार, अर्थव्यवस्था ने H1: वित्त वर्ष 2020-21 तक 15.7 प्रतिशत की गिरावट दिखाई है। पूरे वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की गिरावट: 2020-21 में वर्ष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट का संकेत मिलता है। यह H 2: वित्त वर्ष 2020-21 में H 1: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 23.9 प्रतिशत की वृद्धि का भी संकेत देता है। धीरे-धीरे प्रतिबंध, उच्च उत्सव और मांग और नीति समर्थन की क्रमिक उठाने के बीच व्यावसायिक गतिविधियों का तेजी से सामान्यीकरण दूसरी छमाही में तेजी से प्रत्याशित आर्थिक सुधार में अनुवाद होने की उम्मीद है। यह Q3: वित्त वर्ष 2020-21 में कई उच्च आवृत्ति संकेतकों में देखा गया एक मजबूत रिबाउंड द्वारा समर्थित है।

1.54 मांग पक्ष पर, वसूली दूसरी छमाही (चित्र 42) में व्यापक-आधारित होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी वृद्धि चालक सरकारी उपभोग की संभावना है जो दूसरी छमाही में मजबूत 17 प्रतिशत YoY के बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पहली छमाही में 3.9 प्रतिशत संकुचन के खिलाफ। निजी खपत भी 0.6 प्रतिशत के हल्के संकुचन के साथ काफी बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि पहली छमाही में 18.9 प्रतिशत के संकुचन के खिलाफ था। सकल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCE) द्वारा मापा गया निवेश एच 1 FY 21 में 29 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ दूसरी छमाही में 0.8 प्रतिशत के हल्के संकुचन के साथ काफी हद तक ठीक होने की उम्मीद है। शुद्ध निर्यात (निर्यात - आयात) 10.7 प्रतिशत के निर्यात में संकुचन की तुलना में 29.1 प्रतिशत के आयात में बड़े संकुचन के साथ वर्ष की पहली छमाही में सकारात्मक निकला। धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ, आयात और निर्यात दोनों में तेजी आई है और दूसरी छमाही में शुद्ध निर्यात फिर से नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद है। निर्यात में 5.8 प्रतिशत की गिरावट और वर्ष की दूसरी छमाही में 11.3 प्रतिशत आयात की उम्मीद है।

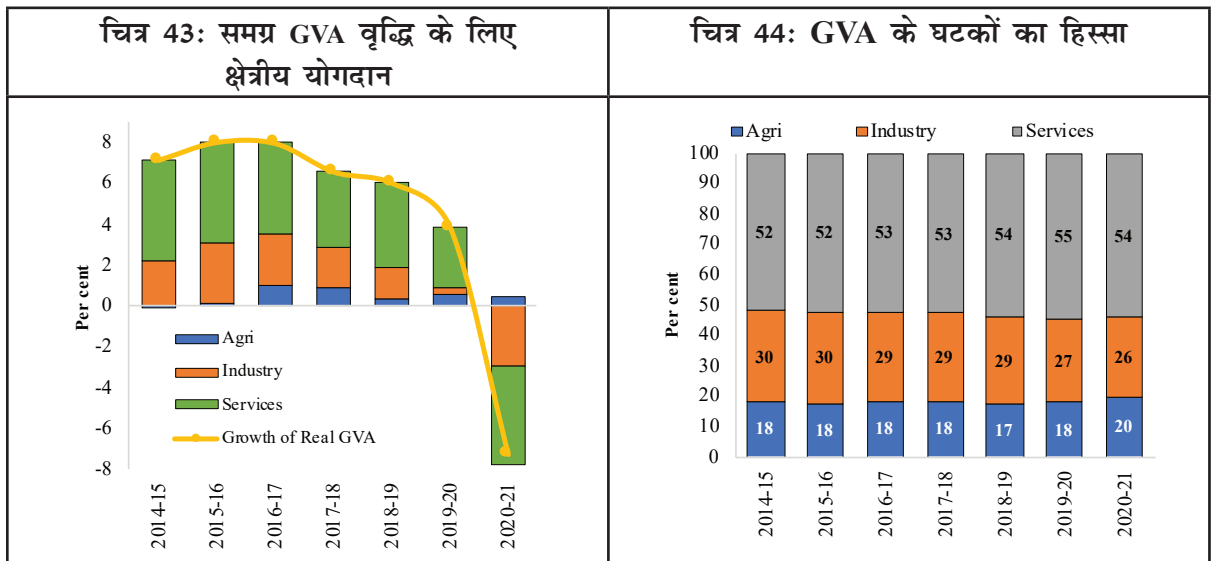


चित्र 42: GDP के घटकों की वृद्धि में अर्धवार्षिक रुझान



स्रोत: NSO

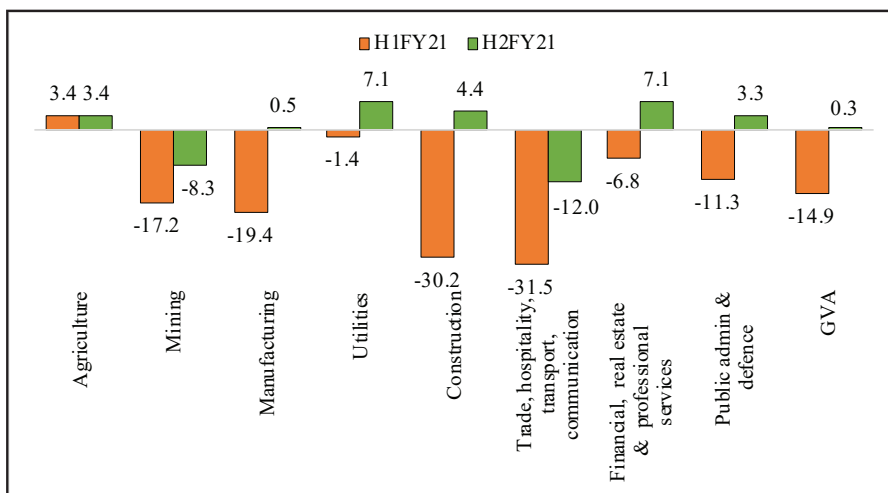
1.55 आपूर्ति पक्ष पर, सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि 2020-21 में -7.2 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 3.9 प्रतिशत थी। केवल कृषि ने सकारात्मक विकास में योगदान दिया जबकि सेवा और उद्योग ने सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन में योगदान दिया (चित्र 43)। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2020-21 में कोविड-19 महामारी के झटके को झेलने के लिए 3.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है-जिसके परिणामस्वरूप जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 19-21 प्रतिशत से 19.9 प्रतिशत बढ़कर 17.8 प्रतिशत हो गई है। 2019-20 (चित्र 44)। यह इंगित करता है कि रबी की कटाई और खरीफ बुवाई के लिए कृषि गतिविधियां कोविड-प्रेरित तालाबंदी से अप्रभावित थीं। वर्ष के दौरान उद्योग और सेवाओं का अनुबंध 9.6 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत अनुमानित है। उद्योग के भीतर, खनन का अनुमान 12.4 प्रतिशत, विनिर्माण का 9.4 प्रतिशत और निर्माण का 12.6 प्रतिशत है। यूलिटीज सेक्टर ने एक तेज रिकवरी दिखाई है और 2020-21 में 2.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। सेवा क्षेत्र के भीतर, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार 21.4 प्रतिशत तक अनुबंधित होने का अनुमान है।



स्रोत: NSO

1.56 दूसरी छमाही में अधिकांश क्षेत्रों के मूल्यवर्धन में सकारात्मक वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्साहजनक संकेत है (चित्र 45)। यह दूसरी छमाही में मामूली 0.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सूचित करता है, जबकि 2020-21 की पहली छमाही में 14.9 प्रतिशत संकुचन होता है। 2020-21 के दोनों हिस्सों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत पर स्थिर है। उद्योग क्षेत्र ने दूसरी छमाही में 1.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के साथ एक मजबूत रिकवरी का मंचन किया है, जबकि पहली छमाही में 20.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ विनिर्माण क्षेत्र में तेज उछाल के साथ दूसरी छमाही में 0.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 19.4 के संकुचन के खिलाफ है। पहली छमाही में बिजली और निर्माण क्षेत्रों का भी अनुमान है कि दूसरी छमाही में क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वी-आकार की वसूली दर्ज की जाएगी। महामारी का सबसे बड़ा खामियाजा संपर्क-संवेदनशील सेवा क्षेत्र ने उठाया है, जो पहली छमाही में 15.5 प्रतिशत की दर से अनुबंधित है और दूसरी छमाही में 1.1 प्रतिशत तक अनुबंध का अनुमान है। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, कुल सेवाओं में से एक तिहाई का गठन, पहली छमाही में 31.5 प्रतिशत द्वारा अनुबंधित और दूसरी छमाही में 12.0 प्रतिशत तक अनुबंध का अनुमान है।

**चित्र 45: G2 को गठन करने वाले अधिकांश क्षेत्रों में H2: FY 2020-21 में वी-आकार की रिकवरी**



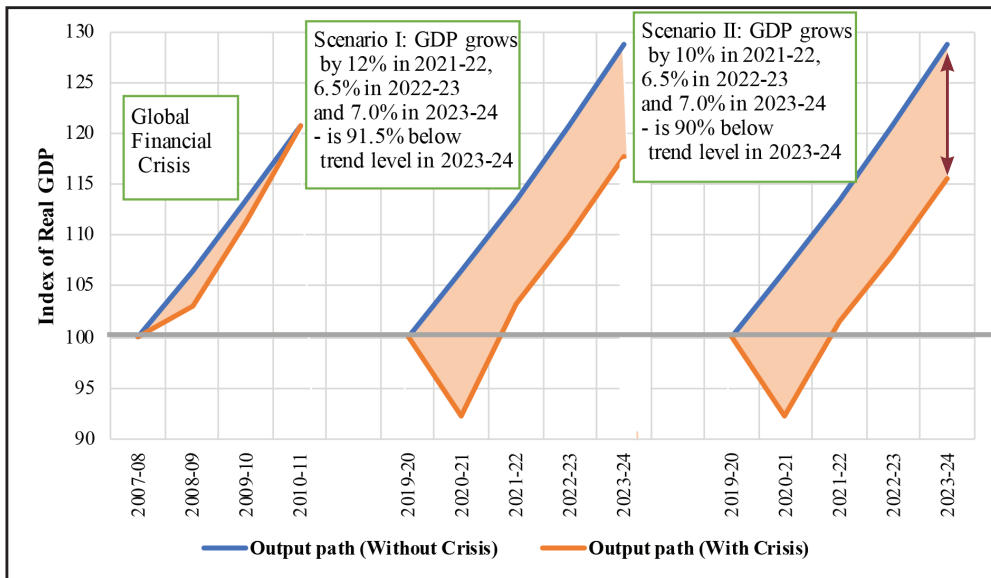
स्रोत: NSO

1.57 यह उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था पर, जैसा कि अपेक्षित था, 2020-21 की पहली तिमाही में महामारी के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्रमिक अनलॉकिंग और मैक्रो-आर्थिक नीतियों के सक्षम समर्थन के साथ, अर्थव्यवस्था ने पूर्व-महामारी के स्तर पर लगातार पलटाव किया है और उच्च-आवृत्ति वाले संकेतकों पर डेटा पिछले वर्ष के गतिविधि स्तरों के साथ बढ़ते अभिसरण का सुझाव देता है। वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था के तेज संकुचन को वर्ष की दूसरी छमाही में व्यापक आधारित पुनरुत्थान वृद्धि द्वारा कवर किए जाने की उम्मीद है।

1.58 लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को संबोधित करने के लिए कई उपभोक्ताओं और उत्पादकों द्वारा आर्थिक गतिविधि में सहज कटौती के साथ, वैश्विक आर्थिक गतिविधि के प्रतिकूल झटके का एक अभूतपूर्व संयोजन का गठन किया है। इसके अल्पकालिक प्रभाव के अलावा, महामारी से उत्पन्न होने वाली गहरी मंदी के कारण “सुपर-हिस्टैरिसिस” के लिए जोखिम होता है—न केवल उत्पादन स्तर का एक स्थायी नुकसान बल्कि संभावित उत्पादन में वृद्धि में एक स्थायी मंदी का जोखिम। इसके अल्पकालिक प्रभाव से परे, महामारी से उत्पन्न गहरी मंदी से हिस्टैरिसिस होने का खतरा होता है। जबकि कई सेमिनल सुधार हिस्टैरिसिस की संभावना को कम करने में मदद करेंगे, वसूली को हिस्टैरिसिस से बचने के रूप में माना जाएगा जब अर्थव्यवस्था पूर्व-कोविड आउटपुट पथ को वापस ले लेती है और संभावित विकास के अपने प्रक्षेपवक्र (कोविड नहीं रहेगा ऐसा मानकर) पर वापस आ जाती है।

1.59 वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत सहित, महामारी से प्रेरित संकट से समय में पीछे सेट की गई है। 2020-21 से पहले के पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी। वर्ष 2021-22 में, कम आधार प्रभाव और अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर 10-12 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की तीव्र वसूली की उम्मीद है। यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था 2022-23 में अपनी विकास दर 6.5 प्रतिशत और 2023-24 में 7.0 प्रतिशत संरचनात्मक सुधारों से सहायता प्राप्त करती है। यदि 12 प्रतिशत वृद्धि के दो परिदृश्य और 2021-22 में 10 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई है, तो भारत 2023-24 (चित्र 46) द्वारा क्रमशः उत्पादन स्तर की प्रवृत्ति के स्तर से 91.5 प्रतिशत और 90 प्रतिशत नीचे होगा।

चित्र 46: क्या भारत की जीडीपी अपने ट्रेंड ग्रोथ में लौट सकती है



स्रोत: NSO से डेटा का उपयोग करके सर्वेक्षण की गणना

नोट: 200:-0 2007 और 2019-20 में रियल जीडीपी को 100 तक अनुक्रमित किया गया है

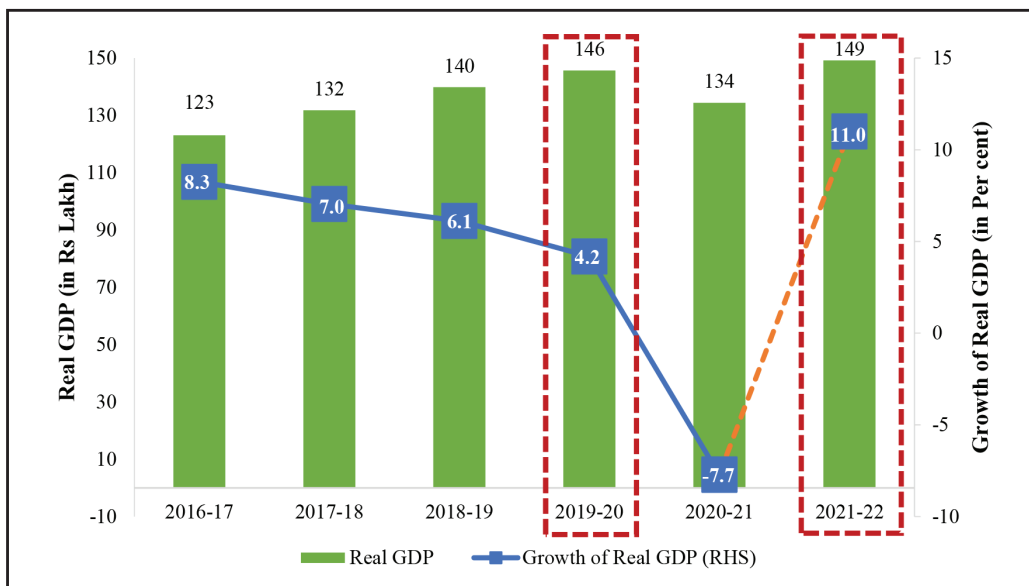
2020-21 से आगे विकास की प्रवृत्ति की दर 6.5 प्रतिशत मानी गई है

1.60 सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी के इस संभावित प्रभाव को मान्यता दी और इसलिए, एक व्यापक सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। आत्म निर्भर भारत मिशन के तहत संरचनात्मक सुधारों और नीतिगत धक्का का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को मजबूत करना है—जो अर्थव्यवस्था को महामारी के झटके से उबारने के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत विकास पथ पर ले जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसकी संभावित वृद्धि तक पहुँचने के लिए निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। नीतिगत जोर सार्वजनिक निवेश के विस्तार पर भी है जो निजी निवेश में भीड़ लाएगा। क्षेत्रों के विचलन और उदारीकरण के प्रयासों का उद्देश्य उद्यमशीलता की ऊर्जा को अनलॉक करने और निजी निवेशकों की जोखिम की भूख को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक वातावरण में सुधार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी के विघटनकारी प्रभाव को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को सरकार की भागीदारी करने की आवश्यकता है।

### आउटलुक

1.61 2020-21 में अनुमानित 7.7 प्रतिशत महामारी-चालित संकुचन के बाद, भारत की वास्तविक जीडीपी 2021-22 में 11.0 प्रतिशत और मामूली जीडीपी 15.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। ये रूढ़िवादी अनुमान विलोम संभाव्यता को प्रदर्शित करता है जो आर्थिक गतिविधियों में निरंतर विमुद्रीकरण के कारण प्रकट हो सकते हैं क्योंकि कोविड-19 टीकों के रोलआउट से कर्षण इकट्ठा होता है। इससे सुधारों और आपूर्ति नियमों में शिथिलता, ढांचागत निवेशों को बढ़ावा देने, उत्पादकता से जुड़ी विनिर्माण योजनाओं को बढ़ावा देने, सेवा क्षेत्र के लिए पेंट-अप मांग में सुधार, रोल के बाद विवेकाधीन उपभोग में वृद्धि के कारण आपूर्ति पक्ष द्वारा समर्थन किया जाएगा। वैकसीन और क्रेडिट में लेने से पर्याप्त तरलता और कम ब्याज दर मिलती है। यह रास्ता 2019-20 के पूर्ण स्तर पर 2.4 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज करेगा—जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को पूर्व-महामारी स्तर (चित्र 47) तक पहुँचने और जाने में दो साल लगेंगे। ये अनुमान भारत के लिए 2021-22 में 11.5% वास्तविक जीडीपी वृद्धि और 2022-23 में 6.8% आईएमएफ के अनुमान के अनुरूप हैं। भारत को आईएमएफ के अनुसार अगले दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की उम्मीद है।

चित्र 47: 2021-21 के लिए वास्तविक GDP के अनुमान



स्रोत: NSO और सर्वेक्षण गणना

1.62 नया साल लंबे समय से प्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी और विभिन्न देशों में टीकाकरण ड्राइव की शुरुआत के साथ शुरू हुआ है। आपातकालीन उपयोग के लिए स्वदेश निर्मित दो टीकों की मंजूरी के साथ, भारत ने 16 जनवरी, 2020 को मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक डिजिटल प्रणाली (विन-को) टीके स्टॉक की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है—प्लेटफॉर्म, भंडारण तापमान और वास्तविक समय के आधार पर वैक्सीन के लाभार्थियों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग।

1.63 भारत छह दिनों के भीतर 10 लाख वैक्सीन रोल-आउट करने वाला सबसे तेज देश बन गया। भारत 22 जनवरी, 2021 को ब्राजील और मोरक्को को निर्यात शुरू करने के साथ विभिन्न देशों के लिए वैक्सीन के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। वैक्सीन के तेजी से रोल आउट से स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर आशावाद को बल मिलता है - आशाएं सेवा क्षेत्र, निजी उपभोग और निवेश में एक मजबूत रिकवरी।

## अध्याय एक नजर में

<p>➤ वर्ष 2020 को वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से भारत और दुनिया के लिए सबसे विकट आर्थिक चुनौती पेश करते हुए कोविड-19 महामारी की भविष्यवाणी की गई थी।</p>
<p>➤ वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 2020 में 4.4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, एक सदी में सबसे तेज संकुचन। इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमी की तुलना में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को जीवन और आर्थिक उत्पादन के मामले में कठिन रूप से प्रभावित किया गया।</p>
<p>➤ एक इलाज या वैक्सीन के बिना, इस सभी व्यापक संकट से निपटने ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को महत्वपूर्ण बना दिया, जबकि नीति नियंत्रकों को “जीवन बनाम आजीविका” की एक दुविधा का सामना करना पड़ा, यानी, बीमारी की चपेट में आने से मंदी की अवस्था का सामना करना पड़ सकता है।</p>
<p>➤ दुनिया भर में, सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने प्रमुख नीतिगत दरों को कम करने, मात्रात्मक सहजता के उपायों, ऋण की गारंटी और राजकोषीय उत्तेजना जैसे कई नीतिगत टूल तैनात किए। हालांकि, बड़े राजकोषीय उत्तेजनाओं के फ्लिप पक्ष में ऋण स्थिरता के मुद्दे और वित्तीय तनाव का जोखिम है।</p>
<p>➤ भारत लगातार अनलॉक करने के बावजूद दूसरी लहर से बचने में कामयाब रहा। यह महामारी विज्ञान वक्र को समतल करने में कामयाब रहा है, सितंबर के मध्य में केस लोड चरम पर है और इसके बाद दैनिक मामलों और भाग्य में लगातार गिरावट आ रही है।</p>
<p>➤ कोविड-19 ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर आपातकालीन ब्रेक लगाया जो वर्ष 2020 की शुरुआत में बढ़ रही थी। वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में वृद्धि (-) 7.7%, H1 में 15.7% की गिरावट और मामूली गिरावट से बनी है। -) दूसरी छमाही में 0.1% की गिरावट।</p>
<p>➤ कृषि क्षेत्र में चांदी की परत बनी हुई है, जबकि संपर्क-आधारित सेवाएं, विनिर्माण, निर्माण सबसे कठिन थे। जुलाई से शुरू, एक लचीली वी-आकार की वसूली अच्छी तरह से चल रही है, जैसा कि उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे बिजली की मांग, ई-वे बिल, GST संकलन, स्टील की खपत, आदि में निरंतर पुनरुत्थान द्वारा दर्शाया गया है।</p>
<p>➤ मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रेरित है, आपूर्ति की गड़बड़ी को देखते हुए, वर्ष के अधिकांश के लिए 6 प्रतिशत से ऊपर रहा।</p>

<p>➤ कमजोर मांग के कारण निर्यात की तुलना में आयात में तेज संकुचन हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार आयात के 18 महीने के लिए बढ़ गया।</p>
<p>➤ वाणिज्यिक पत्र जारी करने में तीव्र वृद्धि, पैदावार में आसानी, और MSMEs के लिए मजबूत ऋण वृद्धि, उद्यमों के जीवित रहने और बढ़ने के लिए एक संशोधित क्रेडिट प्रवाह तंत्र को दर्शाती है।</p>
<p>➤ भारत की चार-स्तंभ की रणनीति के हिस्से के रूप में, कैलिब्रेटेड राजकोषीय और मौद्रिक सहायता को विकसित आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ था, लॉकडाउन में कमजोर को कुशनिंग और अनलॉक करते समय खपत और निवेश को बढ़ावा देता है। कृषि, खनन, श्रम आदि में लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधार अर्थव्यवस्था के लिए संभावित विकास पथ पर लौटने के लिए समवर्ती रूप से किए गए थे, जो सुपर-हिस्टैरिसिस को वाड़ी में रखते हैं। वित्त वर्ष 2022 के लिए 11 प्रतिशत पर अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि आजादी के बाद सबसे अधिक है।</p>
<p>➤ एक सामान्य टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ अर्थव्यवस्था की घर वापसी सामान्य होने के साथ, सेवा क्षेत्र, उपभोग और निवेश में एक मजबूत सुधार की उम्मीद फिर से जागृत हुई है। मध्यम से लंबे समय तक चलने वाले लेंस से, सुधार के एजेंडे को बनाए रखने का कार्य समय की आवश्यकता है।</p>

## REFERENCES

- Gourinchas, P-O (2020), “*Flattening the Pandemic and Recession Curves*”, VoxEU.org, 3 June.
- Hansen, Lars Peter. and Thomas J. Sargent. 2001. “Robust control and model uncertainty”. *American Economic Review* 91(2), 60–66.
- International Monetary Fund. “*World Economic Outlook*” Various issues
- Schueller Emily, Eili Klein, Katie Tseng, Geetanjali Kapoor, Jyoti Joshi, Aditi Sriram, Arindam Nandi, Ramanan Laxminarayan. “*COVID-19 for India Updates*” March 24,2020. <https://cddep.org/wpcontent/uploads/2020/03/covid19.indiasim.March23-2-eK.pdf>
- World Bank. “*Global Economic Prospects*” June 2020
- World Bank. “*Global Economic Prospects*” July 2021
- Xavier Estupinan & Mohit Sharma & Sargam Gupta & Bharti Birla, 2020. “*Impact of COVID-19 Pandemic on Labour Supply and Gross Value Added in India*” Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai Working Papers 2020-022.



Table 0.1 : Key Indicators					
Data categories	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
<b>GDP and Related Indicators</b>					
GDP at current market prices	₹ lakh Crore	171.0	189.7	203.4 <sup>a</sup>	194.8 <sup>b</sup>
GDP at constant market prices	₹ lakh Crore	131.8	139.8	145.7 <sup>a</sup>	134.4 <sup>b</sup>
Growth Rate	(per cent)	7.0	6.1	4.2 <sup>a</sup>	-7.7 <sup>b</sup>
GVA at current basic prices	₹ lakh Crore	155.1	171.4	183.4 <sup>a</sup>	175.8 <sup>b</sup>
GVA at constant basic prices	₹ lakh Crore	120.7	128.0	133.0 <sup>a</sup>	123.4 <sup>b</sup>
Growth Rate	(per cent)	6.6	6.0	3.9 <sup>a</sup>	-7.2 <sup>b</sup>
Gross Savings	% of GDP	32.4	30.1	na	na
Gross Capital Formation	% of GDP	34.2	32.2	na	na
Per Capita Net National Income (at current prices)	₹	1,15,293	1,26,521	1,34,226 <sup>a</sup>	1,26,968 <sup>b</sup>
<b>Production</b>					
Food grains	Million tonnes	285.0	285.2	296.7 <sup>c</sup>	144.5 <sup>c</sup>
Index of Industrial Production (growth)	(per cent)	4.4	3.8	-0.8	-15.5 <sup>d</sup>
Electricity Generation (growth)	(percent)	5.4	5.2	1.0	-4.6 <sup>d</sup>
<b>Prices</b>					
WPI inflation (average)	(per cent)	3.0	4.3	1.7	-0.1 <sup>e</sup>
CPI (Combined) inflation (average)	(per cent)	3.6	3.4	4.8	6.6 <sup>e</sup>
<b>External Sector</b>					
Merchandise export growth (in US\$ term)	(per cent)	10.0	8.8	-5.1	-15.7 <sup>e</sup>
Merchandise import growth (in US\$ term)	(per cent)	21.1	10.4	-7.7	-29.1 <sup>e</sup>
Current Account Balance	% of GDP	-1.8	-2.1	-0.9	3.1 <sup>f</sup>
Foreign Exchange Reserves (end of year)	US\$ Billion	424.4	411.9	475.6	586.1 <sup>k</sup>
Average Exchange Rate	₹ /US\$	64.45	69.92	70.90	74.64 <sup>j</sup>
<b>Money and Credit</b>					
Broad Money (M3) growth (annual)	(per cent)	7.8	10.2	10.1	12.4 <sup>g</sup>
Scheduled Commercial Bank Credit (growth)	(per cent)	10	13.3	6.1	6.1 <sup>g</sup>
<b>Fiscal Indicators (Centre)</b>					
Gross Fiscal Deficit	% of GDP	3.5	3.4	4.6 <sup>h</sup>	3.5 <sup>i</sup>
Revenue Deficit	% of GDP	2.6	2.4	3.3 <sup>h</sup>	2.7 <sup>i</sup>
Primary Deficit	% of GDP	0.4	0.4	1.6 <sup>h</sup>	0.4 <sup>i</sup>
Notes: na: not available					
a: Provisional estimates, b: First advance estimate, c: Fourth AE for 2019-20 and first AE for 2020-21, d: (April-November) 2020, e: (April-December) 2020, f: (April-September) 2020, g: as on December 18, 2020, h: Provisional Actuals, i: Budget Estimates, j: End of December 2020, k: As on 8 <sup>th</sup> January 2021.					